रजिस्ट्री सं० डी० (डी०) 73

REGISTERED NO. D.(D.73)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 1979/ज्येष्ठ 19, 1901

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 1979/JYAISTHA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1979

का० आ० 1828—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 284-सूर्यपेट (अ० जा०) सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती नागामाला नरसम्मा तेलंगाना प्रदेश एरूकाला संघाम, सूर्यपेट, जिला नलगोंडा (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती नागामाला नरसम्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ०प्र०वि०-स०/284/78(31)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 12th April, 1979

S.O. 1828.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Nagamalla Narsamma, Telangana Pradesh Erukala Sangham, Suryapet, District Nalgonda (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 284-Suryapet (SC) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Nagamalla Narsamma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/284/78(31)]

आदेश

का० आ० 1829—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण

निर्वाचन के लिए 284-सूर्यपेट (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इडला गोपइआह, हरीजनवाडा सूर्यपेट जिला नालगोंडा (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री इडला गोपइआह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ० प्र० वि०स० /284/78(30)]

ORDER

S.O. 1829.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Edla Gopaiah, Harijanwada, Suryapet, District Nalgonda (A.P.), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 284-Suryapet (SC) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Edla Gopaiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/284/78(30)]

आदेश

का० आ० 1830.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 244-असिफाबाद (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मटुरी दुर्गाहआह, म० सं० 3-83, असीफाबाद, जिला अदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मटुरी दुर्गाहआह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ०प्र० वि०स०/244/78(29)]

ORDER

S.O. 1830.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Maturi Durgaiah, H. No. 3-83, Asifabad, District Adilabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 244-Asifabad (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Maturi Durgaiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/244/78(29)]

आदेश

नई दिल्ली 23 अप्रैल 1979

का० आ० 1831—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 79-कान्कीपाडु निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कोट्टा वेंकटेश्वरराव कान्कीपाडु, केल्लीपरावारी स्ट्रीट, विजयवाडा तालुक (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कोट्टा वेंकटेश्वरराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं०आ० प्र० वि० स०/79/78(32)]

ORDER

New Delhi, the 23rd April 1979

S.O. 1831.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kotta Venkateswararao, Kankipadu, Kolliparavari Street, Vijayawada Taluk (Andhra Pradesh), a contesting candidate for General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 79-Kankipadu constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kotta Venkateswararao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative

Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/79/78(32)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल 1979

का० आ० 1832.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 249-गया मुफस्सिल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरुण प्रसाद यादव, ग्राम रामपुर, वार्ड नं० 26, पोस्ट-गया, जिला गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अरुण प्रसाद यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/249/77(24)]

ORDER

New Delhi, the 25th April, 1979

S.O. 1832.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Arun Prasad Yadav, Village Rampur, Ward No. 26, Post Gaya, Distt. Gaya Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 249-Gaya Muffasil constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Arun Prasad Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/249/77(24)]

आदेश

का० आ० 1833.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 249-गया मुफस्सिल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विनोद सिंह, ग्राम लोदीपुर, पोस्ट-बुद्धगेरे, जिला-गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विनोद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं बिहार-वि० स० /249/77/(25)]

ORDER

S.O. 1833.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Binod Singh, Village Lodipur, P. Budhgere, Distt. Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 249-Gaya Muffasil constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Binod Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/249/77(25)]

आदेश

का० आ० 1834.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 249-गया मुफस्सिल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, ग्राम एवं पोस्ट बीथो थाना-चन्दौती, जिला गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त सिद्धेश्वर प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं बिहार-वि० स० /249/77/(26)]

ORDER

S.O. 1834.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Siddheshwar Prasad, Vil. and P. O. Bitho, Thana Chandauti, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general electon to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 249-Gaya Muffasil constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Siddheshwar Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/249/77(26)]

आदेश

का० आ० 1835 :—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 249 गया मुफस्सिल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द नाथ वर्मा ग्राम उपर हुली टोला खगड़ी बिगहा, पोस्ट-परैया जिला गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द नाथ वर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/249/77/(27)]

ORDER

S.O. 1835.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chand Nath Varma, Vill. Uprahuli, Tola Khagri-bigha, Post Paraiya District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 249-Gaya Muffasil constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chand Nath Varma to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/249/79(27)]

आदेश

का० आ० 1836.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 307 हटिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूर्यमणि सिंह, ग्राम पहर गेडुआ, पोस्ट कथवन जिला पलामू, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सूर्य मणि सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं बिहार-वि० स० /307/77(32)]

ORDER

S.O. 1836.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suryamani Singh, Village Pahar Gadua, P. O. Kadhawan, District Palamau, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 307-Hatia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Suryamani Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/307/77(23)]

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल 1979

का० आ० 1837 :—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 158 देवघर (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भैरो मिरधा, ग्राम ठढ़ियारा, पोस्ट-भोरने, जिला संथाल परगना, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भैरो मिरधा को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं बिहार-वि० स० /158/77/(28)]

ORDER

New Delhi, the 26th April, 1979

S.O. 1837.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhaira Mirdha, Village Thariyara, P.O. Bhorne, District Santhal Parganas, Bihar a contesting candidate for general election Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 158-Deoghar (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the

Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhairo Merdha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/158/77(28)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979

का० आ० 1838 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 301 तमड़ (अ०ज०ज०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बनमाली सिंह मुण्डा, ग्राम नौडी, डाकघर सिन्दरी, जिला रांची बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बनमाली सिंह मुण्डा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं बिहार-वि० स०/301/77/(29)]

ORDER

New Delhi, the 27th April, 1979

S.O. 1838.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Banmali Singh Munda, Village Nouri, P. O. Sindri, District Ranchi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 301-Tamar(ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Banmali Singh Munda to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/301/77(29)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979

का० आ० 1839.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 150-लिटिपाड़ा (अ० ज० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती लीलावती मुरमू, ग्राम व पोस्ट पाडरकोला, जिला संथाल परगना, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती लीलावती मुरमू संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/150/77/(30)]

ORDER

New Delhi, the 28th April, 1979

S.O. 1839.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Leelawati Murmu, Vill. & P. O. Paderkola, District Santhal Parganas, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1979 from 150-Litipara (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Leelawati Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/150/77(30)]

आदेश

का० आ० 1840.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 148-बोरियो (अ०ज०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपीनाथ सोरेन, ग्राम पंडारा, पोस्ट भगैया, जिला संथाल, परगना (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोपीनाथ सोरेन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/148/77(31)]

ORDER

S.O. 1840.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopi Nath Soren, Village Pindara, P. O. Bhagalya, District Santhal Parganas, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in

June, 1977 from 148-Borio (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopi Nath Soren to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/148/77(31)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1979

का० आ० 1841.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 128-नरपतगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उदय नारायण विराजी, ग्राम-पोस्ट अचरा भाया नवाबगंज, जिला पूर्णिया बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उदय नारायण विराजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/128/77(32)]

ORDER

New Delhi the 2, May, 1979.

S.O. 1841.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Udai Narain Viraji, Vill. Post Achra Via Nawabganj, District Purnea, Bihar, a conntesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 128-Narpatganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Udai Narain Viraji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/128/77(32)]

आदेश

का० आ० 1842.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन लिए 128-नरपतगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवेन्द्र नाथ झा, ग्राम परमानन्दपुर पोस्ट गिधवास, जिला पूर्णिया बिहार, अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवेन्द्र नाथ झा को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/128/77(33)]

(वी० नागसुब्रमण्यन) सचिव,

ORDER

S.O. 1842.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Devendra Nath Jha, Village Parmanadpur, P. O. Gidhwas, District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 128-Narpatganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Devendra Nath Jha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/128/77 (33)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1979

का० आ० 1343.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है क जून, 1977 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-फिलौर (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कुलदीप सिंह, ग्राम रामगढ़ डा० फिलौर, जिला जालन्धर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कुलदीप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि० सं०/39/77(1)]

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 1843.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kuldip Singh, Village Ramgarh, P.O. Phillaur, District Jullundur (Punjab) a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in June, 1977 from 39-Phillaur (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

AND WHEREAS, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kuldip Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House or Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/39/77]

R. D. SHARMA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1979

का०आ० 1844.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6-महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्र शेखर मिश्र, ग्राम मानिकपुरा, डाकखाना—मानिकपुरा, जिला—सारण (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्र शेखर मिश्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-लो०स०/6/77(2)]

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 1844.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Shekhar Mishra, Village Manikpura, P. O. Manikpura, District Saran (Bihar) a contesting candidate for general election to the House of the People held in Bihar in March, 1977 from 6-Maharajganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Shekhar Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/6/77(2)]

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का० आ० 1845.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 136-अमौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मजीबुर रहमान , ग्राम खगजना, पोस्ट घुसमल, जिला पूर्णिया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मजीबुर रहमान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं बिहार-वि०स०/136/77/(35)]

ORDER

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1845.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Majibur Rahman, Village Khagjana, P.O. Ghusmal, District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 136-Amour constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Majibur Rahman to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/136/77 (35)]

आदेश

का० आ० 1846.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये 136-अमौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनूपलाल विश्वास, ग्राम एवं पोस्ट सरोना, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनूपलाल विश्वास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं बिहार-वि० स०/136/77(34)]

ORDER

S.O. 1846.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anup Lal Vishwas, Village and P. O. Tarauna, Distritc Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legisaltive Assembly held in June 1977 from 136-Amour constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made threunder :

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anup Lal Vishwas to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HA/136|77(34)]

By order

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई 1979

का० आ० 1847.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 16-मधुबन निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री फौजदार राय, ग्राम-फाजिलपुर, पोस्ट-तैतरिया, जिला-पूर्व चम्पारण, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री फौजदार राय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/16/77 (40)]

ORDER

New Delhi the 8th May, 1979

S.O. 1847.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Fauzdar Rai, Village Fazilpur, P. O. Tataria District East Champaran, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 16-Madhhuban constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Represntation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Fauzdar Rai to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,

[No. BR-LA/16/77(40)]

आदेश

का० आ० 1848.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 72- पुपरी निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उमर नइयर फातमी, स्टेट बैंक के सामने गली में, महेन्द्रू, पटना-6 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक, सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमर नइयर फातमी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/72/77(41)]

ORDER

S.O. 1848.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Naiyar Fatmi, In front of the State Bank Street Mahendru, Patna-6 a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 72-Pupsi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as requiired by the Represntation of People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Comission hereby declares the said Shri Amar Naiyar Fatmi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/72/77(41)]

आदेश

का० आ० 1849.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 72- पुपरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जागृत प्रसाद यादव, ग्राम व पोस्ट गौंडा, जिला-सीतामढ़ी (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जामुन प्रसाद यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार- वि० स०/72/77(42)]

ORDER

S.O.1849.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jamun Prasad Yadav, Vill. Post Gaura, Thana Nanpur, Distt. Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 72-Pupri constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Electionn Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, threfore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jamun Prasad Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/72/77(42)]

आदेश

का० आ० 1850—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69- मेजरगंज (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामाश्रय हजरा, ग्राम एवं पोस्ट दुसाध टोली वैरगनिया, जिला सीतामढ़ी, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामाश्रय हजरा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार- वि० स०/69/77/37]

ORDER

S.O. 1850.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramasbray Hazra, Village and Post Dusadh Toli, Vairgania, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 69--Majarganj (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramashray Hazra to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/69/77(37)]

आदेश

का० आ० 1851—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69- मेजरगंज (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रूदल पासवान, ग्राम एवं पोस्ट मकुरहर, जिला- सीतामढ़ी, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रूदल पासवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य के चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार- वि० स०/69/77(38)]

ORDER

S.O. 1851.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rudal Paswan, Vill and Post Bhakurhar, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 69-Majarganj (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rudal Paswan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/69/77(38)]

आदेश

का० आ० 1852.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69- मेजरगंज (अ०जा.) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव पासवान, ग्राम एवं पोस्ट- बड़हुखा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव पासवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि० स०/69/77 (39)]

ORDER

S.O. 1852.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Paswan, Vill. and Post Badharwa, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legisative Assembly held in June, 1977 from 69-Majarganj (SC) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Paswan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/69/77(39)]

आदेश

का० आ० 1853.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 64- रूनी सैदपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रत्नेश्वर ठाकुर, ग्राम व पोस्ट थुम्मा भाया रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रत्नेश्वर ठाकूर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स० /64/77(36)]

ORDER

S.O. 1853.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Ratneshwar Thakur, Village Post, Thumma Via Runni Saidpur, Distt. Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 64--Runi Saidpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the Pepole Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of sectionn 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ratneshwar Thakur to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/64/77(36)]

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1979

का० आ० 1854.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 14—झंझारपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जय प्रकाश नाथ मिश्र, ग्राम एवं डाकखाना—कैथाही, भाया राजनगर, जिला मधुबनी (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जयप्रकाश नाथ मिश्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार—लो०स०/14/77(3)]

ORDER

New Delhi, the9th May, 1979

S.O. 1854.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jaiprakash Nath Mishra, Village and P. O. Kaithahi, Via Rainagar, District Madhubani (Bihar) a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 14-Jhanjharpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jaiprakash Nath Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/14/77(3)]

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई 1979

का०आ० 1855.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 225 काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेश सिंह, ग्राम व पोस्ट- पवनी, जिला रोहतास, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री नरेश सिंह को असंसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/225/77(43)]

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1979

S.O. 1855.—Whereas the Election Commission is satisfied that Naresh Singh , Village Post Pawni, District Rohtas, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 225-Karakat constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Naresh Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/225/77(43)]

New Delhi, the 17th May, 1979

का०आ० 1856—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 265 सिमरिया (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव जगत राम, ग्राम बानासाड़ी, पोस्ट- सिमरिया, जिला हजारीबाग (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव जगत राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/265/77(44)]

ORDER

New Delhi, the 17th May, 1979

S.O. 1856.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Shiv Jagat Ram. Village Banasaudi, P. O. Simaria, District Hazaribagh, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 265-Simaria (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Jagat Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/265/77(44)]

आदेश

का० आ० 1857.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 72-भरतपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विष्णु बाबा, बीनारायन गेट, वार्ड सं० 6, मकान सं० 26, भरतपुर, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विष्णु बाबा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०वि०स०/72/77(11)]

ORDER

S.O. 1857.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vishnu Baba, Beenarain Gate, Ward No. 6, House No. 26, Bharatpur, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 72-Bharatpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vishnu Baba to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/72/77(11)]

आदेश

का० आ० 1858.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 8-हाजीपुर (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनुदास, ग्राम, शहबुल्लापुर, पोस्ट हाजीपुर, जिला वैशाली (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनुदास को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-लो०स०/8/77(4)]

ORDER

S. O. 1858.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Annu Das, Village Sahdullahpur, P. O. Hazipur, District Vaishali (Bihar) a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 8-Hazipur (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Annu Das to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/8/77(4)]

आदेश

का० आ० 1859.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 9-वैशाली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपाल पासवान ग्राम सिमरा, डाकखाना रामपुर मोना, जिला—मुजफ्फरपुर (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोपाल पासवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-लो०स०/9/77(5)]

ORDER

S.O. 1859.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopal Paswan, Village Siswa, P. O. Rampur Muni, District Muzaffarpur (Bihar) a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 9-Vaishali constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopal Paswan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[BR-HP/9/77(5)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1979

का०आ० 1860.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20-सहरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वैद्यनाथ कामत ग्राम तथा डाकखाना—बनगांव, जिला—सहरसा (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वैद्यनाथ कामत को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-लो०स०/20/77(6)]

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1979

S.O. 1860.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baidyanath Kamat, Village and P.O. Bangaon, District Saharsa (Bihar) a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 20-Saharsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baidyanath Kamat to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[BR-HP/20/77(6)]

आदेश

का० आ० 1861.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 20-सहरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मदन चौधरी ग्राम तथा डाकखाना बारा भाया पंचगाछिया, जिला—सहरसा (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मदन चौधरी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-लो०स०/20/77(7)]

ORDER

S. O. 1861.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madan Choudhary, Village & P. O. Bara, Via Panchgachia, District Saharsa (Bihar) a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 20-Saharsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Madan Choudhary to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/20/77(7)]

आदेश

का० आ० 1862. यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 14-कोलायत निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सोहन लाल, सेठियों का वास, मोनासर, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोहन लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज०-वि० स०/14/77/(12)]

ORDER

S. O. 1862.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sohan Lal, Sethion Ka Bas, Bhingsar, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 14-Kolayat constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commissioon is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pusuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sohan Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/14/77(12)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1979

का० आ० 1863.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये 40-औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पीतम्बर सिंह ग्राम बटहानी, डाकखाना करकी, बाया गोरारु, जिला गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है, या

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पीतम्बर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-लो०स०/40/77(9)]

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1979

S. O. 1863.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pitamber Singh, Village Bathani, P.O. Kerki Via Gururu Mills, District Gaya (Bihar), a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 40-Aurangabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pitamer Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/40/77(9)]

आदेश

का० आ० 1864.— यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये 37-बक्सर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन सिंह, ग्राम तेतारहर, डाकखाना-परमान पुर द्वारा नवानगर, जिला-भोजपुर (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-लो०स०/37/77(8)]

ORDER

S.O. 1864.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Singh, Village Tetarhar, P. O. Parmanpur, Via Nawanagar, District Bhojpur (Bihar), a contesting candidate for general election to the House of the People in the State of Bihar held in March, 1977 from 37-Buxar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/37/77(8)]

आदेश

का० आ० 1865.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 381-अनूपशहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधेलाल, शिवपुरी, बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधेलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/381/77(10)]

ORDER

S.O. 1865.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Lal, Shivpuri, Bulandshahr, District Buldandshahr, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 381-Anupshahr constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhey Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/381/77 (10)]

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई, 1979

का० आ० 1866.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 38-तिरूचेन्दुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस० सोरयामुथ्थू थेवर, 6/1 वीरा एडाकुडी स्ट्रीट, साथनकुलम, तालुक तिरूचन्दुर, जिला तिरूनेलवेली (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है; अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस० सोरयामुथ्थू थेवर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० ता० म० ली० स० /38/77/(4)]

ORDER

New Delhi, the 22nd May, 1979

S.O. 1866.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. Sooryamuththu Thevar, 6|1 Veera Edakudi Street, Sathankulam, Tiruchendur Taluk, Tirunelveli District (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in March, 1977 from 38-Tiruchendur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. Sooryamuththu Thevar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/38/77(4)]

आदेश

का०आ० 1867 —यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 59-मुगाइयुर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री आई० इल्लूमलाई, 13, सुन्दरम पिलाई लेन, पुरासावालकम, मद्रास-600007 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री आई० इल्लूमलाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ;

[सं० ता० ना० -वि० स० /59/77/(36)]

ORDER

S.O. 1867.— Whereas the Election Commission is satisfied that Shri I. Elumalai, 13, Sundaram Pillai Lane, PurasaWalkam, Madras-600007, a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 59-Mugaiyur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri I. Elumalai to be disqualified for being chosen as, and for beaing, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/59/77(36)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

का० आ० 1868.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 281- खागा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मजहर हैदर उर्फ मज्जू मिया, ग्राम व पोस्ट पट्टी शाह, जिला फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मजहर हैदर उर्फ मज्जू मिया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स० /281/ 77(11)]

वी० नागासुब्रामण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 1868.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mazhar Haidar alias Mazzu Miyan, Village and Post Patti Shah District Fatehpr (Uttar Pradesh), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 281-Khaga constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mazhar Haidar alias Mazzu Miyan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/28/77(11)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

का० आ० 1869.—यत : निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 24-खडूर साहिब (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री करतार सिंह, ग्राम व डा० खान छाबरी, जिला अमृतसर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री करतार सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि० स०/24/77]

आर० डी० शर्मा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st May, 1979

S.O. 1869.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kartar Singh, Village and P.O. Khan Chabri, District Amritsar (Punjab) a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in June,1977 from 24-Khadur Sahib(SC) constituency, has faild to lodge an account of his election expenses at all as required by the

Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kartar Singh to be disqualified for being chosen as ,and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No.PB-LA/24/77/]

R. D. SHARMA, Under Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1979

का० आ० 1870.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै० ए० सी० ई० इन्वेस्टमैंट्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1018/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 23/18/79-एम० 1]

बी० बी० टंडन, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 26th May, 1979

S.O. 1870.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. A.C.E. Investments Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 1018/75).

[No. 23/18/79-M(I)]

B. B. TANDON, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 28 मई, 1979

का० आ० 1871.—1978 के अधिनियम संख्या 45 के अधीन यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली तथा नई दिल्ली में विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायलयों में नीचे दी गई तालिका के कालम 3 में उल्लिखित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के मामलों में अभियोजन तथा उनसे उत्पन्न किसी अन्य मामले का भी संचालन करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कालम 2 में उल्लिखित अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

क्रम संख्या	अधिवक्ता का नाम	मामला संख्या
1	2	3
1.	श्री विपिन बिहारी लाल	श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-III) श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 2/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-I) श्री संजय गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 2 78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-I) श्री बी० सी० शुक्ल के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-II)
2.	श्री अवतार सिंह	श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-I) श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-III) श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 2/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-I) श्री संजय गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 2/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-II) श्री बी० सी० शुक्ल के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-II)
3.	श्री नरेन्द्र सिंह बैंस	श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-I) श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-III) श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 2/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-I) श्री संजय गाँधी तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 2/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-II) श्री बी० सी० शुक्ल के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 1/78-एस० आई० यू० (एस० आई० बी०-II)

[सं० 225/5/79-ए०वी०डी०(2)]

टी० के० सुब्रामणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 28th May 1979

S.O.1871.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure,

1973 (2 of 1974) as amended under Act No. 45 of 1978, the Central Government hereby appoints the Advocates mentioned at column (2) of the Table below as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution and also any other matter arising out of the Delhi Special Police Establishment cases mentioned in column (3) of the Table below in the trial, appellate and revisional courts in Delhi and New Delhi.

TABLE

S. No.	Name of the Advocate	Case Number
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Bipin Behari Lall	Regular case No. 1/78-SIU (SIB-III) against Smt. Indira Gandhi and others. Regular case No. 2/78-SIU (SIB.I) against Smt. Indira Gandoi and others. Regular case No. 2/78-SIU (SIB.II) against Shri Sanjay Gandhi and otners. Regular case No. 1/78-SIU (SIB. II) against Shri V.C. Shukla.
2.	Shri Avtar Singh	Regular case No. 1/78-SIU (SIB. I) against Smt. Indira Gandhi ano others. Regular case No. 1/78-SIU (SIB.III) against Smt. Indira Gandhi and others. Regular case No. 2/78-SIU (SIB.I) against Smt. Indira Gandhi and others. Regular case No. 2/78-SIU (SIB. II) against Shri Sanjay Gandhi and others. Regular case No. 1/78-SIU (SIB. II) against Shri V.C. Shukla.
3.	Shri Narendra Singh Bains.	Regular case No. 1/78-SIU (SIB. I) against Smt. Indira Gandhi and others. Regular case No. 1/78-SIU (SIB. III) against Smt. Indira Gandhi and others Regular case No. 2/78-SIU (SIB. I) against Smt. Indira Gandhi and others. Regular case No. 2/78-SIU. (SIB. II) against Shri Sanjay Gandhi and others. Regular case No. 1/78-SIU. (SIB. II) against Shri V.C. Shukla.

[No. 225/5/79-AVD.II]

T.K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1979

का० आ० 1872.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) दूसरा संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 11 के उपनियम (4) के नीचे "टिप्पण" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण—निधि के अतिशेषों पर 6 मास की अवधि के आगे ब्याज का संदाय,—

(क) एक वर्ष तक की अवधि के लिए, लेखा कार्यालय का प्रधान (इस पद के अंतर्गत वेतन और लेखा अधिकारी, जहां कोई है, भी हैं) ; और

(ख) किसी भी अवधि तक के लिए, लेखा कार्यालय के प्रधान से ठीक वरिष्ठ अधिकारी [इस पद के अंतर्गत लेखा नियंत्रक जहां कोई है, या संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का वित्तीय सलाहकार भी है,]

व्यक्तिगत रूप से अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगा कि संदाय में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जो अभिदाता या उस व्यक्ति के जिसे ऐसा संदाय किया जाना था, नियंत्रण से परे थीं और ऐसे प्रत्येक मामले में होने वाले प्रशासनिक विलम्ब का पूर्णतः अन्वेषण किया जाएगा और यदि अपेक्षित है तो कोई कार्रवाई भी की जाएगी ।"

[संख्या 13(11)-स्था-V(बी)/78 भवि० नि०]

New Delhi, the 30th May, 1979

S.O. 1872.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Second Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. For the "Note" under sub-rule (4) of rule 11 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, the following shall be substituted, namely :—

"Note—Payment of interest on the Fund balance beyond a period of 6 months may be authorised by,—

(a) the Head of Accounts Office (which expression includes the Pay and Accounts Officer, where there is one) upto a period of one year; and

(b) the immediate superior to the Head of Accounts Office (which expression includes a Controller of Accounts, where there is one or the Financial Adviser to the concerned administrative Ministry or Department) upto any period.

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control

of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken"

[No. 13(11)-EV(B)/78-GPF]

का० आ० 1873.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अभिदायी भविष्य निधि (भारत) (संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (4) के नीचे "टिप्पण" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—निधि के अतिशेषों पर 6 मास की अवधि के आगे ब्याज का संदाय,—

(क) एक वर्ष तक की अवधि के लिए, लेखा कार्यालय का प्रधान (इस पद के अंतर्गत वेतन और लेखा अधिकारी, जहां कोई है, भी हैं) ; और

(ख) किसी भी अवधि तक के लिए, लेखा कार्यालय के प्रधान से ठीक वरिष्ठ अधिकारी (इस पद के अन्तर्गत लेखा नियंत्रक जहां कोई है, या सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का वित्तीय सलाहकार भी है),

व्यक्तिगत रूप से अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगा कि संदाय में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जो अभिदाता या उस व्यक्ति के जिसे ऐसा संदाय किया जाना था, नियंत्रण से परे थीं । और ऐसे प्रत्येक मामले में होने वाले प्रशासनिक विलम्ब का पूर्णतः अन्वेषण किया जाएगा और यदि अपेक्षित है तो कोई कार्रवाई भी की जाएगी ।"

[सं० 13(11)-स्था V (बी)/78-भवि० नि०]

सीताराम अग्रवाल, अवर सचिव

S.O. 1873.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1 (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund Rules (India) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the "Note" under sub-rule (4) of rule 12 of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, the following shall be substituted, namely :—

"Note—Payment of interest on the Fund balance beyond a period of 6 months may be authorised by,—

(a) the Head of Accounts Office (which expression includes the Pay and Accounts Officer, where there is one) upto a period of one year ; and

(b) the immediate superior to the Head of Accounts Office (which expression includes a Controller of Accounts, where there is one or the Financial Adviser to the concerned administrative Ministry or Department) upto any period.

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscribe or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken."

[No. 13(11)-EV(B)/78-CPF]

S. R. AGRWALA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

आय-कर

का०आ० 1874.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम	माइक्रोबीयल डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल स्लेजज बाइ स्यूडोमोनस एईरुजीनोसा ।
आयोजनकर्ता . . .	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि०, डाकघर पेट्रोकेमिकल, जिला—बड़ौदा ।
आयोजन का स्थान	महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा ।
आरम्भ होने की प्रस्तावित तारीख .	दिसम्बर, 1978
पूर्ण होने की अनुमानित तारीख .	दिसम्बर, 1980
अनुमानित लागत . .	43,400 रु०

बड़ौदा के दि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अधीन अनुमोदित किया जा चुका है, देखिए वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 1077 (फा०सं० 203/37/75-आ०क०अ० II), तारीख 9-9-1975 ।

[सं० 2734 (फा०सं० 203/23/79-आ०क०अ०II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th February, 1979.

(INCOME-TAX)

S.O. **1874.**—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income -tax Act, 1961 read with Rule 6 (iv) of the Income-tax Rules, 1962, by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi.

Name of the scientific research programme :	Microbial Degradation of Petrochemical Sludges by Pseudomonas aeruginosa.
Name of the sponsorer ..	Indian Petrochemicals Ltd., P. O. Petrochemicals Distt. Baroda.
To be undertaken by	Maharaja Sayajirao University, Baroda.
Proposed date of commencement :	December, 1978 .

Anticipated date of completion.	December, 1980.
Estimated outlay	Rs. 43,400.

2. The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Baroda stands approved u/s. 35 (i) (iii) of the Income-tax Act, 1961 vide finance Department's Notification No. 1077 (F. No. 203/37/75-IIA.II) dated 9-9-1975.

[No. 2734 /F. No. 203/23/79-IIA.II]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1979

आय-कर

का० आ० 1875.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

के०एम० वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, मसोधा, डाकघर मोदीनगर, जिला फैजाबाद

यह अधिसूचना 17-1-79 से 16-1-1980 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी ।

[सं० 2739/फा०सं० 203/197/78—आ०क०अ० II]

New Delhi, the 1st March, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1875.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

K.M.Scientific Research Centre, Masodha, P.O.Modinagar, Distt. Faizabad.

This notification will be effective for a period of one year from 17.1.1979 to 16.1.1980.

[No. 2739/F. No. 203/197/78-ITA.II]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1979

आय-कर

का० आ० 1876.—राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 34, तारीख 24 नवम्बर, 1946 में निम्नलिखित संशोधन करना है :—

"दि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बाम्बे ।" के स्थान पर "विज्ञान संस्थान, मुम्बई" पढ़ें ।

[सं० 2754(फा०सं० 203/6/79-आई टी ए II)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th March, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1876.—The Department of Revenue hereby amend the Notification No. 34 dated 24th November, 1946 as under:—

For	Read
The Royal Institute of Science, Bombay.	The Institute of Science, Bombay.

[No. 2754 F. No. 203/6/79-ITA.II]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1979

आय-कर

का० आ० 1877.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(i) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगी ।

(ii) यह कि संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

शान्ति अवेदना आश्रम, मुम्बई

यह अधिसूचना 6 फरवरी, 1979 से 5-2-1981 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 2753 (फा०सं० 203/45/79-आई टी ए II)]

New Delhi, the 27th March, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1877.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific research association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions:—

(i) That the Association will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

SHANTI AVEDNA ASHRAM, BOMBAY

This notification is effective for a period of 2 years from 6th February, 1979 to 5.2.1981.

[No.2753/F.No.203/45/79-ITA.II]

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1979

आय-कर

का०आ० 1878.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है ।

संस्था

भाई लाल अमीन फाउंडेशन, बड़ौदा

यह अधिसूचना 1-1-1979 से 31-12-1980 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 2759 (फा०सं० 203/60/78-आई टी ए II)]

New Delhi, the 30th March, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1878.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Bhailal Amin Foundation, Baroda

This notification is effective for a period of 2 years from 1.1.1979 to 31.12.1980.

[No. 2759/F. No. 203/60/78-ITA.II]

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

आय-कर

का०आ० 1879.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है ।

संस्था

दि उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड, जिला बेलगांव

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 से 28 फरवरी, 1981 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 2767 (फा०सं० 203/100/78-आई टी ए II)]

New Delhi, the 9th April, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1879.— It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

The Ugar Sugar Works Ltd., Distt. Belgaum.

This notification is effective for a period of two years from 1st March, 1979 to 28th February, 1981.

[No. 2767/F.No.203/100/78-ITA.II]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1979

आय-कर

का०आ० 1880.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में 'संस्था' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्थान, प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला

यह अधिसूचना 10-11-1978 से 9-11-1981 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 2775 (फा०सं० 203/160/78-आई टी ए II)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 25th April, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1880.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, the Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category 'Institution' in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions:—

(i) that the Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agriculture/animal husbandry/fisheries & medicines).

(ii) that the said Institute will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala.

This notification is effective for a period of three years from 10.11.1978 to 9.11.1981.

[No. 2775/F. No. 203/160/78-I.T.A.II]

J. P. SHARMA, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई 1979

बीमा

का०आ० 1881.—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27-ख की उपधारा (i) के खंड (ज) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1978-79 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 2.50 करोड़ रुपए मूल्य के 1988 (प्रथम सीरीज) के 6-1/2 प्रतिशत वाले 10 वर्षीय बंधपत्रों को, (इस अधिकार के साथ कि 2.50 करोड़ रुपए से ऊपर प्राप्त अभिदाय का 10 प्रतिशत तक प्रतिधारित कर लिया जाएगा) उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "अनुमोदित विनिधान" के रूप में घोषित करती है।

[सं० 88(23) इंस्यो IV/78)]

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 22nd May, 1979

(INSURANCE)

S.O. 1881.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (1) of section 27-B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby declares the 6¼ per cent 10 years Bonds 1988 (1st Series) of the value of Rs. 2.50 crores issued in 1978-79 (with the right to retain the subscription received upto 10 percent in excess of Rs. 2.50 crores) by the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, as "approved investments" for the purposes of said secion.

[No. 88 (23) Ins. IV/78]

का० आ० 1882 केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27-क की उपधारा (1) के खंड (थ) द्वारा, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना सं० सा०.का०. नि०. 734 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को लागू होता है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1978-79 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 2.50 करोड़ रुपए मूल्य के 1988 (प्रथम सिरीज) के 6-1/2 प्रतिशत वाले 10 वर्षीय बंधपत्रों को (इस अधिकार के साथ कि 2-50 करोड़ रुपए से ऊपर प्राप्त अभिदाय का 10 प्रतिशत तक प्रतिधारित कर लिया जाएगा) उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित विनिधान" के रूप में घोषित करती है।

[सं० 88(23) इंस्यो iv/78)

एस०डी० रहेजा, अवर सचिव

S.O. 1882.—In exercise of the powers conferred by Clause (q) of sub-section (1) of section 27-A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as applied to the Life Insurance Corporation of India by the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 734, dated 23rd August, 1958, the Central Government hereby declares the 6¼ per cent 10 years bonds 1988 (1st Series) of the value of Rs. 2.50 crores issued in 1978-79 (with the right to retain the subscription received upto 10 per cent in excess of Rs. 2.50 crores) by the Indusrial Reconstruction Corporation of India Limited, as "scheduled investment" for the purposes of the said section.

[No. 88(23)Ins.IV/78]

S. D. RAHEJA, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1979

का० आ० 1883 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारियों में से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई के परियोजना वित्त प्रभाग के प्रबन्धक श्री डब्ल्यू०के० मानगांवकर को 22 मई, 1979 से आरम्भ होकर 21 मई, 1982 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है।

[संख्या एफ 9/15/79-बी०ओ०-I]
बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 22nd May, 1979

S.O. 1883.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (1), read with sub-section (4), of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri W. K. Mangaokar, Manager, Project Finance Division, Industrial Development Bank of India, Bombay, as a director of the Industrial Development Bank of India, from amongst the officer employees of the Industrial Development Bank of India and financial institutions, for a period of three years commencing on the 22nd day of May, 1979 and ending with the 21st day of May, 1982.

[No. F. 9/15/79-BO. I]
BALDEV SINGH, Joint Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

का० आ० 1884.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में फार्म 'क' के साथ संलग्न नोट (च) के उपबंध, बैंक आफ कोचीन लिमिटेड पर उसके 31 दिसम्बर 1978 तक के तुलन पत्र के बारे में लागू नहीं होंगे जो कि कथित फार्म के सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति पक्ष की मद 4 के उप-शीर्ष (2), (3), (4) तथा (5) में से किसी के सामने के अन्दर वाले खाने में दिखाये गये मूल्य से उप शीर्ष के अन्तर्गत निवेशों से बाजार मूल्य के बढ़ जाने पर उस उप शीर्ष के अंतर्गत निवेशों के बाजार मूल्य को अलग से कोष्ठकों में दिखाता है।

[संख्या 15(9)-बी० ओ०-III/79]

New Delhi, the 26th May, 1979

S.O. 1884.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note(f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the Bank of Cochin Ltd. in respect of its balance-sheet as at the 31st December 1978, which, when the value shown in the inner column against any of the sub-heads (ii), (iii), (iv) and (v) of item 4 of the Property and Assets side of the said Form exceeds the market value of the investments under that sub-head, shows separately within brackets the market value of the investments under that sub-head.

[No. 15(9)-B.O. III/79]

नई दिल्ली, 23 मई, 1979

का० आ० 1885—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 2 के उपबंध, 31 मार्च, 1980 तक, ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इस बैंक द्वारा, निम्नलिखित कम्पनियों के नामों के आगे दिये गये शेयरों के बंधक रूप में धारिता से है ।

कम्पनी का नाम	बंधक रखने की तारीख	शेयरों का चुकता मूल्य (लाख रुपयों में)
1. जे के आटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	24-11-66	1.65
	03-02-1967	0.25
2. ग्लोब यूनाइटेड इंजिनियरिंग एण्ड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड ।	20-11-1967	8.80
	16-02-1967	8.81
	16.03-1968	0.05

[सं० 15(13)-बी०ओ०-III/79]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1979

S.O. 1885—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Sub-section 2 of Section 19 of the said Act shall not apply, till the 31st March 1980, to Grindlays Bank Ltd., Calcutta in respect of the shares held by it as pledgee of the under noted companies as shown against their names.

Name of the company	Date of lodgement	Paid up value of the shares held (in lakhs of Rs.)
1. Jay Kay Automobiles Pvt. Ltd.	24-11-1966	1.65
	03-02-1967	0.25
2. Globe United Engineering and Foundry Co. Ltd.	20-11-1967	8.80
	16-02-1968	8.81
	16-03-1968	0 05

[No.15(13)-B.O.III/79]

M.B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1979

का०आ० 1888—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर० पी० त्रिवेदी, सहायक मुख्य अधिकारी (ग्रामीण विकास), सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को श्री ए० एम० कोर्डे के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जून, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर० पी० त्रिवेदी, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 8-8/79-आर० आर० बी.]

सी० आर० बिश्वास, उप-सचिव

New Delhi, the 26th May, 1979

S.O. 1886.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. P. Trivedi, Assistant Chief Officer (Rural Development) Central Bank of India as the Chairman of the Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad vice Shri A. M. Korde and specifies the period commencing on the 1st June, 1979 and ending with the 30th June, 1982 as the period for which the said Shri R. P Trivedi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 8-8/79-RRB]

C. R. BISWAS, Deputy Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1079

का०आ० 1887.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (प्रथम संशोधन) नियम 1979 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में,

(1) नियम 3 में, उप-नियम (1) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(छ) 'विभागाध्यक्ष' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी भी कार्यालय अथवा कार्यालयों के संबंध में उसका अर्थ अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है और इसमें ऐसा अन्य प्राधिकारी और व्यक्ति भी शामिल हैं जिसे केन्द्रीय सरकार का संबंधित विभाग, आदेश द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करें ;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति किसी अभिज्ञेय संगठन का अध्यक्ष हो और उसके संशोधित वेतनमान का न्यूनतम भारत सरकार के उपसचिव के वेतनमान के न्यूनतम से कम न हो ,

(ii) अनुसूची 1 में, "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, उप-शीर्षक '(क) आर्थिक कार्य विभाग' और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(क) आर्थिक कार्य विभाग :

1. निदेशक, आपात जोखिम बीमा योजना, नई दिल्ली ।

2. बीमा नियंत्रक, शिमला ।

3. भारत का राष्ट्रीय बचत आयुक्त ।

4. मास्टर, भारत सरकार टकसाल, अलीपुर रोड, कलकत्ता, इंचार्ज सिलवर रिफाइनरी, कलकत्ता ।

5. मास्टर, भारत सरकार टकसाल, बम्बई।

6. मास्टर, भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद।

7. महाप्रबन्धक तथा पदेन स्टाम्प नियंत्रक इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड।

8. महाप्रबन्धक, सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद।

9. महाप्रबन्धक, बैंक नोट प्रेस, देवास"

(iii) अनुसूची v के अनुबन्ध में—

(क) क्रम संख्या 14 में, कालम 4 की मद संख्या 2 में मुद्रण तथा जिल्द बंधन से संबंधी प्रविष्टि में "(1) सभी विभाग 5,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रविष्ट के स्थान पर" "(1) सभी विभाग.... 10,000 रुपए प्रतिवर्ष" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) क्रम संख्या 26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

1	2	3	4
"26.	सभी प्रकार के कम्प्यूटरों को छोड़कर, टाइपराइटर, इन्टर-काम इक्विपमेंट, कैलकुलेटर्स इलैक्ट्रोनिक स्टेंसिल कटर्ज, डिक्टाफोन, टेपरिकार्डर्स, फोटो कापियर्ज, कापीइंग मशीन, फैंकिंग मशीन, एड्रेसोग्राफ फाइलिंग एंड इन्डेक्सिंग सिस्टम आदि	संपूर्ण शक्तियां	(1) इन मशीनों की खरीद, उन्हें किराए पर लेने उनके अनुरक्षण और मरम्मत पर व्यय, वित्त मंत्रालय या पूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन किया जाएगा। (2) विभागाध्यक्ष भी इस संबंध में निर्दिष्ट सामान्य शर्तों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित सीमाओं तक व्यय कर सकते हैं:— आवर्ती 500 रु० अनावर्ती 5000 रु०"

(iv) अनुसूची vii में कालम 2 की मद संख्या (1) में "स्टाफ ३ ... न्य खातों में शामिल मोटर वाहन अथवा मोटरसाइकिल को ... कर अन्य सामग्री के मूल्य में कमी अथवा ह्रास" से संबंधित प्रविष्टि में कालम 3 में "रुपए 1000" शब्दों और अंकों के स्थान पर "रुपए 2500" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

टिप्पणी:—22 जुलाई, 1978 के साप्ताहिक गजट के भाग ii खण्ड (3) उपखंड (ii) में प्रकाशित और का०आ० संख्या 2131 के अधीन प्रख्यापित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियनमावली, 1978 के ये प्रथम संशोधन नियम है।

[संख्या फ० 1(9)-संस्था II(क) 74]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 16th May, 1979.

S.O. In 1887—pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (First Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Delegation of Financial Powers Rules, 1978,

(i) in rule 3 for clause (f) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) Head of the Department in relation to an office or offices under his administrative control means an authority specified in Schedule I and includes such other authority or person as the concerned Department in the Central Government may, by order specify, as a Head of the Department :

Provided that such a person is the Head of an identifiable organisation and the minimum of his revised scale of pay is not lower than that of a Deputy Secretary to the Government of India." ;

(ii) in Schedule I, under the heading "MINISTRY OF FINANCE", for the sub-heading '(A) Department of Economic Affairs' and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"(A) Department of Economic Affairs :

1. Director Emergency Risks Insurance Scheme, New Delhi.
2. Controller of Insurance, Simla.
3. National Savings Commissioner for India.
4. Master India Government Mint, Alipore Road, Incharge Silver Refinery, Calcutta.
5. Master India Government Mint, Bombay.
6. Master India Government Mint, Hyderabad.
7. General Manager and Ex-Officio Controller of Stamps, India Security Press, Nasik Road.
8. General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad.
9. General Manager, Bank Note Press, Dewas." ;

(iii) in the Annexure to Schedule V.

(a) in serial No. 14, the entry relating to Printing and Binding, in column 4, in item 2, for the entry "(i) All Departments.......Rs. 5,000 per annum" the entry, "(i) All Departments......Rs. 10,000 per annum" shall be substituted ;

(b) for serial No. 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4
"26.	All office equipments including typewriters, intercom equipment, calculators, electronic stencil cutters, dictaphones, tape recorders, photo copiers, copying machines, franking machines, addressographs, filing and indexing systems, etc. excluding Computors of all kinds.	Full powers.	(1) The expenditure on the purchase, hire, upkeep of and repairs to such machines shall be incurred subject to general or special orders issued by the Ministry of Financ or Department o f Supply from time to time in this behalf.

1	2	3	4
		(2) Heads of Offices may also incur expenditure in this regard subject to the observance of general conditions laid down in this regard upto the following limits :—	
		Recurring	Rs. 500
		Non-recurring	Rs. 5,000.

(iv) in Schedule VII, in the entry relating to "Deficiencies and depreciation in the value of stores other than a motor vehicle or a motor cycle, included in the stock and other accounts" in item (i) in column 2, for the letters and figures "Rs.1,000" in column 3, the letters and figures "Rs.2,500" shall be substituted.

Note : These are First Amendment Rules to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 promulgated vide S.O. 2131 appearing in part II, Section (3) Sub-section (ii) of the Weekly Gazettee dated July 22, 1978.

[No. F.I. (9)-E-II (A)/74]

नई दिल्ली, 18 मई, 1979

का० आ० 1888.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, भोपाल
2. सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा (उर्वरक और रसायन) नई दिल्ली
3. डाक-तार लेखा परीक्षा कार्यालय दिल्ली
4. निदेशक लेखा परीक्षा (खाद्य) लखनऊ

[मि०सं० ए-11019/1/79 ई०जी०I]

एस०के० दास, अवर सचिव

New Delhi, the 18th May, 1979

S.O. 1888.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the Indian Audit and Accounts Department, the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :

1. Member, Audit Board & Ex-officio Director of Commercial Audit, Bhopal.
2. Member, Audit Board & Ex-officio Director of Commercial Audit (Fertiliser & Chemicals), New Delhi.
3. P & T Audit Office, New Delhi.
4. Director of Audit (Food), New Delhi.
5. Regional Audit Office (Food), Lucknow.

[F. No. A-11019/1/79-EGI]

S. K. DAS, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1979

का०आ० 1889.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिये कतिपय प्रस्ताव तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं०का०आ० 491 तारीख 11 फरवरी, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1965 के नियम 11 के उप-नियम (11) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश तारीख 22 अप्रैल, 1978 से भारत के राजपत्र, तारीख 22 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित किये गए थे ।

और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 अप्रैल, 1978 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 491 तारीख 11 फरवरी, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर, कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है —

(1) अधिसूचित करती है कि मेंढक की प्रशीतित टांगे निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ।

(2) इस आदेश के उपाबंध I में दिए गए मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है तो निर्यात से पूर्व मेंढक की प्रशीतित टांगों के संबंध में लागू होगा ;

(3) मेंढक की प्रशीतित टांगों के लिए इस आदेश के उपाबंध II में दिए गए विनिर्देशों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान मेंढक की ऐसी प्रशीतित टांगों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि मेंढक की ऐसी प्रशीतित टांगे मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात योग्य है ।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को जल, थल या वायु मार्ग द्वारा मेंढक की प्रशीतित टांगों के उन नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका मूल्य 250/- से अधिक नहीं है ।

3. इस आदेश में मेंढक की प्रशीतित टांगों से, जैसे :—

(i) राना टाइग्राइना

(ii) राना हैक्साडेक्टाइला तथा

(iii) राना आगा

खाद्य मेंढकों से प्राप्त सभी प्रकार की मेंढक की प्रशीतित टांगे या मेंढक का मांस अभिप्रेत है ।

[सं० 6(10)/77-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLY AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1979

S.O. 1889.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting frozen froglegs to quality control and inspection prior to export, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 491 dated the 11th February, 1966 and the notification were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rule 1964, in the Gazette of India dated the 22nd April, 1978 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce dated the 22nd April, 1978.

And whereas objections and suggestions were invited within forty five days of the publication of the said order from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th April, 1978.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 491 dated the 11th February, 1966, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

(1) notifies that frozen froglegs shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Frozen Froglegs (Quality Control and Inspection) Rules, 1979 as the type of inspection as set out in Annexure I to this order which shall be applied to such frozen froglegs prior to their export;

(3) recognises the specification as set out in Annexure II to this order as the standard specifications for frozen froglegs;

(4) prohibits the export, in the course of international trade of such frozen froglegs unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by an Agency established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to the effect that such frozen froglegs conform to the standard specifications and are exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of frozen froglegs to prospective buyers, the value of which does not exceed Rs. 250.

3. In this order frozen froglegs shall mean all types of frozen froglegs or frogmeat, obtained from edible frogs such as :

(i) Rana Tigrina;
(ii) Rana hexadactyla; and
(iii) Rana crassa.

[No. 6(10)/77-EI&EP]

का०आ० 1890.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—इन नियमों का नाम मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) 'मेंढक' की प्रशीतित टांगों से—

(i) राना टाइग्राइना

(ii) राना हैक्साडेक्टाइला; तथा

(iii) रानक्रासा

जैसे खाद्य मेंढकों से प्राप्त सभी प्रकार के मेंढक की प्रशीतित टांगे या मेंढक का मांस अभिप्रेत है :

(घ) "मानक विनिर्देश" से प्रशीतित मेंढक की टांगों के वे विनिर्देश अभिप्रेत है जो इस आदेश के उपाबंध II में अधिकथित हैं।

3. "क्वालिटी नियंत्रण"

क. प्रसंस्करण यूनिटों की अपेक्षाएं

अभिकरण द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण एकक ही निर्यात के लिए मेंढक की प्रशीतित टांगों को प्रसंस्कृत करने के पात्र होंगे। (मछली तथा मछली से बने उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अनुमोदित एककों को भी निर्यात के लिए मेंढक की टांगों को प्रसंस्कृत करने की अनुमति दी जाएगी)। ऐसे अनुमोदन के लिए अर्हित होने के लिए एकक के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए।

(1) पास पड़ोस संरचना तथा अभिन्यास

(क) प्रसंस्करण एकक के पास पड़ोस में, जो प्रसंस्करणकर्ता के भौतिक नियंत्रण में हो, ऐसे कोई, दलदल, कूड़ा फेंकने के स्थान या पशुगृह होने चाहिए जो स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं।

(ख) हवा से उड़कर आने वाली धूल से बचने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी निकटतम पहुंच मार्गों पर, जो प्रसंस्करणकर्ता के भौतिक नियंत्रण में हों, कंकरीट या तारकोल बिछाया जाना चाहिए या घास उगाई जानी चाहिए।

(ग) प्रसंस्करण एकक एक ऐसे स्थायी भवन में होगा, जहां वर्षा तथा हवा से उड़कर आने वाली धूल जैसे सामान्य जल वायु संबंधी खतरों से पर्याप्त सुरक्षा रहे।

(घ) विभिन्न अनुभागों का अभिन्यास इस ढंग से किया जाएगा कि कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा प्रसंस्करण पूर्व अनुभाग से संभव दूषण को रोका जा सके।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र

(क) वह क्षेत्र जहां कच्चा माल प्राप्त तथा भंडारित किया जाता है उस क्षेत्र से बिल्कुल अलग रखा जाएगा जिसमें उत्पाद अन्तिम रूप से तैयार होता है या उसकी पैकिंग की जाती है जिससे कि तैयार उत्पाद दूषित होने से बच सके।

(ख) खाद्य उत्पादों को भंडार करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले क्षेत्र तथा कक्षा उन क्षेत्रों तथा कक्षों से अलग तथा भिन्न होंगे जिनमें अखाद्य सामग्री रखी जाती है।

(ग) जिन क्षेत्रों में सामग्री उठाई धरी जाती है वे निवास के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त क्षेत्र से बिल्कुल अलग होंगे।

(घ) ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कटी हुई टांगें पूरी सफाई के साथ तथा काटने के समय जितना संभव हो उतने कम समय में प्रसंस्करण एककों को ले जाई जाएंगी ।

(ङ) प्रसंस्करण एककों के समान कटिंग केन्द्र भी उन्हीं सफाई संबंधी अपेक्षाओं के अधीन होंगे ।

(च) अच्छी सफाई तथा स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित सफाई कार्यक्रम अपनाया जाएगा ।

(3) छत, दीवार तथा फर्श

(क) उस कमरे की छत जहां माल या तो रखा जाता है या प्रसंस्कृत किया जाता है, दरारों और खुले हुए जोड़ों से मुक्त होगी तथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आसानी से सफाई की जा सकती हो ।

(ख) छत ऐसी हो कि उसमें कृन्तक रुक न सकते हों ।

(ग) प्रसंस्करण क्षेत्रों की दीवारें चिकनी तथा गड्ढों और दरारों से मुक्त होंगी । तथा उन्हें ऐसी होगी कि उन्हें कम से कम 1.3 मीटर तक की ऊंचाई तक धोया जा सकता हो ।

(घ) फर्श अपारगम्य तथा असंक्षारक सामग्री से बना होगा तथा उसमें अपशिष्ट पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ढलान होगा ।

(ङ) फर्श तथा दीवारों के जोड़ों में ऐसी गोलाई होनी चाहिए कि सफाई आसानी से हो सके ।

(4) मक्खियों से बचाव कीड़ों तथा पशुओं पर नियंत्रण

(क) प्रसंस्करण क्षेत्र में मक्खियों से बचाव के लिये सभी प्रभावशाली व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के कीड़ों, कृन्तकों, पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों तथा इसी प्रकार के अन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए उपाय किये जाएंगे ।

(5) प्रकाश तथा संचालन

(क) सभी कार्य-क्षेत्रों में अच्छा प्रकाश होना चाहिए ।

(ख) प्रसंस्करण मेज के ऊपर या उत्पाद को तैयारी के किसी भी प्रक्रम पर, रोशनी के लिए बल्ब या फिक्सचर सीधे नहीं लटकाए जाने चाहिए । ये सुरक्षित प्रकार के होने चाहिए अथवा उन्हें अन्यथा इस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए कि टूट जाने की दशा में संदूषण को रोका जा सके ।

(ग) जिन कमरों में काम किया जाता है, उनमें ताजी हवा लाने के लिए, अवांछनीय गंध, भाप तथा धुएं को वहां से निकालने के लिए तथा वहां द्रवण रोकने के लिये, प्राकृतिक या यांत्रिक संवातन प्रणाली की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए ।

(6) काम करने के लिये मेजें तथा बर्तन

(क) प्रसंस्करण कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मेजें, लकड़ी से भिन्न, किसी असंक्षारक, अनभिकारक सामग्री की होंगी ।

(ख) प्रसंस्करण मेजें इस प्रकार से बनाई तथा लगाई जाएंगी कि उनके नीचे तथा आस-पास के क्षेत्र की आसानी से सफाई की जा सके ।

(ग) मेज की सतह स्टैनलैस इस्पात, एल्यूमिनियम अथवा जंग रहित जी० आई० चादर की होनी चाहिए तथा समतल और गड्ढों तथा दरारों से मुक्त होगी ।

(घ) काम में आने वाली मेजों की व्यवस्था ऐसे की जाएगी कि काम सुगमता से किया जा सके ।

(ङ) प्रसंस्करण के लिए काम में आने वाली सभी पात्र जैसे ट्रे, टैंक, कुण्ड तथा बर्तन, लकड़ी से भिन्न, असंक्षारक पदार्थ के होंगे । ये दरारों से मुक्त समतल सतह वाले होंगे । तारों की जाली के प्रयोग की अनुमति भी दी जा सकती है बशर्ते कि वह जंग रहित हो ।

(च) इनेमिल किए गए बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(छ) बांस की टोकरियों का प्रयोग प्रसंस्करण कक्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अनुमत किया जा सकता है ।

(ज) अखाद्य तथा दूषित सामग्री के लिये प्रयोग में लाए जाने वाले उपस्कर तथा बर्तन ऐसे होने चाहिये कि उन्हें किसी चिन्ह या आकार या रंग के कारण पहचाना जा सके । जिसके लिये उन्हें खाद्य वस्तुओं को धरने-उठाने के लिये प्रयोग में न लाया जा सके ।

(झ) प्रसंस्करण क्रिया के दौरान कार्य क्षेत्रों से अपशिष्ट सामग्री शीघ्र हटाई जाएगी तथा इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त संख्या में अपशिष्ट पात्रों की व्यवस्था की जाएगी ।

(7) मशीनें

(क) कार्य सर्वाधिक होने के समय, उत्पादन की पूर्ति के लिये पर्याप्त प्रशीतन क्षमता होनी चाहिए तथापि अन्य अनुमोदित प्रसंस्करण एककों की फालतू क्षमता का भी प्रयोग किया जा सकता है परन्तु ऐसे प्रशीतन के लिए नियंतिकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता जिम्मेदार होगा ।

(ख) जिस प्रकार का प्रशीतन काम में लाया जाएगा वह उत्पाद की प्रकृति तथा पैकिंग की किस्म को देखते हुए विशेष किस्म का होगा । उत्पाद की अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजन के लिये प्लेट प्रशीतक या ब्लास्ट प्रशीतक का प्रयोग किया जा सकता है ।

(ग) सामग्री अलग-अलग जल्दी जमने वाली होगी या उसे ब्लाकों में प्रशीतित किया जाएगा ताकि $3\frac{1}{2}$ घंटे की अवधि में उसका तापमान 40° सें० ग्रे० तक पहुंच जाए ।

(घ) तापमान दर्शित करने के लिये प्रशीतन उपकरण के साथ गेज फिट किए जाएंगे ।

(8) शीतागार तथा भण्डागार

(क) शीतागार की स्थिति तथा डिजाइन इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह सम्पूर्ण स्थापना के सामान्य अभिन्यास के साथ सम्बद्ध रहे तथा इसका प्रचालन सर्वांगीण कार्य पद्धति में खप सके ।

(ख) प्रत्येक प्रशीतन एकक में पर्याप्त क्षमता वाले शीतागार होंगे । तथापि निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए, शीतागारों की सामान्य सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है :—

(i) उचित तापमान बनाए रखना ;

(ii) विद्युत रोधी ट्रकों द्वारा परिवहन; तथा

(iii) डिब्बों के इस प्रकार घण्टे लगाए जाएं कि उन्हें पहचाना जा सके ।

(ग) शीतागार का आदर्श तापमान — 18° सें० ग्रे० अथवा उससे कम होगा और अच्छा यह होगा कि उसमें कोई स्वचालित तापमान अभिलेखन यंत्र फिट हो, तथापि जांच के किसी भी समय उत्पाद का तापमान 16° सें० ग्रे० होना चाहिए ।

(घ) निरन्तर अभिलेखन थर्मामीटर के अभाव में, शीतागार का तापमान कम से कम प्रत्येक 4 घंटे में मापा जाएगा तथा उसका उचित अभिलेख रखा जाएगा ।

(ङ) शीतागार में प्रकाश की उचित व्यवस्था होगी तथा आसानी से हवा आने जाने की सुविधा के लिये फर्श तथा साइडों पर उचित व्यवस्था की जाएगी ।

(च) शीतागार में प्रवेश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि प्रवेश द्वार खोलते ही तापमान में अधिक वृद्धि न हो अन्यथा इससे भंडारित सामान पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

(छ) उचित आकार के एक संलग्न कक्ष की भी व्यवस्था की जानी चाहिए है तो संलग्न कक्ष की व्यवस्था आवश्यक नहीं होगी ।

(ज) शीतागार की प्रशीतक सतह को, उस पर बर्फ या हिम के अधिक जमने को रोकने के लिए नियमित रूप से विहिमीकृत किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रशीतन यंत्र की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

(झ) विहिमीकरण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि हिम, बर्फ या पिघल कर बना पानी भंडारित उत्पाद पर न पड़े।

(ञ) यदि कोई व्यक्ति शीतागार के अन्दर फंस जाए तो उसे समय से सहायता पहुंचाने के लिए शीतागार में कारगार खतरे की घंटी लगी होनी चाहिए।

(ट) शीतागार में सफाई संबंधी अपेक्षाओं का उसी प्रकार पालन किया जाएगा जैसे कि सामग्री की व्यवस्था करने वाले अन्य स्थापनों में होता है।

(ठ) इस प्रयोजन के लिये नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित हो सके।

(ड) जिस एककों में पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में, कच्चा माल रात भर के लिए भंडारित किया जाता है वहां उपयुक्त आकार के एक ठंडे कमरे की, जिसका तापमान $+1^{\circ}$ सें० या कम हो, व्यवस्था की जाएगी। तथापि जिन एककों में ठंडे कमरे की सुविधा नहीं है उनमें सामग्री को रात भर पर्याप्त बर्फ में रखा जाना चाहिये।

(ढ) सभी प्रक्षालक तथा रोगाणुनाशक अलग-अलग भंडारित किये जाएंगे।

(ण) पैकिंग सामग्री को भंडार में रखने की सुविधा अलग से होगी।

(त) अग्निशमन यंत्रों के अतिरिक्त, जहरीले पदार्थ जैसे कृन्तकनाशी, धूमक, कीट नाशी या अन्य पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पृथक बंद कमरे में रखे जाने चाहिए।

(9) जल तथा बर्फ

(क) पेय जल (हानिकारक रसायन तथा कीटाणु रहित) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा।

(ख) यदि प्रसंस्करण के लिये प्रयुक्त जल, संरक्षित जल प्रदाय स्कीम से भिन्न श्रोत से लिया जाता है तो उसकी पेयता का प्रमाण-पत्र जिसे निर्यात निरीक्षण अभिकरण ने या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं ने दिया हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) यदि बायलर या अन्य सहायक सेवाओं के लिए पीने अयोग्य जल का प्रदाय किया जाता है तो सहायक जल वितरण तंत्र तथा पेय जल वाहन तंत्र के बीच कोई क्रास-संबंध नहीं होगा।

(घ) यदि संचयन टंकी का प्रयोग किया जाता है तो उसे बाहरी संदूषणों से अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, और वह पर्याप्त क्षमता वाली होगी।

(ङ) संचयन टंकी 6 मास में कम से कम एक बार अच्छी तरह से साफ की जाएगी।

(च) प्रसंस्कृत कच्चे सामग्री के प्रत्येक किलो ग्राम के लिये पेयजल की खपत कम से कम 12 लिटर होगी।

(छ) प्रसंस्करण के लिये प्रयुक्त जल में क्लोरीन अंश कम से कम 3 पी० पी० एम० स्तर पर रखा जाएगा।

(ज) चमकाने (ग्लेजिंग) तथा पुनः चमकाने (रीग्लेजिंग) के लिये प्रयुक्त जल 10 पी०पी० एम० स्तर परक्लपेरीन युक्त होगा।

(झ) केवल पेय जल से बनी बर्फ ही प्रयोग में लाई जाएगी।

(ञ) यदि बाहर की बनी बर्फ ही प्रयोग की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह पेय जल से बनाई गई है तथा दूषित नहीं है।

(ट) यदि बर्फ तोड़ने की मशीन प्रयुक्त की जाती है तो वह अच्छी साफ हालत में रखी जाएगी।

(10) सफाई संबंधी सुविधाएं तथा नियंत्रण

(उ) सफाई

(क) ऐसे सभी बर्तन, ट्रे और मेज की सतह, जो कच्चे माल को छोड़कर अन्य सामग्री के लिये प्रयुक्त होती है, पहले अपमार्जक पदार्थों से साफ की जाएगी और अंत में न्यूनतम 50 पी०पी० ए० क्लोरीन वाले जल से साफ की जाएगी।

(ख) प्रसंस्करण कक्ष दिन का काम प्रारम्भ करने से पहले एक बार साफ किया जाएगा और फिर प्रत्येक पारी के अन्त में साफ किया जाएगा।

(ग) इसके अतिरिक्त सफाई और धुलाई समय-समय पर आवश्यकतानुसार बार-बार की जाएगी।

(ii) धुलाई की सुविधा

(क) प्रत्येक प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश द्वार के पास साबुन तथा हाथ धोने की पर्याप्त सुविधाएं की जाएंगी।

(ख) पांव साफ करने का प्रबंध भी प्रवेश द्वार के पास किया जाएगा।

(iii) वाहित मल तथा अपशिष्ट जल का निपटान

(क) प्रसंस्करण परिसर में प्रयुक्त जल को निकालने के लिये जल निकास की और उसे एकक से कम से कम तीन मीटर दूर किसी नाले में डालने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(ख) कारखाने के अन्दर जल निकास व्यवस्था ठीक से ढकी हुई होगी तथा सरलता से सफाई करने योग्य होगी।

(ग) कृन्तकों के प्रवेश को रोकने के लिए खुली नालियों के जो दीवारों में से गुजरती है, मुख पर धातु की जालिया लगाई जाएंगी।

(घ) मल, गंदे पानी और कूड़े करकट के निपटान की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह एकक तथा उसके पास-पड़ोस के लिये सफाई संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न करे।

(ङ) शौच स्थल से गंदा जल इस ढंग से बहाया जाएगा कि मक्खियां उस तक पहुंच न सके और एककों को दिया जाने वाला पानी प्रदूषित न हो।

(च) किसी भी दशा में परिसर में अपशिष्ट जल या वर्षा का जल एकत्रित नहीं होगा।

(iv) शौच सुविधाएं

(क) इस संबंध में लागू विधिक अपेक्षाओं के अनुसार सफाई की दृष्टि से पर्याप्त शौच सुविधाएं दी जाएंगी।

(ख) शौच स्थल प्रसंस्करण क्षेत्रों से कुछ दूर अलग स्थित होंगे तथा उनके अपने आप बंद होने वाले दरवाजे हाथ धोने का पात्र तथा साबुन की सुविधाएं भी होंगी।

(ग) धुलाई के प्रयोजनों के लिए पेय जल उपलब्ध किया जाएगा।

(ii) कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता

(क) संयंत्र के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह ज्ञात हो कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित है ऐसे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति न दी जाएगी जहां उत्पाद उठाया रखा जा रहा हो।

(ख) ऐसे रोग का पता आसानी से लगाने के लिए प्रबंधक उन कर्मचारियों की जो एकक के खाद्य संबंधी क्षेत्र में कार्य कर रहें हैं वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा कराएगा ।

(ग) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति काम करते समय अत्यधिक सफाई रखेंगे ।

(घ) प्रबंधक प्रसंस्करण तथा पैकिंग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को साफ किये हुए एप्रन तथा टोपियां देगें ।

(ङ) कर्मचारी, जब भी आवश्यक है, और विशेष रूप से प्रत्येक अनुपस्थित के पश्चात्, प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व, अपने हाथ तथा पैर पेय जल तथा साबुन से धोयेगा ।

(च) परिसरों में थूकना तथा किसी भी रूप में तम्बाकू का प्रयोग निषिद्ध होगा ।

(छ) भोजन करने के लिए अलग से किसी स्थान की व्यवस्था की जाएगी तथा अन्य स्थानों पर भोजन करना निषिद्ध होगा ।

12. परिवहन सुविधाएं :—

(क) सबसे अच्छा तो यह है कि कच्चा माल तथा तैयार माल केवल विद्युत रोधी या प्रशीतित वाहनों में ले जाया जाए। तैयार माल किसी भी दशा में, गैर विद्युत रोधी वाहनों में नहीं ले जाया जाएगा ।

13. अभिलेख का रखा जाना

मेंढक की टांगों के प्रसंस्करण का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण कर्ता परिषद द्वारा समय-समय पर यथा विहित अभिलेखा तथा रजिस्टर रखेगा। यह अभिलेख अभिकरण या परिषद् के अधिकारियों को, यथा पेक्षित रूप में उपलब्ध किया जाएगा ।

(ख) मेंढक की टांगों के प्रसंस्करण एककों अथवा कटिंग केन्द्रों का अनुमोदन

(1) (क) निर्यात करने के लिए मेंढक की टांगों का प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रसंस्करण कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में, परिषद द्वारा विहित प्रोफार्मे में, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को देगा ।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी प्रसंस्करण एकक या कटिंग केन्द्रों में यह देखने के लिए जाएंगे कि एकक में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं ।

(ग) यदि ये पाया जाता है कि एकक में वे न्यूनतम सुविधाएं जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं विद्यमान हैं तो अभिकरण एकक अनुमोदित कर देगा तथा उसे निर्यात के लिए मेंढक की टांगों का प्रसंस्करण संबंधी कार्य करने की आज्ञा दे देगा ।

(घ) यदि यह पाया जाता है कि एकक में न्यूनतम सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं तो प्रसंस्करण कर्ता को निर्यात के लिए मेंढक की टांगों के प्रसंस्करण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

2. (क) प्रसंस्करण कर्ता को दिया गया अनुमोदन कम से कम सात दिन की सूचना देने के बाद, निम्नलिखित कारणों से वापिस लिया जा सकेगा,—

(i) यदि उपकरण, मशीनें और भंडारकरण की सुविधाएं अच्छी कार्यकरण दशा में नहीं है ।

(ii) यदि एकक की स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है;

(iii) यदि प्रति जांच के लिए लिये गए नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं;

(iv) यदि प्रसंस्करण कर्ता ने इन नियमों के उपबंधों या समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है या जानबूझ कर उल्लंघन करने का प्रयत्न किया है । अनुमोदन की ऐसी वापसी प्रसंस्करण कर्ता को लिखित रूप में सूचित की जाएगी ।

(3) (क) यदि प्रसंस्करण कर्ता अनुमोदन को वापिस लेने के विनिश्चय से व्यथित है तो वह नियम 5 में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा ऐसे मामले में उसे प्रसंस्करण जारी रखने की अनुमति होगी ।

(ख) यदि विशेषज्ञों के उक्त पैनल का विनिश्चय प्रतिकूल होता है तो प्रसंस्करण कर्ता निर्यातकर्ता को मध्यवर्ती अवधि के दौरान सम्पूर्ण प्रसंस्कृत माल निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(4) जिस एकक का अनुमोदन वापिस ले लिया गया है, वह कमियों को दूर करने के पश्चात् अभिकरण से पुनः अनुमोदित करने के लिये पुनः आवेदन कर सकेगा ।

(5) (क) यदि किसी भी समय किसी कारणवश उत्पाद को विनिर्देशों के अनुरुप बनाए रखने में कठिनाई होती है, या किसी कारणवश अभिकरण ने यह निर्देश दिया है कि निर्यात के लिये उत्पादन निलम्बित कर दिया जाए तो, अभिकरण को सूचित करते हुए, निर्यात के लिए प्रसंस्करण निलम्बित कर दिया जाएगा ।

(ख) निर्यात के लिए प्रसंस्करण तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब उसके लिये अभिकरण लिखित रूप में अनुमोदन दे दे ।

(ग) प्रसंस्करण

(1) प्रसंस्करण कर्ता सक्षम कर्मचारियों के निरीक्षण में ही अनुमोदित एककों में प्रसंस्करण करेगा ।

(2) (क) प्रसंस्करण संयंत्रों को पहुँचाने वाली मेंढक की कटी हुई टांगों को प्रसंस्करण के लिए कच्ची सामग्री माना जाएगा । मेंढक की टांगों का प्रसंस्करण उन्हीं एककों में अनुमोदित किया जा सकता है जो कि पहले से ही आई० पी० ओ० सी० योजना के अन्तर्गत मछली तथा मछली से बने उत्पादों के लिए अनुमोदित हैं ।

(ख) प्रसंस्करण एकक में आने वाले कच्चे माल का निरीक्षण, उसकी मात्रा, क्वालिटी तथा उसमें विजातीय पदार्थ के लिये किया जाएगा और संप्रेक्षणों को समय-समय पर परिषद् द्वारा विहित रीत से अभिलिखित किया जाएगा ।

(ग) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसंस्करण के लिए ताजा और अच्छा कच्चा माल ही प्रयोग में लाया जाएगा ।

(3) कच्चे माल का चयन और निर्यात होने तक उसका पश्चात्-वर्ती प्रसंस्करण पैकिंग और भंडारकरण समय-समय पर अभिकरण के अधिकारियों द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार सक्षम कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(4) (क) पूर्वोक्त संक्रियाओं की जब भी आवश्यकता हो अभिकरण के अधिकारी आगे भी जांच कर सकेंगे ।

(ख) प्रसंस्करण या पैकिंग पर उस सामग्री को, जिसका अनुमोदन अभिकरण के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है यथास्थिति प्रसंस्करण परिसर से हटा दी जाएगी या उसकी कमियां दूर कर दी जाएंगी ।

(ग) अस्वीकृत सामग्री का निपटान अभिकरण के समाधानप्रद ढंग से किया जाएगा ।

(5) विलंब की दशा में, संबंधित कच्ची सामग्री या तो बर्फ की पर्याप्त मात्रा में रखी जाएगी या उसका प्रसंस्करण अलग से पहचान टैग या चिन्ह के साथ किया जाएगा तथा अन्तिम निपटान के लिए अलग रख दी जाएगी, जिसका विनिश्चय अभिकरण के अधिकारियों के पैनल द्वारा किया जाएगा।

(6) मेंढक की टांगों का प्रसंस्करण नीचे विनिर्दिष्ट ढंग से किया जाएगा :—

(क) जीवित मेंढक की पीछे की टांगे कमर से अधिक से अधिक 2.5 से 3 से० मी० दूरी पर उदर से काटी जाएंगी।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाचक नाल का कोई भी हिस्सा टांगों से स्पर्श न करे।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि काटी गई पिछली टांगों से उचित रूप में रक्त प्रवाह हो तथा उनमें अंदर रक्त जमाव न हो, उन्हें 15 मिन्ट के लिए 20 पी० पी० एम० क्लोरीन युक्त 5 शीतल लवण जल में डुबोया जाएगा।

(घ) शीतित लवण जल नियत अंतराल पर बदल दिया जाएगा।

(ङ) सामग्री को ताजे पेय जल में तीन बार धोया जाएगा तथा 500 पी० पी० एस० क्लोरीन वाले 5% लवण जल में 15 मिन्ट के लिए डुबोया जाएगा।

(च) इसके पश्चात टांगों को अच्छी क्वालिटी वाली बर्फ की पर्याप्त मात्रा में पैक किया जाएगा।

(छ) टांगे कतरी जाएंगी फिर ताजे पेय जल में अच्छी तरह से धोई जाएंगी।

(ज) धुलाई के पश्चात् सामग्री को 500 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले सोडियम क्लोराइड के घोल में पन्द्रह मिन्ट तक डुबोया जाएगा, उसकी त्वचा उतार ली जाएगी और शिराओं को (काटे गए सिरे से बड़ी रक्त नलिकाओं को खींच कर या घुटने के जोड़ पर मौस में छेद करके नलिका को बाहर निकाल कर) अलग कर लिया जाएगा, उस सामग्री को धोया जाएगा श्रेणीकृत किया जाएगा तथा उसके पहले कि सामग्री का और आगे प्रसंस्करण किया जाए, उसे 20 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले ताजे पेय जल से पांच बार अन्तिम रूप से धोया जाएगा।

(झ) टांगों को पहले से ही 5 मिनट के लिए 20 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले पेय जल में डुबोये हुए पालिएथीन अथवा किसी अन्य उचित आर्द्रता सह्य पेपर में लपेटा जाएगा।

(ञ) (क) प्रशीतन के लिए सामग्री लादने में विलम्ब होने की दशा में बिना लपेटी हुई टांगे को, कीटाणु नष्ट हुई अच्छी बर्फ की उचित मात्रा के साथ-साथ 20 पी० पी० एम० क्लोरीन युक्त पानी वाले डिब्बे में रख दी जाएगी।

(ख) इस प्रकार परिरक्षित सामग्री अस्थायी रूप से एक शीतित कमरे में रखी जाएगी।

(ग) टांगें 40 सें० या इससे कम पर शीघ्र प्रशीतित की जाएंगी तथा 18° सें० अथवा कम तापमान वाले शीतागारों में तुरन्त भेज दी जाएंगी।

(ट) निरीक्षण की प्रक्रिया

(i) (क) इन नियमों के अधीन निरीक्षण के प्रयोजन के लिये एक दिन का उत्पादन एक नियंत्रण एकक होगा।

(ख) एक नियंत्रण एकक में उत्पाद के प्रकारों पर निर्भर कर हुए कई उपएकक हो सकते हैं।

(ग) नमूने, परिषद द्वारा अभिकथित अनुदेशों के अनुसार कच्चा माल प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों और अन्तिम उत्पाद में से लिए जाएंगे।

(घ) वह लाट जो अभिकथित मानकों के अनुरूप होंगे अनुमोदित लाट माने जाएंगे।

(2) मेंढक की प्रशीतित टांगों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात कर्ता परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणा पत्र देगा कि मेंढक की प्रशीतित टांगों के परेषण का प्रसंस्करण इस संबंध में विहित प्रसंस्करण के दौरान क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करके किया गया है और यह परेषण अनुमोदित लाट में से लिया गया है।

(3) ऐसी सूचना प्रसंस्करण परिसर से परेषण के पोतलदान के लिए भेजे जाने की तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व अभिकरण के कार्यालय को पहुंच जानी चाहिए।

(4) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण सामान्यतः केवल जैव-तात्विक परीक्षणों के लिये नमूने लेगा और यदि अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण अधिसूचित मानकों के अनुरूप है और यदि खंड ग(4) के अनुसार अभिलिखित नियमित जांच के परिणाम संतोषजनक है तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के भीतर परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए निर्यातकर्ता को प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिलिखित जांच के परिणामों के आधार पर ऐसा करना उचित है या अभिकरण यह समझता है कि और विस्तृत जांच आवश्यक है तो अभिकरण द्वारा निर्धारित रूप में जीवाणु विज्ञान संबंधी परीक्षण सहित विस्तृत परीक्षण के लिये परेषण में से अतिरिक्त नमूने लिये जाएंगे। ऐसे मामलों में निर्यात योग्य होने के प्रमाण-पत्र केवल परीक्षणों के समाधान-प्रद रूप में पूरा होने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

(6) जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और उसकी सूचना इंकार के कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता को देगा।

(7) नियंत्रण एकक या उप-एकक की जो मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है अस्वीकृत तथा निपटान के ढंग से संबंधित सूचना देने वाला एक पृथक अभिलेखा रखा जाएगा।

(8) (क) निरीक्षण के प्रयोजन के लिये अभिकरण के अधिकारियों को सुसंगत अभिलेखों और परिसर तक जहां मेंढक की प्रशीतित टांगों का प्रसंस्करण पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है पहुंच प्राप्त होगी।

(ख) प्रसंस्करणकर्ता प्रसंस्करण क्षेत्र के पार्श्व में आवश्यक सुविधाओं सहित एक पृथक निरीक्षण कक्ष की व्यवस्था करेगा।

(9) (क) प्रमाणन के पश्चात् भी अभिकरण को शीतागार में अभिवहन में या पतलों पर परेषण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(ख) मूलतः जारी किया गया प्रमाणपत्र इस में से किसी भी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में वापस ले लिया जाएगा।

(ग) निरीक्षण फीस—निर्यातकर्ता अभिकरण को प्रति किलो ग्राम या उसके किसी भाग के लिए 20 पैसे की दर से निरीक्षण फीस देगा। किन्तु किसी एक परेषण के लिये यह फीस 30 रुपये से कम नहीं होगी।

(5) अपील

(1) नियम 3 के खंड (ख) (I) के अधीन अपने एकक के लिये अनुमोदित किये जाने से नियम 3 के खंड घ (2) के अधीन प्राप्त अनुमोदन के वापिस ले लिये जाने से या नियम 3 के खंड घ के अधीन निर्यात योग्यता का प्रमाणपत्र जारी न किये जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार या वापसी की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपाबंध II

मेंढक की प्रशीतित टांगों के लिए विनिर्देश

1. मेंढक की टांगे दो प्रकार की होंगी : (1) सफेद या हाथी दांत जैसी जिसके अन्तर्गत हल्की गुलाबी तथा हल्की भूरी भी है (2) हल्की नीली।

2. मेंढक की टांगे अलग-अलग या तो पालिथिन फिल्म या अन्य उपयुक्त आवरण में लपेटी हुई होंगी या फिर ब्लाकों में प्रशीतित होंगी।

3. मेंढक की टांगें त्वचा तथा बाह्य पदार्थों से पूर्णतः युक्त होंगी। किनारे अच्छी प्रकार से कटे हुए होंगे तथा रक्त जमाव तथा अपवर्णन से युक्तियुक्त रूप से मुक्त होंगे।

4. मेंढक की टांगों से उनके खराब होने का कोई चिन्ह प्रकट न हो तथा गलाने पर उनमें से कोई गंदी अधिक क्लोरीन की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकी बनावट नर्म तथा मजबूत होगी।

5. किसी भी डिब्बे में पैक की गई मेंढक की टांगों का भार घोषित भार से कम नहीं होना चाहिए।

6. डिब्बे में पैक की गई मेंढक की टांगे माप में एक समान होगी तथा मापसंख्या घोषित माप श्रेणी के अनुरूप होगी।

7. मेंढक की टांगों की सूक्ष्म जैविक अपेक्षाएं ऐसी होगी जैसी नीचे विहित की गई हैं :—

(i) कुल जीवाणु की संख्या 37 सी प्रति ग्राम अधिकतम	5,00,000
(ii) ई० कायल प्रति ग्राम सं० अधिकतम	10
(iii) सेलमोनला तथा एरिजोना	—
(iv) पाजिटव के लेज स्टेफी लोकेकसी प्रति ग्राम अधिकतम	100

संकेतन

(i) प्रशीतित स्लेबों की दशा में प्रशीतित मेंढक की टांगों के स्लेबों में एक संकेत पर्ची लगी होगी तथा अलग-अलग सदयः प्रशीतन की दशा में संकेत पर्ची डिब्बों के भीतर रखी जाएगी संक्षेप में संकेत पर्ची बनाने के लिये एक दृष्टांत नीचे दिया है :—

'एक्स०बाई०एफ०ई०एल०

9 ए 05

उक्त दृष्टांत में —

एक्स०बाई–प्रसंस्करण कर्ता का संकेत नाम

एफ०ई०एल० मेंढक की प्रशीतित टांगें।

9 प्रसंस्करण का वर्ष (यहां यह 1979 वर्ष सूचित करता है)

ए प्रसंस्करण का मास (यहां यह जनवरी मास सूचित करता है)

05 प्रसंस्करण की तारीख (यहां यह मास का पांचवां दिन सूचित करता है)

(ii) निम्नलिखित संक्षेपाकार वर्ष के मास सूचित करने के लिये प्रयोग किये जाएंगे।

मास	संक्षेपाकार
जनवरी	क
फरवरी	ख
मार्च	ग
अप्रैल	घ
मई	ङ
जून	च
जुलाई	छ
अगस्त	ज
सितम्बर	झ
अक्तूबर	ञ
नवम्बर	ट
दिसम्बर	ठ

[सं० 6(10)/77-नि०नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० फुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 1890.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export of Frozen Froglegs (Inspection) Rules, 1965, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Frozen Froglegs (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act, at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras.

(c) "frozen froglegs" means all type of frozen froglegs or frogmeat obtained from edible frogs such as—

(i) rana tigrina

(ii) rana hexadactyla; and

(iii) rana crassa.

(d) "standard specification" means the specfications of frozen froglegs laid down in Annexure-II to this order.

3. "QUALITY CONTROL

A. Requirements of processing units

Only those of the processing units approved by the agency shall be eligible for processing frozen froglegs for export. (The units approved for processing of fish and fishery products shall also be allowed to process froglegs for export). A unit to quality for such approval shall have the minimum facilities as specified below :—

1. Surroundings, construction and lay out :

(a) The surroundings of the processing unit which are under the physical control of the processor shall not have any swamps, dumps, of animal housings nearby, which might pose any sanitary problems.

(b) All the immediate approaches of the processing area which are under the physical control of the processor shall be concreted or tarred or turfed to prevent wind-blown dust.

(c) The processing unit shall be housed in a building of permanent nature affording sufficient protection from normal elimate hazards like wind-blown dust and rain.

(d) The lay out of the different sections shall be arranged in such a way as to facilitate the smooth flow of work and to prevent possible contamination from preprocessing section.

2. Processing areas'

(a) The area in which the raw material is received and stored shall be so separated from the area in which the final product preparations or packing is conducted so as to preclude contamination of the finished product.

(b) Areas and compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for inedible materials.

(c) The material handling areas shall be completely separated from the area used for residential purposes.

(d) It must be ensured that the cut legs are transported to the processing unit in absolute hygienic conditions and in as short time as possible from the time of cutting.

(e) The cutting centre shall be subject to the same sanitary requirements as the processing unit.

(f) A regular cleaning schedule shall be followed to ensure good sanitary and hygienic condition.

3. Ceiling, Wall and floor

(a) The ceiling of the room where the material is either processed for stored, shall be free from crevices, open joints and lend itself for easy cleaning.

(b) The ceiling shall not offer any facility for rodent harbourages.

(c) The walls of the processing area shall be smooth and free from pits and cracks and shall be washable upto a height of min. 1.3 metres.

(d) The floor shall be of impermeable and non-corroding materials and shall have sufficient sloping to drain away all the waste water.

(e) The floor and wall junctions may be rounded off to facilitate easy cleaning.

4. Fly proofing, vormin and animal control :

(a) The processing area shall be provided with effective flyproofing arrangements.

(b) Measures shall be adopted to protect against the entry of other insects, rodents, birds, cats, dogs and the like into the processing areas.

5. Lighting and ventilation :

(a) All the working areas shall be well lighted.

(b) Light bulbs and fixtures should not be directly suspended over the processing table or any stage of the preparation of the product. These shall be of safety type to prevent contamination in the event of breakage.

(c) There shall be adequate facilities for natural or mechnical ventilation system to provide fresh air, remove undesirable odours, steam and smoke and prevent condensation in rooms where work is performed.

6. Working tables and utensils :

(a) The tables used for processing work shall be of non-corrodible, non-reacting material other than wood.

(b) The processing tabes shall be constructed and installed in such a way that the areas underneath and around are accessible to easy cleaning.

(c) The table tops shall be of stainless steel, aluminium, or rust free G.I. sheets and shall be smooth and free from pits and crevices.

(d) The arrangements of working tables shall be such that smooth flow of work is ensured.

(e) All receptacles like trays, tanks, vats and utensils used for the processing shall be of non-corrodible materials other than wood. These shall have smooth surfaces free from crevices. Use of wire-mesh receptacles may be permitted provided these are not rusted.

(f) Enamelled utensils shall not be used.

(g) Bamboo backets when used may be permitted in areas other than processing hall.

(h) The equipments and utensils used for inedible and cibtaminated materials shall be separately identifiable by a mark or shape or colour so that these are not used for handling edible products.

(i) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operation and adequate waste receptacles shall be provided for this purpose.

7. Machinery :

(a) The freezing capacity shall be adequate to meet the production in peak season. However, spare capacity of other approved processing units may be utilised provided the onus of responsibility for such freezing will be that of the processor/exporter.

(b) The type of freezing employed shall be specific to the nature of the product and type of pack. For this purpose, either the plate freezer or the blast freezer may be used depending upon the requirement of product.

(c) The material shall be either individually quick frozen (IQF) or frozen in blocks to attain a temperature of—40°C within approx. 3-1/2 hrs. period.

(d) The freezing equipment shall be fitted with gauges to show the temperature.

8. Cold storage and warehousing :

(a) The location and design of the cold stores should be such that it is integrated into the general lay out of the whole establishment and its operation incorporated into the flow pattern of the overall operation.

(b) Every freezing unit shall have cold storage of adequate capacity. However, common facility cold storage may be utilised subject to the following conditions :

(i) the maintenance of proper temperature;

(ii) transporation by insulated trucks; and

(iii) stacking of cartons in an identifiable manner.

(c) The ideal temperature of the cold storage shall be —18°C or less preferably fitted with automatic temperature recording device. The product temperature should, however, be —16°C at any time of checking.

(d) In the absence of continuous recording thermometer, the temperature of the cold storage shall be measure at least every 4 hours and suitable records maintained.

(e) The cold storage shall be well lighted and shall have suitable arrangement on the floods and sides to facilitate free circulation of air.

(f) The entry into the cold storage should be so designed that on opening the entry door, the temperature shall not rise appreciably, as otherwise it would affect the stored product.

(g) An ante-room of suitable size shall invariably be provided. However, where air curtain with automatic switch-on device is provided the provision of ante-room would not be required.

(h) The cooling surfaces of the cold storage should be regularly defrosted in order to avoid excessive build up to ice or frost, which could seriously affect the efficiency of the cooling system.

(i) During defrosting operation, care shall be taken to prevent any frost, ice or melt water falling on the stored product.

(j) There shall be an efficient alarm system to render timely help to persons trapped inside.

(k) The cold storage shall be subject to the same sanitary requirements as in other material handling establishments.

(l) For this purpose, a regular cleaning schedule shall be maintained to ensure good hygienic conditions.

(m) In the units where the raw material has to be stored overnight for want of adequate processing facilities, a chill room of suitable size, maintained at a temperature of -/-1°C or less, shall be provided. However, in the units where chill room facility is not available, the material shall be permited to be stored overnight, adequately iced.

(n) All detergents and disinfectants shall be stored separately.

(o) There shall be separate facility for storing packaging materials.

(p) Toxic substance such as rodenticides, fumigants, insecticides or other substances injurious to health except fire fighting, equipments, shall be kept in a separate locked room.

(q) Water and Ice.

(a) There shall be plentiful supply of potable water (free from harmful chemical and bacteria).

(b) If the water used for processing is from sources other than a protected water supply scheme, a certificate of potability of the same from Export Inspection Agency or other institutions approved by Export Inspection Agency shall be produced.

(c) If non-potable water is supplied for boiler and other auxiliary services there shall be no cross-connection between the auxiliary water system and the system carrying potable water.

(d) The storage tanks, if used, shall be sufficiently protected from extraneous contamination, and shall be of sufficient capacity.

(e) The storage tanks shall be preperly cleaned at least once in six months.

(f) The consumption of potable water shall not be less than 12 liters for every kilogram of raw material processed.

(g) The minimum available chlorine content in water used for processing shall be maintained at 3 ppm. level.

(h) The water used for glazing and re-glazing shall be chlorinated to a level of 10 ppm.

(i) Ice made from potable water only shall be used.

(j) If ice from external sources is used, it shall be ensured that the same is made from potable water and is not contaminated.

(k) Ice crushing machine, if used, shall be kept in good sanitary conditions.

10. Sanitary facilities and control

(i) Cleaning :

(a) All the utensils, trays and table surfaces, which in contact with the material except packaged material shall be washed initially with a cleansing agent and finally with water having a minimum concentration of 50 ppm. chlorine.

(b) The porcessing hall shall be cleaned before the day work starts and then at the end of each workink shift.

(c) In addition the cleaning and washing shall be done as frequently as necessary.

(ii) Washing facility :

(a) Soap and adequate hand washing facilities shall be provided in each processing hall near the entrance.

(b) Arrangements to sanitise the feet shall also be made near the entrances.

(iii) Sewag and waste disposal :

(a) There shall be adequate drainage facilities for water used in the processing premises and to discharge it into a channel at least 3 metres from the unit.

(b) The drainage system inside the factory shall be properly covered and easily cleanable.

(c) The openings of the open drains which pass through walls shall be fitted with metal grills to prevent the entry of rodents.

(d) The arrangements for disposal of sewage, waste water and offal shall be such that it shall not cause any sanitary problem to the unit and the neighbourhood.

(e) The sewage from the toilet shall be disposed of in such a manner that the water shall not be accessible to flies and the unit's water supply not contaminated.

(f) On no account there shall be accumulation of water including waste or rain water in the premises.

(iv) Toilet facility :

(a) Adequate toilet failities of sanitary type shall be provided as per legal requirements applicable in this regard.

(b) The toilets shall be well isolated from the processing area and shall be provided with self-closing doors, wash basin and soap.

(c) Potable water shall be made available for a washing purposes.

11. Personal health and hygiene :

(a) Plant management shall take care to ensure that no person, while known to be aflected with a communicable disease, is permitted to work in area where the product is handled.

(b) In order to facilitate the detection of such disease, the management shall conduct at least yearly medical examination of the personnel working in the food handling areas of the unit.

(c) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(d) The management shall provide sanitised uprons and head-gears to the employees working in the processing and packing areas.

(e) The workers shall wash their hands and feet with potable water often as necessary and specially before entering the processing hall after each absence.

(f) Spitting and use of tabacco in any form shall be prohibited in the processing premises.

(g) A separate eating place shall be provided and eating at other places shall be prohibited.

12. Transportation facilities :

(a) It is ideal that the raw material and also the finished product are transported only insulated or refrigerated vehicles.

(b) Under no circumstances finished products shall be transported in non-insulated vehicles.

13. Maintenance of records :

Necessary registers and records, as prescribed by the Council from time to time, shall be maintained by the processor in order to ensure effective control on the processing of froglegs and these shall be made available to the Council or Agency officers as and when required.

B. APPROVAL OF PROCESSING UNITS OR CUTTING CENTRES OF FROGLEGS

1. (a) A processor intending to process froglegs for export shall inform his intention to do so in writing in the proforma prescribed by the Council to the nearest office of the Agency.

(b) On receipt of such information, the agency officers shall visit the processing unit or cutting centre in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(c) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in those rules, the agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of froglegs for export.

(d) If the unit is found not to have the minimum facilities, the processor shall not be allowed to process froglegs for export.

(2) (a) The approval accorded may be withdrawn in respect of a processor for the following reasons, after giving a notice of minimum period of seven days:—

(i) if the equipments, machinery and storage facilities are not in good working condition;

(ii) if the sanitary and hygienic conditions of the unit are not satisfactory;

(iii) if samples drawn for counter checks fail to meet the laid down standards;

(iv) if the processor has violated or deliberately attempted to violate the provisions of these rules or instructions issued from time to time. Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(3) (a) If the processor is aggrieved by the decision to withdraw the approval, he may file an appeal before the panel of experts referred to in rule 5. In such cases, he shall be allowed to continue processing.

(b) In the event of an adverse decision by the said panel of exports, the processor/exporter shall not be allowed to export the entire material processed during the intervening period.

(4) A unit whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects, make a fresh application to the agency for getting fresh approval.

(5) (a) If at any time there is any difficulty in maintaing the conformity of the products to the specification, for any reason or if directed by the agency to suspend production for export, for any reason shall be suspended under intimation to the agency.

(b) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the agency in writing.

C. PROCESSING

(1) The processor shall carry out processing only in approval units under the supervision of competent personnel,

(2) (a) Cut froglegs arriving at the processing plants could be treated as the raw materials for processing. Processing of forglegs could be allowed in the same units which were already approved under I.P.Q.C. scheme for fish and fishery products.

(b) The raw material arriving in the processing unit shall be inspected for its quantity, qality and foreign matter, and the observations recorded in the manner prescribed by the Council from time to time.

(c) It shall be ensured that only fresh and wholesome raw materials are used processings.

(3) The selection of raw material and its subseqent processing, packing and storage till export shall be carried out under the supervision of competent personnel as per directives given by the agency officers from time to time.

(4) (a) The aforesaid operations shall be subject to further check by the Agency officers as often as found necessary,

(b) The material at any stage of processing or packing not approved by the agency officers, shall be removed from the processing premises or defects rectified, as the case may be.

(c) The rejected material shall be disposed of in a way satisfactory to the agency.

(5) In case of dispute, the concerned raw material shall be either kept adequately iced or processed with a separate identity tag or mark and kept separately for final dispoeal which shall be decided by the Panel of officers of the Agency.

(6) Processing of froglegs shall be carried out in the manner as specified below:—

(a) The hind-legs shall be carried out from live frogs at the abdomen not more than 2.5 to 3 cm. from the waist.

(b) It shall be ensured that no portion of the elimentary tract comes in contact with the legs.

(c) The chopped hind-legs shall be dipped in 5 percent chilled brine containing 20 ppm chlorine for 15 minutes in order to ensure proper bleeding and to prevent the clotting of blood inside.

(d) The chilled brine shall be changed at ferquent intervals.

(e) The material shall be then washed thrice in fresh potable water and the dipped in 5 percent brine containing 500 ppm available cholrine for 15 minutes.

(f) After that the legs shall be packed properly in sufficient quantity of good quality ice.

(g) The legs shall be trimmed and then properly washed in fresh potable water.

(h) After washing, the material shall be dipped in 5 percent sodium chloride solution containing 500 ppm available chlorine for 15 minutes, skinned, deveined (by pulling out the large blood vessels from the cut-end or by piercing the flesh at the knee joint and then pulling out the vessel), washed, graded and then finally washed five times with fresh potable water containing 20 ppm chlorine before the material goes for further processing.

(i) Legs shall be wrapped in polyethene or any other suitable moisture-proof paper already dipped is potable water containing 20 ppm chlorine for 5 minutes.

(j) In the case of delay in loading the material for freezing the unwrapped legs shall be transferred to a container containing water with 20ppm available chlorine along with suitable quantity of bacterologically sound ice.

(b) The material thus preserved shall be temporarily kept in a chill room,

(c) The legs shall be quick-frozen at or below-40° and be transferred immediately to a cold storage maintained at or below 10° C.

D PROCEDURE OF INSPECTION.

(i) (a) For the purpose of inspection under these rules, a day's production shall constitute a control unit.

(b) A control unit may have more sub-units depending upon the species of the product.

(c) Samples shall be drawn from raw-material, different processing stages and the final product in accordance with the instructions laid down by the Council.

(d) Those of the lots which meet the laid down standards shall be treated as approved lot.

(2) An exporter intending to export a consignment of frozen froglegs shall give intimation to the agency in writing in the proforma prescribed by the Council and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignment of frozen frog legs has been processed exercising the inprocess quality control measures as prescribed in this regard and from the approved lot.

(3) Such intimation shall reach the agency office not less than three working days' prior to the date of despatch or the consignment from the processing premises for shipment.

(4) On receipt of such intimation, the agency shall normally draw samples for organoleptic tests only, and if the agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the notified standards and if the results of recorded regular checks satisfied that the consignment to be exported complies with the three working days' of receipt of such intimation, issue a certificate to the exporter declaring the consignment export-worthy.

(5) In case the results of the recorded checks so warrant, or if the agency feels that further detailed checks are necessary, additional samples, as decided by the agency, shall be drawn from the consignment for detailed testing including bacteriology, and in such case the certificate of export worthiness shall be issued only after satisfactory completion of the test.

(6) Where the agency is not so satisfied, it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter along with the reasons therefor.

(7) Aseparate record shall be maintained giving information relating to the rejection and mode of disposal of the control units or sub-units which do not conform to the standard specifications.

(8) (a) For the purposes of inspection, the agency officers shall have access to the relevant records and premises where processing, packing and storage of frozen froglegs are carried out.

(b) The processor shall provide a separate inspection room with necessary facilities adjacent to the processing area.

(9) (a) Subsequent to certification, the agency shall have the right to reassess the quality of the consignment in the cold storage in transit or at the ports.

(b) In the event of the consignment being found not confirming to the standard specifications at any of these stages, the certificate originally issued shall be withdrawn.

(c) INSPECTION FEE : Subject to a minimum of Rs.304 for each consignment, a fee at the rate of 20 ps per kg. or part thereof shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

5. APPEAL.

(1) Any person aggrieved by the agency to accord approval for his unit under clause B (1) of rule 3, or withdrawal of approval accorded uner clause B (2) of rule 3, or to issue a certificate of exportworthiness under clause D (6) of rule 3, may within ten days of receipt of the communication of such refusal or withdrawal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three, but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Govt.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel of experts shall consists of non-officials.

(3) The quoram of the panel shall be three

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

ANNEXURE-II

SPECIFICATION FOR FROZEN FROGLEGS

1. The froglegs shall be of two types, namely, (1) white or ivory white including light pink and light brown.

(2) Blaish white.

2. The froglegs shall be either wraped individually in polythene film or other suitable covering or frozen in blocks.

3. The froglegs shall be completely free from skin and any foreign matter; shall be well trimmed, and be reasonabley free from blood-cloths and discolouration.

4. The froglegs shall not show any signs or spoilage and shall not have any off or excessive chlorine odour when thawed. These shall have a soft and firm texture.

5. The weight of the froglegs packed in any given container shall be not less than the declared weight.

6. The froglegs packed in a container shall be uniform in size and the size count shall confirm to the declared size-grade.

7. The microbiological requirements of the froglegs shall be as prescribed herender:—

Total bacterial count

Total bacterial count at 37 C per gram, Max	5,00,000
E. coil, count per gram, Max	10
Salmonella and Arizona	
Coagulase positive	—
Staphylococus per gram, Max	100

CODING

(i) A code slip shall be embedded in the slabs of frozen froglegs in the case of frozen slabs, and the code slip placed in the primary container in the case of individual quick frozened. An illustration for making the code slip in the abbreviated form is given below :—

'XYFEL

9 AO 5

Where in the above illustration—

XY—name of processor in code FEL.—Frozen frog legs 9—year of processing (here it represents the year 1979) A month of processing (here it represents January) 05—date of processing (here it represents 5th day of the month).

The following abbreviations shall be used to indicate the months of the years :—

Months	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	I
October	J
November	K
December	L

[No. 6(10)/77-EI&EP]

C. B. KUKRATI, Jt. Director

(समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियंत्रण)

नई दिल्ली, 9 मई, 1979

का० आ० 1891.—का० आ० सं० 387 दिनांक 25-1-1979 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नोक्त संशोधन किए जाते हैं :—

के स्थान पर	पढ़ें
मद सं० 9 उप सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।	श्री एस० रामास्वामी, विकास अधिकारी (एस जी), तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।

[सं० 1/एम० 16/78-ई० पी० एप्री-5]

टी० आर० नागाराजन, उप निदेशक

(Marine Products Industry Development Control)

New Delhi, the 9th May, 1979

S.O. 1891.—In the Notification issued under S.O. No. 387 dated 25-1-1979, the following amendments are made by Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972) read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972

FOR	READ
S. No. 9 Deputy Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry, New Delhi.	Shri S. Ramaswamy Development Officer (S.G.) Directorate of Technical Development, New Delhi.

[No. 1/M-16/78-FP (Agri-V)]

T. R. NAGARAJAN, Dy. Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1979

का० आ० 1892.—सर्वश्री परफेक्ट सर्किल विक्टर्स लि० प्लाट नं० 20 एम०आई०डी०सी० एरिया, सतपुर नासिक को आई डी ए साख के अन्तर्गत 5,90,604 रुपये के टिन प्लेट वेस्ट/वेस्ट का आयात करने के लिए दिनांक 6-3-76 को आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1416721/आर/आई एन/58/एच/41-42 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल (सीमा-शुल्क/मुद्रा नियंत्रण प्रति) लाइसेंस सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाने के बाद खो गया था अस्थानस्थ हो गया है। लाइसेंसधारी ने आगे यह कहा है कि लाइसेंस में 1,46,086 रुपये की अप्रयुक्त धन राशि शेष थी।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से सन्तुष्ट है कि मूल लाइसेंस सं० पी/डी/1416721 दिनांक 6-3-76 खो गया या अस्थानस्थ हो गया है और इसलिए निदेश देता हूं कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल लाइसेंस एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4. लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मि० सं० आटो/पी-6 (1)/ए एम 76/आर एम-4]

सी० एस० आर्य, उप मुख्य नियंत्रक

कृते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Import and Exports)

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1979

S.O. 1892.—M/s. Perfect Circle Victors Ltd., Plot No. 20, M.I.D.C. Area, Satpur, Nasik were granted import licence No. P/D/1416721/R/IN/58/H|41.42 dated 6-3-1976 for import of Tin Plate Waste/Waste valued at Rs. 5,90,604/- under I.D.A. credit.

2. They heve requested for issue of duplicate licence on the ground that the original (Customs/Exchange Control, copies) have been lost or misplaced after having been registered with the Customs Authorities. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilised balance of Rs. 1,46,086/-.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original licence No. P/D/1416721 dated 6-3-1976 has been lost or misplaced and hence directs that duplicate Customs/Exchange Control Purposes Copies of the said licence should be issued to the applicant. The original licence is hereby cancelled.

4. The duplicate licence is being issued separately.

[File No. Auto/P-6(1),'AM 76/RM-4]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller

for Chief Controller of Imports and Exports.

नई दिल्ली, 9 जून, 1979

शुद्धिपत्र

का०आ० 1893.—भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 25 नवम्बर, 1978 के पृष्ठ 3165 से 3169 तक पर प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, सिविल पूर्ति व सहकारिता की अधिसूचना सं० का०आ० 3348, तारीख 25 नवम्बर, 1978 की सारणी के स्तम्भ (2) की प्रविष्टियों में—

(1) पृष्ठ 3165 पर—

(क) स्तम्भ (1) में क्रम सं० 1 के सामने,—

(i) मद (1) में, "राजगहरिया" के स्थान पर "राजगरहिआ" पढ़ें;

(ii) मद (5) में, "उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)," के स्थान पर, "उपनिदेशक (निर्यात संवर्धन), पदेन" पढ़ें ।

(ख) स्तम्भ (1) में क्रम सं० 2 के सामने—

(i) मद (5) में, "श्याम सुन्दर बगारिया" के स्थान पर "श्री श्याम सुन्दर बगारिया" पढ़ें ।

(2) पृष्ठ 3166 पर,—

(क) स्तम्भ (1) में क्रम सं० 3 के सामने,—

(i) मद (1) में, "भण्डारी" के स्थान पर, "भवानी" पढ़ें ।

(ii) मद (6) में, "पदेन", के स्थान पर, "पदेन", निर्यात निरीक्षण परिषद्" पढ़ें ।

(ख) स्तम्भ (1) में क्रम सं० 4 के सामने,—

मद (7) में, "सदस्य" के स्थान पर "संयोजक" पढ़ें ।

(ग) स्तम्भ (1) में क्रम सं० 5 के सामने,—

मद (2) में, "डी राजगरहिया" के स्थान पर "श्री डी०आर० राजगरहिआ" पढ़ें ।

[सं० 6(27)/76 सि०लि० तथा नि०उ०]

सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th June, 1979

S.O. 1893.—In the Table to the notification of the Government of India in the ministry of Commerce, Civil Supplies & Cooperation, S.O. No. 3348 dated the 25th November, 1978, published at pages 3165 to 3169 of sub-section (ii) of section 3 of Part II of the Gazette of India, dated the 25th November, 1973, in the entries in Column (2) —

(i) against Sl. No. 1 in column (1), —

(a) in item 1) at page 3167, for "Rajigarhia", read "Rajgarhia",

(b) In item (5) at page 3168, after "The Deputy Director (Export Promotion)", add "Ex-officio".

(ii) against Sl. No. 2 in column (1), in item (5) at page 3168, before "Shyam Sunder Bagaria" add "Shri',

(iii) against Sl. No. 3 in column (1),

(a) in item (1) at page 3168, for "Bhandani", read "Bnadani",

(b) in item (6) at page 3168, after "Ex-officio", add "Export Inspection Council",

(iv) against Sl. No. 4 in column (1),

(a) to items (4) and (5) at page 3169, add "Member".

(b) in item (7) at page 3169, for "Member", read "Convener".

(v) against S1.No.5 in column (1), in item (2) at page 3169, for "D. Rajgarhia", read "D. R. Rajgarhia".

[No. 6(27/76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Joint Director

(नागरिक पूर्ति सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, मई, 1979

का०आ० 1894.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सैन्ट्रल इण्डिया कमर्शियल एक्सचेंज लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किए गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को अलसी की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 2 जून, 1979 से पहली जून 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12 (5)-आई०टी०/79]

के० एस० मैथ्यू, उप सचिव

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the May, 1979

S.O. 1894.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from the 2nd June, 1979 to the 1st June, 1982 both days inclusive, in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(5)-IT/79]

सहकारिता मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1979-05-02

का० आ० 1895.— समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-6724 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, फर्म के अपने अनुरोध पर 1979-02-01 से रद्द कर दिया गया है :

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीएम/एल-6724 1978-01-31	मैसर्स किर्लोस्कर किसान इक्विपमेंट लि०, कर्वे रोड, कोथरुड, पूणे 411029 (महाराष्ट्र)	निम्न रेटिंग के एक सिलेंडर, दो स्ट्रोक वायु शीतित चिनगारी वाही इंजन :	: 7347–1974 छोटे साइज के चिनगारी वाही इंजनों की विशिष्टि

कि वा०	गति	टाइप	मार्का
0.956 (1.3 हार्पा)	6000 चक्कर प्रति मिनट	केपी० 35	'किर्लोस्कर'

[सी०एम०एल०/55: 6724]
ए०पी० बनर्जी, उप महानिदेशक

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1979-05-02

S.O. 1895.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-6724 particulars of which are given below has/have been cancelled with effect from 1979-02-01 on request of the firm.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CM/L-6724 1978-01-31	M/s. Kirloskar Kisan Equipment Ltd, Karve Road, Kothrud, Pune-411029 (Maharashtra)	Single cylinder, two-storke, air-cooled spark ignition engines of the following ratings:	IS : 7347-1974 Specification for Small size spark ignition engines.

kW	Speed	Type	Brand
0.956 (1.3 bhp)	6000 RPM	KP-35	'KIRLOSKAR'

[No. CMD/55 : 6724]
A.P. BANERJI, Deputy Director General

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1979

का० आ० 1896.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, नमक आयुक्त, जयपुर के कार्यालय में नियोजित कर्मचारिवृन्द की ऐसे निवास स्थानों के आबंटन संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जो उक्त नमक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

अनु० नि० 317 कथ-1—संक्षिप्त नाम और लागू होना : (1) इन नियमों का नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (नमक आयुक्त कार्यालय कर्मचारिवृन्द क्वार्टर) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनु० नि० 317 कथ-2—परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "नमक आयुक्त" से नमक आयुक्त, भारत सरकार, विभाग में प्रधान अभिप्रेत है;

(ख) "आबंटन" से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निवास-स्थान के अधिभोग के लिए सम्पदा अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है;

(ग) "आबंटन वर्ष" से प्रथम जनवरी को आरम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(घ) "जयपुर" से, जयपुर नगरपालिका के अधीन जयपुर नगर की सीमाओं के भीतर का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे सरकार सरकारी निवास-स्थान के आबंटन के लिए पात्रता प्रदान करने वाला घोषित करें;

(ङ) "सम्पदा अधिकारी" से नमक उपायुक्त (मुख्यालय) अभिप्रेत है;

(च) "उपलब्धियों" से मूल नियम 45ग में यथा परिभाषित उपलब्धियां अभिप्रेत हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत प्रतिकारात्मक भत्ता नहीं है;

स्पष्टीकरण :—निलम्बित अधिकारी के मामले में, "उपलब्धियों" से (ये) "उपलब्धियां" मानी जाएंगी जो उनसे उस आबंटन वर्ष के प्रथम दिन प्राप्त की है जिसमें वह निलम्बित किया गया है अथवा, यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख के ठीक पहले प्राप्त की गयी है;

(छ) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, पत्नी अथवा पति और संतान, सौतेली संतान, वैध रूप में दत्तक ली गई संतान, माता-पिता, भाई, अथवा बहनें जो साधारण या अधिकारी के साथ निवास करते हैं और जो उस पर आश्रित हैं;

(ज) "सरकार" से, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(झ) "पूर्विकता तारीख" से, अधिकारी जिस प्रकार के निवास-स्थान का नियम 5 के अधीन पात्र है, उसके संबंध में, वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जब से वह, छुट्टी की अवधि के विकास, निरन्तर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन जिसके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी किसी पद पर प्राप्त करता रहा है जो किसी विशिष्ट टाइप अथवा किसी उच्चतर टाइप के लिए सुसंगत है :

परन्तु टाइप II, III के निवास-स्थानों की बाबत, वह तारीख, जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में, जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा की अवधि भी है, निरन्तर रहा है, उस टाइप के लिए उसकी पूर्विकता तारीख होगी :

परन्तु यह और जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही है, वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की राशि से अवधारित की जाएगी, अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी और जहां उपलब्धियां समान हैं वहां सेवा-काल की दीर्घता से अवधारित की जाएगी।

(1) टाइप (IV) और (V) के हकदार अधिकारियों की पूर्विकता तारीख वह तारीख होगी, जिससे सरकारी सेवक हकदार टाइप के संसंगत उपलब्धियां निरन्तर प्राप्त कर रहा है।

(2) टाईप (IV) और (V) के हकदार अधिकारियों की अपनी हकदारी से एक वर्ग नीचे के लिए आवेदन करने का विकल्प तब दिया जाएगा जब हकदार टाइप का क्वार्टर उपलब्ध नहीं है।

(3) उच्चतर टाइप के क्वार्टरों के हकदार अधिकारियों से उसी क्वार्टर का भाड़ा लिया जाएगा, चाहे वह उस क्वार्टर में जाने से इंकार करता है और निम्नतर टाईप के क्वार्टर में ही बना रहता है।

(अ) पात्र कार्यालय से नमक आयुक्त का वह कार्यालय अभिप्रेत है, जिसके कर्मचारिवृन्द को केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन निवास स्थान के लिए पात्र घोषित किया गया है।

परन्तु यदि किसी टाईप के निवास-स्थान नमक आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारिवृन्द का अपुक्षाओं से अधिक है तो नमक आयुक्त आबंटिती से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करके कि नमक आयुक्त उसे लिखित रूप में एक मास की सूचना देकर आबंटन प्रतिसंहृत कर सकेगा, विशेष मामले के रूप में केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारी/कर्मचारियों को आबंटन कर सकेगा।

(ट) "अनुज्ञप्ति फीस" से इन नियमों के अधीन आबंटित निवास स्थान की बाबत मूल नियम के उपबंधों के अनुसार मासिक रूप से देय धनराशि अभिप्रेत है,

(ठ) "निवास-स्थान" से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है जो तत्समय नमक आयुक्त जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में है ;

(ड) "उप पट्टे पर देने " में किसी आबंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ और अन्य व्यक्ति द्वारा किराए का संदाय करने पर अथवा किए बिना, आवास-सुविधा का सहभोग करना सम्मिलित है;

स्पष्टीकरण :— किसी आबंटिती द्वारा अपने निकट नातेदार या सौमित्तिक अतिथि के आवास सुविधा का सहभोग, उप पट्टप नहीं समझा जाएगा;

(ढ) "अस्थायी स्थानान्तरण" से ऐसा स्थानान्तरण अभिप्रेत है जिसमें जयपुर से कर्तव्य पर अनुपस्थिति की अवधि चार मास से अधिक की नहीं है;

(ण) "स्थानान्तरण" से जयपुर से किसी अन्य स्थान को अथवा जयपुर में किसी अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अपात्र संस्था या निकाय में स्थानान्तरण भी है;

(त) "टाइप" से किसी अधिकारी के संबंध में निवास-स्थान का वह टाइप अ अभिप्रेत है, जिसका वह नियम 5 के अधीन पात्र है।

अनु० नि० 317 कथ 3-मकानों के स्वामी अधिकारियों का इन नियमों के अधीन आबंटन के लिए पात्र होना:—

(1) इस नियम में,

(क) 'लगी हुए नगर पालिका' से स्थानीय नगर पालिका से आसन्न कोई नगरपालिका अभिप्रेत है;

(ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्य के संबंध में मकान से, निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाला कोई ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेतित है जो, स्थानीय नगर पालिका या किसी लगी हुए नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित है।

स्पष्टीकरण:— ऐसा भवन, जिसका भाग निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इस बात के होते हुए भी कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के लिए भी प्रयुक्त होता है, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए मकान समझा जाएगा;

(ग) किसी अधिकारी के संबंध में, स्थानीय नगरपालिका से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका कार्यालय स्थित है;

(घ) 'नगरपालिका' के अंतर्गत नगर-निगम, नगर समिति बोर्ड, नगर क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड भी है ;

(2) वे अधिकारी भी, जिनके अपने मकान हैं, क्वार्टरों के आबंटन के लिए पात्र होंगे। ऐसे अधिकारियों को आबंटन सामन्य भाड़े पर किया जायेगा उसके अपने आधी दर पर, यदि मकान आय प्रतिमास 1000 रु० से अधिक नहीं है, बाजार-भाड़े की आधी दर पर यदि अथवा प्रतिमास 1000 रू० से अधिक किन्तु 2000 रू० से अधिक नही है। तथा बाजार-भाड़े की पूरी दर पर, यदि आय प्रतिमास 2000 रु० से अधिक हो। यह नियम समान रूप से लागू होगा, चाहे मकान का स्वामी अधिकारी स्वयं है या उसकी पत्नी/उसका पति है या उसके आश्रित बच्चे हो।

(3) यदि कोई अधिकारी, सरकारी निवास- स्थान आबंटित कर दिए जाने के पश्चात स्वंय या उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य मकान बनाता है या अन्यथा मकान का स्वामी हो जाता है, तो ऐसा अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह या ऐसा सदस्य व मकान का स्वामी होता है, चार सप्ताह की अवधि के भीतर सम्पदा अधिकारी को ऐसा तथ्य अधिसूचित करेगा।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार कष्ट के विनिर्दिष्ट मामलों में या लोकहित में किसी अधिकारी को निवासस्थान आबंटित कर सकेगी या यदि वह ऐसे निवास-स्थान का अधिभोगी है, तो यथास्थिति, भू० नि० 45-क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय या भाड़ा- युक्त आधार पर उसके प्रतिधारण की उसे अनुज्ञा दे सकेगी।

अनु० नि० 317 कथ 4 पति और पत्नी को आबंटन, परस्पर विवाहित अधिकारियों के मामलों में पात्रता:—

(1) किसी अधिकारी को, यथास्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवास स्थान आबंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवास-स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता:

परन्तु यह उप-नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक निवास कर रहे हैं।

(2) यदि दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन आबंटित पृथक-पृथक निवास- स्थानों के अधिभोगी हैं, परस्पर विवाह कर लेते हैं तो वे विवाह के एक मास के भीतर उस निवास-स्थानों में से एक अभ्यर्पित कर देंगे।

(3) यदि निवास- स्थान का अभ्यर्पण उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो निम्नतर टाइप के निवास स्थान का आबंटन एक मास की समाप्ति पर रद्द कर दिया गया समझा जाएगा और यदि निवास- स्थान एक ही टाइप के हैं तो नमक आयुक्त के विनिश्चयानुसार उनमें से एक का आबंटन उक्त एक मास की समाप्ति पर रद्द कर दिया गया समझा जाएगा।

4. यदि पति और पत्नी दोनों, नमक आयुक्त के कार्यालय, जयपुर में नियोजित हों तो इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबंटन के लिए उनकी पात्रता पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया जाएगा।

अनु० नि० 317—कथ-5 निवास स्थानों का वर्गीकरण :—इन नियमों द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अधिकारी नीचे दी गई सारणी में वर्णित टाइप के निवासस्थान के आबंटन का पात्र होगा :—

निवास स्थान का टाइप	अधिकारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन किया जाएगा उसके प्रथम दिन उसका प्रवर्ग अथवा उसकी मासिक उपलब्धियां
1	259 रु० तक
2	260 रु० से 499 रु० तक
3	500 रु० से 999 रु० तक
4	1000 रु० से 1499 रु० तक
5	1500 रु० और उससे अधिक, मुख्य एकक

अनु०नि० 317 कथ-6—आबंटन के लिए आवेदन पत्र : वह अधिकारी, जो निवास-स्थान के आबंटन या ऐसे निवास-स्थान को, जो उसे आबंटित किया गया है, बनाए रखने की वांछा करता है, सम्पदा अधिकारी को किसी भी समय आवेदन कर सकेगा और उस निमान सम्पदा अधिकारी को तब आवेदन करेगा जब उसके द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिया जाए और ऐसी तारीख तक ऐसा आवेदन करेगा जो सम्पदा अधिकारी द्वारा विहित की जाए। प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन उपबन्ध 'ख' में दिए गए प्रारूप में होगा।

अनु० नि० 317 कथ-7—निवास स्थानों का आबंटन और प्रस्थापनाएं :—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी निवास-स्थान के खाली होने पर वह, सम्पदा अधिकारी द्वारा उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसकी उस टाइप के निवास-स्थान के लिए पूर्विकता तारीख पूर्वतम हो। यह आबंटन निम्नलिखित शर्तों पर होगा, अर्थात् :—

(I) सम्पदा अधिकारी उस टाइप से उच्चतर टाइप का निवास-स्थान आवंटित नहीं करेगा जिसका आवेदक नियम 5 के अधीन पात्र है;

(II) सम्पदा अधिकारी किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वह नियम 5 के अधीन जिस टाइप के निवास-स्थान का पात्र है उससे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान स्वीकार करे।

(III) सम्पदा अधिकारी अति विशेष परिस्थितियों में किसी आवेदक से निम्नतर प्रवर्ग के निवास-स्थान के आबंटन के लिए उसकी प्रार्थना पर उसे ऐसे निवास-स्थान से ठीक निचले टाइप का निवास-स्थान आवंटित कर सकता है जिसके लिए आवेदक अपनी पूर्विकता तारीख के आधार पर नियम 5 के अधीन (उस तारीख को जिसको प्रार्थना की गई थी) पात्र है।

(2) यदि किसी अधिकारी के अधभोगाधीन किसी निवास-स्थान को खाली कराना अपेक्षित है तो सम्पदा अधिकारी उस अधिकारी का ऐसी टाइप का अनुकल्पी निवास-स्थान आवंटित कर सकता है, अथवा

अत्यावश्यकता की स्थिति में, उस अधिकारी के अधिभोगाधीन के निवास-स्थान के टाइप से ठीक निम्नतर टाइप कक्ष का अनुकल्पी निवास-स्थान भी आबंटित कर सकता है ।

टिप्पणी :—यदि किसी अधिकरी के अधिभोगाधीन उस टाइप के निवास-स्थान से, जिसके लिए वह नियम 5 के अनुसार हकदार है, उच्चतर टाइप का निवास-स्थान है तो उसे उस टाइप की, जिसके लिए वह नियम 5 के अधीन हकदार है, अनुकल्पी निवास-स्थान या अत्यावश्यकता की स्थिति में उस टाइप से, जिसके लिए वह हकदार है, ठीक निचली टाइप का अनुकल्पी निवास-स्थान दिया जा सकेगा ।

(3) खाली निवास-स्थान को, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन किसी अधिकारी को आबंटित किए जाने के अतिरिक्त, अन्य पात्र अधिकारियों को भी उनकी पूर्विकता की तारीखों के क्रम से, आबंटन के लिए प्रस्थापित किया जा सकता है ।

अनु० नि० 317-कथ-8—आबंटन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना अथवा आबंटित निवास-स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में न लेना :—

(1) यदि कोई अधिकारी किसी निवास-स्थान का आबंटन, आबंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद आठ दिन के भीतर उस निवास-स्थान का कब्जा नहीं लेता है या कुछ समय के पश्चात् आबंटन अभ्यर्पित कर देता है तो वह, यथास्थिति, उस आबंटन-पत्र या अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि किसी अधिकारी को, जिसके अधिभोगाधीन किसी निम्नतर टाइप का निवास-स्थान है, ऐसे टाइप का निवास-स्थान आबंटित या प्रस्थापित किया जाता है जिसके लिए वह नियम 5 के अधीन पात्र है या उसके लिए उसने नियम 7(I)(iii) के अधीन आवेदन किया है तो उसे, उक्त आबंटन या आबंटन की प्रस्थापना के अस्वीकार कर दिए जाने पर, पहले आबंटित निवास-स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) ऐसा अधिकारी आबंटनपत्र की तारीख से छह मास की अवधि तक के लिए उच्चतर श्रेणी के निवास-स्थान के दूसरे आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) विद्यमान निवास-स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वह अनुज्ञप्ति फीस जो उसे मू० नि० 45-क के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास-स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा वह अनुज्ञप्ति फीस जो उस निवास-स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, इसमें से जो भी अधिक है वह, प्रभारित की जाएगी ।

अनु० नि० 317-कथ-9—आबंटन प्रभावी रहने की अवधि, और तत्पश्चात् कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि :—

(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको सम्बन्धित अधिकारी ऐसे स्वीकार करता है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि :—

(क) अस्थायी स्थानान्तरण की अवधि समाप्त नहीं हो जाती;

(ख) उपखण्ड (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती;

(ग) आबंटन, सम्पदा अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता;

(घ) अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता; या

(ङ) अधिकारी निवास-स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता ।

(2) अधिकारी, उसे आबंटित निवास-स्थान को, उपनियम (3) के अधीन रहते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के घटित होने पर उस अवधिपर्यन्त अपने पास रख सकता है जो उस सारणी के स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, परन्तु यह तब जब कि वह निवास-स्थान, अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के सद्भाविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो ।

सारणी

घटनाएं	निवास-स्थान अपने पास रखने के लिए अनुज्ञेय अवधि
(i) पदत्याग, पदच्युति, सेवा से हटाया जाना, या सेवा का पर्यवसान ।	1 मास
(ii) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	2 मास
(iii) आबंटती की मृत्यु	4 मास
(iv) जयपुर से बाहर किसी स्थान को स्थानान्तरण ।	2 मास
(v) राज्य या केन्द्रीय सरकार को प्रतिनियुक्ति	2 मास
(vi) भारत में अन्यत्र सेवा पर जाना	2 मास
(vii) छुट्टी जो निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो ।	छुट्टी की अवधिपर्यन्त किन्तु चार मास से अनधिक ।
(viii) निवृत्ति-पूर्व छुट्टी या मूल नियम 86 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी ।	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधिपर्यन्त पूर्व छुट्टी की दशा में 180 दिन की और अन्य मामलों में 4 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए ।
(ix) अध्ययनार्थ छुट्टी (भारत से बाहर) या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति ।	अवधिपर्यन्त
(x) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी (क्षय रोग छुट्टी से भिन्न)	छुट्टी की पूर्ण अवधिपर्यन्त किन्तु आठ मास से अधिक नहीं ।
(xi) क्षय रोग के आधार पर चिकित्सीय छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि के लिए ।
(xii) प्रशिक्षण	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि के लिए
(xiii) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की अवधिपर्यन्त, किन्तु छह मास से अधिक नहीं ।

स्पष्टीकरण :

(1) मद (4), (5) और (6) के सामने उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना पर भार छोड़ने की तारीख से की जाएगी । जहां भारत में स्थानान्तरण होने या अन्यत्र सेवा में जाने पर किसी अधिकारी को कोई छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नए कार्यालय में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उस छुट्टी का उपभोग करता है तो उसे मद (4), (5), (6) और (7) के सामने वर्णित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अधिक हो, निवास-स्थान रखे रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

(2) जहां भारत में स्थानान्तरण या अन्यत्र सेवा सम्बन्धी कोई आदेश किसी अधिकारी को जब जारी किया जाता है, जब वह पहले से ही छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण 1 के अधीन अनुज्ञेय अवधि की गणना, ऐसा आदेश जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी ।

(3) जहां कोई निवास-स्थान उपनियम (2) के अधीन कायम रखा जाता है तो अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति पर वह आबंटन, सिवाय उस दशा के जब उन अवधियों की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् अधिकारी नमक आयुक्त, जयपुर के कार्यालय में कर्त्तव्य भार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया गया समझा जाएगा ।

(4) जिस अधिकारी ने उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर, निवास-स्थान अपने पास रखे रखा है वह नमक आयुक्त, जयपुर के कार्यालय में, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनर्नियोजित होने पर, उस निवास-स्थान के किसी और आबंटन का भी पात्र होगा । परन्तु यदि पुर्नियोजन होने पर, अधिकारी की उपलब्धियां उसे उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार नहीं बनाती जो उसके अधिभोग में है, तो उसे ऐसे निवास-स्थान के आबंटन के लिए, अन्य आवेदकों से अधिमान देते हुए, निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित किया जाएगा ।

अनु० नि० 317 क ध-10—अनुज्ञप्ति फीस सम्बन्धी उपबन्ध :

(1) जहां वास-सुविधा या अनुकल्पी वास-सुविधा का आबंटन स्वीकार कर लिया जाता है वहां अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठवें दिन से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा । जो अधिकारी आबंटन स्वीकार करने के पश्चात् उस वास-सुविधा का कब्जा आबंटन की प्राप्ति से आठ दिन के भीतर नहीं ले लेता है, उससे उस तारीख से एक मास की अवधि या उस वास-सुविधा का पुनः आबंटन हो जाने की तारीख तक की, इनमें से जो भी पहले हो, अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी ।

(2) जहां एक निवास-स्थान के अधिभोगी किसी अधिकारी को दूसरा निवास-स्थान आबंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान पर अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास-स्थान का आबंटन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा । किन्तु वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पहले निवास-स्थान को, उस दिन तथा उसके पश्चात्वर्ती दिन तक, बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए, अपने पास रख सकता है ।

अनु० नि० 317-क ध-11—निवास-स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना :

(1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया जाए उस पर उसकी अनुज्ञप्ति फीस तथा उस नुकसान का दायित्व होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त उस निवास-स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा व्यवस्था को उस अवधि के दौरान पहुंचाता है जब निवास-स्थान उसे आबंटित रहा है और रहता है, या यदि आबंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया है तो जब तक निवास-स्थान तथा उससे संलग्न उपगृह खाली करके उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता । निवास-स्थान का कब्जा लेते समय या उसे खाली करते समय उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फर्नीचर और फिटिंग तालिका पर हस्ताक्षर करे ।

(2) जहां वह अधिकारी, जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है, न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्थायीवत्, वहां वह एक प्रतिभूति सहित जो नमक आयुक्त, जयपुर के अधीन सेवारत स्थायी सरकारी सेवक होगा, सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप (उपाबन्ध "ग") में, प्रतिभूति पत्र निष्पादित करेगा । यह प्रतिभूति-पत्र अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास-स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हो ।

(3) यदि प्रतिभूति नमक आयुक्त, जयपुर के अधीन सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या अपनी प्रत्याभूति वापस ले लेता है या किसी अन्य कारण से वह उपलब्ध नहीं रह जाता है तो अधिकारी ऐसी घटना या तथ्य की जानकारी होने से 30 दिन के भीतर किसी अन्य प्रतिभूति द्वारा निष्पादित एक नया बन्धपत्र देगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो, जब तक सम्पदा अधिकारी अन्यथा विनिश्चित न करे, उस निवास-स्थान का उसे आबंटन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा ।

अनु० नि० 317-क ध-12—आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि :

अधिकारी ऐसी सूचना देकर, जो निवास-स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व सम्पदा अधिकारी के पास पहुंच जाए, किसी भी समय आबंटन को अभ्यर्पित कर सकता है । निवास-स्थान का आबंटन उस दिन के पश्चात्, जिसको पत्र सम्पदा अधिकारी को प्राप्त होता है, ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, रद्द किया गया समझा जाएगा । यदि अधिकारी सम्यक् सूचना न दे तो वह दस दिन की अथवा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो, उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए दायी होगा, परन्तु सम्पदा अधिकारी कम अवधि की सूचना को स्वीकार कर सकता है ।

अनु० नि० 317-क ध-13—निवास-स्थान का परिवर्तन :

(1) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आबंटन किया गया है, यह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले में उसी टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका वह नियम 5 के अधीन पात्र है, जो भी निम्नतर हो, निवास-स्थान दिया जाए । किसी अधिकारी को आबंटित एक टाइप के निवास-स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) परिवर्तन के लिए सभी आवेदन कैलेण्डर मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त किए जाएंगे । इस प्रकार प्राप्त आवेदन अगले मास की प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किए जाएंगे । इस नियम के प्रयोजनों के लिए वे अधिकारी जिनके नाम पूर्ववर्ती मास की प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किए गए हों, समुच्चयित रूप से उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मास की सूची में सम्मिलित किए जाने हैं । किसी विशिष्ट मास की सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्वकता तारीखों के क्रम से अवधारित की जाएगी ।

(3) परिवर्तन उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम से तथा यावत्साध्य अधिकारियों के अधिमानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्थापित किया जाएगा ।

(4) यदि कोई अधिकारी, उसे प्रस्थापित निवास-स्थान का परिवर्तन, आबंटन-पत्र जारी किए जाने के सात दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता तो उसके नाम पर, उस टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा ।

(5) जो अधिकारी, निवास-स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता, उससे ऐसे निवास-स्थान के लिए जो पहले ही उसके कब्जे में है और जिसका आबंटन बराबर बना रहेगा, मू० नि० 45-क के अधीन सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, नियम 10 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निवास-स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी ।

अनु० नि० 317-क ध-14—कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु आदि होने की दशा में निवास-स्थान का परिवर्तन :

नियम 13 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करता है तो उससे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है, परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास-स्थान में तथा उसी मंजिल पर होगा जो उस अधिकारी को पहले से आबंटित है ।

अनु० नि० 317-क य-15—निवास-स्थानों का पारस्परिक विनिमय

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास स्थान आबंटित किए गए हैं, वे अपने निवास-स्थानों के पारस्परिक विनिमय करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकते हैं । जब इस बात की युक्तियुक्त तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनिमय के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास तक जयपुर में कर्त्तव्यारूढ़ रहेंगे और पारस्परिक रूप से विनिमय किए गए अपने निवास-स्थानों में रहेंगे, तो पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

अनु० नि० 317-क य-16—अकुटुम्ब स्टेशनों पर स्थानान्तरण :

यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण ऐसे स्टेशन पर कर दिया जाता है जहां सरकार द्वारा उसे अपने साथ कुटुम्ब को ले जाने की अनुज्ञा या सलाह नहीं दी जाती है और इन नियमों के अधीन उसे आबंटित निवास-स्थान की आवश्यकता उसके बच्चों की सद्भाविक शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए, कुटुम्ब को है, तो उसे, प्रार्थना करने पर, जयपुर में अपने बच्चों के चालू शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक अ० नि० 45-क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस को संदाय करने पर निवास-स्थान अपने पास रख रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

अनु० नि० 317-क य-17—निवास-स्थान का अनुरक्षण :

जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया जाता है वह उसे और उसके परिसरों को, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका, जयपुर को समाधानप्रद रूप में, साफ दशा में रखेगा । ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान से संलग्न किसी उद्यान, आंगन या चार-दीवारी में न तो राज्य सरकार और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटेगा या छांटेगा । इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष, पौधे या वनस्पति को, सम्बन्धित अधिकारी की जोखिम पर और उसके खर्च पर राज्य सरकार/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया जा सकेगा ।

अनु० नि० 317-क य-18—निवास-स्थान को उप पट्टे पर देना और सहभोग :

(1) कोई अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपगृहों और गैरेजों का सहभोग, केन्द्रीय/राज्य सरकार या सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी से नहीं करेगा और इसके लिए भी सम्पदा अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी । सेवक क्वार्टरों उपगृहों और गैराजों का उपयोग केवल सद्भाविक प्रयोजनों के लिए, जिनमें आबंटिती के सेवकों का निवास भी सम्मिलित है, या अन्य ऐसे, प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी सम्पदा अधिकारी अनुज्ञा दें ।

(2) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्थान को उप-पट्टे पर नहीं देगा : परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास-स्थान में किसी अन्य अधिकारी को, जो सरकारी आवास-सुविधा का सहभोग करने के लिए पात्र है नियम 10(2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, रखवाल के रूप में, रख सकता है जो छह मास से अधिक की नहीं होगी ।

(3) जो अधिकारी अपने निवास-स्थान का सहभोग करे या उसे उपपट्टे पर दे वह ऐसा अपनी जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा और उस निवास-स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेदार बना रहेगा जो निवास-स्थान को या उसके अहाते या भूमि की या सरकार द्वारा उसमें दी गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो ।

अनु० नि० 317-क य-19—असाधारण परिस्थितियों में समक आयुक्त, सरकारी निवास-स्थान के आबंटिन या सहभोगी को बाजार दर पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर, अनिवासीय प्रयोजनों (उदाहरणार्थ विवाह आदि मनाने) के लिए 7 (सात) दिन से अनधिक की अवधि के लिए आबंटन कर सकेगा ।

अनु० नि० 317 क य -20—नियमों और शर्तों को भंग करने के परिणाम :—(1) यदि वह अधिकारी, जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास-स्थान उपपट्टे पर देता है या सहभोगी पर ऐसी दर से अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित करता है जिसे सम्पदा अधिकारी अत्यधिक समझता है अथवा निवास-स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है अथवा निवास-स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है जिसके लिए वह है अथवा विद्युत या जल के कनेक्शन को बिगाड़ता है अथवा इन नियमों या आबंटन के निबंधनों और शर्तों को भंग करता है अथवा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें सम्पदा अधिकारी अनुचित समझे, निवास-स्थान या परिसर का उपयोग करता है अथवा स्वयं ऐसा व्यवहार करता है कि जो सम्पदा अधिकारी की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, अथवा आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझकर देता है, तो सम्पदा अधिकारी उस अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, निवास-स्थान का आबंटन रद्द कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिकारी" पद के अंतर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है ।

(2) यदि अधिकारी ने नियम 3 के उपनियम (2) में यथा उपबंधित सम्पदा अधिकारी को अधिसूचित नहीं किया है या इस प्रकार अधिसूचित करते हुए किसी आवेदन या कथन में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है तो सम्पदा अधिकारी उस तारीख से, जिसको अधिकारी नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन सरकारी वास-सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र हो गया है, आबंटन रद्द कर सकेगा ।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपगृह या गैरेज को इन नियमों का उल्लंघन करके उपपट्टे पर देता है तो, ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे उतनी वर्धित अनुज्ञप्ति फीस ली जा सकती है जो अ० नि० 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुने से अधिक नहीं है । प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और किस अवधि के लिए वसूल की जाए, सम्पदा अधिकारी गुणावगुण के आधार पर करेगा । इसके अतिरिक्त, उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधिपर्यन्त, जो सम्पदा अधिकारी विनिश्चित करे निवास-स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जा सकेगा ।

(4) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से उपपट्टे पर दिए जाने के कारण आबंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाती है वहां आबंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा । परिसर खाली किए जाने की तारीख या आबंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि की समाप्ति पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा ।

(5) जहां निवास-स्थान का आबंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां उस अधिकारी को सम्पदा अधिकारी के विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास-स्थान किसी अन्य स्थान में आबंटित किया जा सकता है ।

(6) सम्पदा अधिकारी इस नियम के उपनियम (2) से (5) तक के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्रवाई करने के लिए तथा ऐसे अधिकारी को जो इन नियमों तथा उसको जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष तक की अवधि के लिए आवास-सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए सक्षम होगा ।

अनु० नि० 317 क ध 21. आवंटन के रद्द किए जाने के तपश्चात् निवास-स्थान में बने रहना:—जहां कोई आवंटन इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया गया है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात वह निवास-स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आवंटित किया गया है उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा है वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान, सेवाओं, फर्नीचर और बाग प्रभारों के उपयोग और अधिभोग के लिए ऐसी नुकसानी के लिए ऐसे प्रभार देने के लिए दायी होगा जो नमक आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर हो ;

परन्तु अधिकारी को, विशेष दशाओं में सम्पक्ष अधिकारी द्वारा नियम 10(2) के अधीन अनुज्ञात अवधि से आगे छह मास तक की अवधि के लिए मु० नि० 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से दुगुनी अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर, निवास-स्थान रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

अनु० नि० 317 क-ध-22—इन नियमों के जारी किए जाने के पहले किए गए आवंटनों का बना रहना : निवास स्थान का विधि-मान्य आवंटन, जो तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व अस्तित्व में था, इस बात के होते हुए भी कि वह अधिकारी जिसे वह आवंटन किया गया हो, नियम 5 के अधीन उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार नहीं है, सम्यक रूप से किया गया आवंटन समझा जाएगा और उस आवंटन और उस अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

अनु० नि० 317 क ध-23—नियमों का निर्वाचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठता है तो उसे विनिश्चय के लिए भारत सरकार को निर्देशित किया जाएगा।

अनु० नि० 317 क ध-24—नियमों का शिथिलीकरण :—

भारत सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, इन नियमों के सभी उपबंधों को या उनमें से किस को किसी अधिकारी या निवास स्थान या किसी वर्ग अधिकारियों या निवास-स्थानों के किसी टाइप के बारे में इन नियमों के अधीन, यदि अपेक्षित हो तो समुचित प्राधिकारी से परामर्श करने/अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शिथिल कर सकेगी।

[फा० सं० 44011/22/76-नमक]

ए० महादेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Salt Desk)

New Delhi, the 28th May, 1979

S.O. 1896.—In pursuance of the provisions of Rule 45 of the Fundamental Rules, the president hereby makes the following rules regarding allotment of residences under the Administrative Control of the Salt Commissioner, Jaipur to the Staff employed in his office.

S.R. 317-AQ-1.—Short title and application :

(1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (Salt Commissioner Office Staff Quarters) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

S.R. 317-AQ-2.—Definitions :

In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Salt Commissioner" means the Salt Commissioner, Government of India, the Head of the Department ;

(b) 'allotment' means the grant of a licence by the Estate Officer to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules ;

(c) 'allotment year' means the year beginning on 1st January, or such other period as may be notified by the Central Government ;

(d) 'Jaipur' means the arae within the limits of Jaipur township under Jaipur municipality which the Government may declare as conferring eligibility for the allotment of Government accommodation ;

(e) 'Estate Officer' means the Deputy Salt Commissioner (Headquarters) ;

(f) 'emoluments' means the emoluments as defined in Fundamental Rule 45 C but excluding the compensatory allowance :

EXPLANATION :

In the case of an Officer who is under suspension the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments ;

(g) 'family' means the wife or husband, as the case may be, and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the Officer ;

(h) 'Government' means the Central Government unless the context otherwise requires ;

(i) 'priority date' of an Officer in relation to a type of residence to which he is eligible under rule 5 means, the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or State Government or on foreign sevice except for the periods of leave :

Provided that in respect of a Type II, III residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or State Government including the periods of foreign service, shall be his priority date for that type :

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments ; and where the emoluments are equal, by the length of service ;

(1) Date of priority of officers entitled to Type IV and V shall be the date from which a Government servant is continuously drawing emoluments relevant to entitled type.

(2) Officers entitled to Types IV and V shall be given option to apply for one class below their entitlement if quarter of the entitled type is not available.

(3) Officers entitled to higher type of quarters shall be charged rent of that quarter even if he refuses to shift to that quarter and continues in lower type quarter.

(j) 'eligible office' means the Salt Commissioner's Office the staff of which has been declared by the Central Government as eligible for accommodation under these rules ;

Provided that if any type of accommodation becomes surplus to the requirements of staff of the Salt Commissioner's Office, the Salt Commissioner may allot the same to an employee/employees of other Central or State Government Departments as a special case on obtaining an undertaking from

the allottee that the Salt Commissioner reserves the right to revoke it at any time by giving him one month's notice in writing. The undertaking to be furnished should be in the form given in Annexure 'A'.

(k) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence of allotted under these rules;

(l) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the Salt Commissioner, Jaipur;

(m) 'sub-letting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person.

EXPLANATION :

Any sharing of accommodation by an allottee with close relations or a casual guest shall not be deemed to be sub-letting.

(n) 'temporary transfer' means a transfer on duty from Jaipur which involves an absence for a period not exceeding four months;

(o) 'transfer' means a transfer from Jaipur to any other place or to an ineligible office in Jaipur and includes a transfer to a State Government Department or any other Department of the Central Government or any ineligible institution or body.

(p) 'type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under rule 5.

S.R. 317-AQ-3.—Officers owning houses to be eligible for allotment under these rules :

(1) In this rule —

(a) 'adjoining municipality' means any municipality contiguous to a local municipality;

(b) 'house' in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

EXPLANATION :

A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes;

(c) 'local municipality' in relation to an Officer means the municipality within whose juristdiction his office is located;

(d) 'municipality' includes a Municipal Corporation, a Municipal Committee or Board, a Town Area Committee, a Notified Area Committee, and a Cantonment Board.

(2) The officials who own houses shall also be eligible for allotment of quarters. Allotment to such Officials shall be on normal rent if the income from his own house does not exceed Rs. 1,000 p.m., one half the market rent if the income exceeds Rs. 1,000 p.m. but does not exceed Rs. 2,000 p.m. on full market rent if the income is above Rs. 2,000 p.m. This will apply equally whether the house is owned by the officer or his/her wife/husband or by his/her dependent children.

(3) Where, after a Government residence has been allotted to an Officer, he or any other member of his family constructs a house or otherwise becomes the owner of the house, such officer shall notify the fact to the Estate Officer within a period of four weeks from the date on which he or such member becomes the owner of the house;

(4) Notwithstanding anything contained in this rule Government may allot a residence to an officer or if he is in occupation of such residence allow its retention on payment of licence fee under F.R. 45-A or on rent free basis, as the case may be, in specific cases of hardship or in public interest.

S.R. 317-AQ-4.—Allotment to husband and wife, eligibility in cases of officers who are married to each other :

1. No officer shall be allotted a residence under these rules, if the wife or the husband as the case may be, has already been allotted a residence unless such residence is surrendered;

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any Court.

2. Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall, within one month of the marriage, surrender one of the residences.

3. If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of one month and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Salt Commission may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of said one month.

4. Where both husband and wife are employed in the office of the Salt Commissioner, Jaipur, the eligibility of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

S.R. 317-AQ-5.—Classification of residences :

Save as otherwise provided by these rules, an officer will be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below :—

Type of residence	Category of officer or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made.
I	Upto Rs. 259
II	Rs. 260 to Rs. 499
III	Rs. 500 to Rs. 999
IV	Rs. 1,000 to Rs. 1,499
V	Rs. 1,500 and above, main unit

S.R. 317 AQ-6.—Application for Allotment :

An officer who seeks allotment of a residence or the continuance of allotment of a residence which has been allotted to him may apply at any time and shall apply in that behalf to the Estate Officer when directed to do so by him and by such date as may be prescribed by the Estate Officer. The application to be submitted shall be in the form given in Annexure 'B'.

S.R. 317-AQ-7.—Allotment of residences and offer :

(1) Save as otherwise provided in the rules, a residence, on falling vacant, will be allotted by the Estate Officer to an applicant having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions :—

(i) the Estate Officer shall not allot a residence of a type higher than that to what the applicant is eligible under rule 5.

(ii) the Estate Officer shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than that to what he is eligible under rule 5.

(iii) The Estate Officer in very special circumstances on request from an applicant for allotment of a lower category residence, might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under rule 5 on the basis of his priority

date for the same (date on which the request was made).

(2) The Estate Officer may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances, an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer, if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

Note.—In case an officer is occupying residence of a type higher than the one to which he is entitled in terms of rule 5, he may be given an alternative residence of the type to which he is entitled to under rule 5 or in emergent circumstances, an alternative residence of the type next below his entitled type.

(3) A vacant residenc may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1) above be offered simultaneously to other eligible officers in the order of the priority dates.

S.R. 317-AQ-8.—Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residences after acceptance

(1) If an officer fails to accept the allotment of a residence within seven days of receipt of notice or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment or surrenders the allotment after some time, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of the allotment letter or the date of surrender as the case may be.

(2) If an officer occupying a lower type residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 5 for which he has applied under rule 7(1)(iii) he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotment residence on the following conditions, namely :

(a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher class accommodation ;

(b) while retaining the existing residence, he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under F.R. 45-A in respect of residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation whichever is higher.

S.R. 317-AQ-9.—Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.

(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until :

(a) the expiry of the period of temporary transfer ;

(b) the expiry of the concessional period permissible under sub-clause (2) ;

(c) it is cancelled by the Estate Officer or is deemed to have been cancelled under any provisions in these rules ;

(d) it is surrendered by the officer, or

(e) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3), be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the bona-fide use of the officer or member of his family.

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence
(i) Resignation, dismissal, removal or termination of service.	1 month
(ii) Retirement or terminal leave	2 months
(iii) Death of the allottee.	4 months
(iv) Transfer to a place outside Jaipur.	2 months
(v) Deputation to the State or Central Government.	2 months
(vi) On proceeding of foreign service in India.	2 months
(vii) Leave other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave.	For the period of leave but not exceeding 4 months
(viii) Leave preparatory to retirement or refused Leave granted under F.R. 86.	For the full period of leave on full average pay, subject to a maximum of 180 days in the case of leave preparatory to retirement and 4 months in other cases.
(ix) Study leave (outside India) or deputation outside India.	Entire period.
(x) Leave on medical grounds (other than T.B. Leave).	For the period of leave but not exceeding 8 months.
(xi) Medical leave on grounds of T.B.	For the full period of leave.
(xii) On proceeding on training.	For the full period of training.
(xiii) Study leave in India.	For the period of leave but not exceeding six months.

EXPLANATION-I :

The period permisible on transfer mentioned against items (iv), (v) and (vi) shall count from the date of relinquishing charge. Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v), (vi) and (vii) or for the period of leave, whichever is more.

II. Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under Explanation I shall count from the date of issue of such order.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in the office of the Salt Commissioner, Jaipur.

(4) An Officer who has retained the residence by virtue of the concessions under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2), shall on re-employment in the office of the Salt Commissioner, Jaipur, within the period specified in the said Table be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules. Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence in preference to othr applicants for allotment of such a residence.

S.R. 317-AQ-10.—Provisions relating to Licence Fee :

(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment letter whichever is earlier. An officer who after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of

receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of one month or upto the date of re-allotment of that particular accommodation, whichever is earlier.

(2) Where an officer who is in occupation of a residence is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

S.R. 317-AQ-11.—Personal liability of the officer for payment of Licence Fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officers :

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereto and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by the Central Public Works Department during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules until the residence along with the outhouses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government. He shall be required to sign an inventory of the furniture and fittings when he takes possession and vacates the residence.

(2) Where an officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government Servant, he shall execute a security bond in the form prescribed (Annexure 'C') in this behalf by the Central Government with a permanent Government servant serving under the Salt Commissioner, Jaipur for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu.

(3) If the surety ceases to be in the Government service with the Salt Commissioner, Jaipur or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact, and if he fails to do so, the allotment of the residence shall, unless otherwise decided by the Estate Officer, be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event or fact.

S.R. 317-AQ-12.—Surrender of an allotment and period of Notice :

An Officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Estate Officer at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh days after the day on which the letter is received by the Estate Officer or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice, he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Estate Officer may accept a notice for a short period.

S.R. 317-AQ-13.—Change of residence :

(1) "An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under rule 5, whichever is lower. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) All applications for the change shall be received upto the 19th day of a calendar month. The application so received shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purposes of this rule, the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior enblock to those whose names are included in the list in subsequent months. The inter-seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Change shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officers preferences as far as possible.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within seven days of the issue of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of residence of that type.

(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of rule 10 in addition to the normal licence fee under F.R. 45-A for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist.

S.R. 317-AQ-14.—Change of residence in the event of death etc. of a member of the family :

Notwithstanding anything contained in rule 13, an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family, if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of residence and in the same floor as the residence already allotted to the officer.

S.R. 317-AQ-15.—Mutual exchange of residence :

Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residence. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty in Jaipur and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

S.R. 317-AQ-16.—Transfer to non-family stations.

If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bona-fide educational needs of his children, he may be allowed, on request to retain the residence on payment of licence fee under F.R. 45-A till the end of current academic session of his children in Jaipur.

S.R. 317-AQ-17.—Maintenance of residence.

The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Departmet and the Municipal Committee, Jaipur. Such Officer shall not grow any trees, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the State Government and Central Public Works Departmet nor cut or lop off any existing tree or shrubs in any garden, courtyard or compound attached to the residence, save with the prior permission in writing of the Central Public Works Department. Trees, plantation or vegetation grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the State Government/Central Public Works Department of the risk and cost of the officer concerned.

S.R. 317-AQ-18.—Subletting and sharing of residences.

(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses and garages appurtenant thereto except with the employees of the Central/State Government or Government Undertaking for which prior permission of the Estate Officer will be required. The servants' quarters, out-houses and garages may be used only for the bonafide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Estate Officer.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence ; provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share Government accommodation as a caretaker for the period specified in rule 10(2) but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sub-lets this residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its preciners or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

S.R. 317-AQ-19.—In exceptional circumstances, the Salt Commissioner may make allotment for a period not exceeding 7 (seven) days for non-residential purposes (e.g. celebrating marriages etc.) on payment of market rate of licence fee to allottees or sharer of Government accommodation.

S.R. 317-AQ-20.—Consequences of breach of rules and conditions :

(1) If an officer to whom a residence has been allotted, unauthorisedly sublets the residence or charges licence fee from the share at a ratio which the Estate Officer considers excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of these rules or the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Estate Officer considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securring the allotment, the Estate Officer may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

EXPLANATION :

In this sub-rule, the expression officer includes unless the context otherwise requires, a member or his family and any person claiming through the the officer.

(2) If the officer has failed to notify to the Estate Officer as provided for in sub-rule (2) of rule 3 or while so notifying, has in any application or statement suppressed any material fact, the Estate Officer may cancel the allotment with effect from the date he became ineligible for allotment of Government accommodation under sub-rule (1) of rule 3.

(3) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, or garages, appurtenant thereto, in contravention of these rules he may, without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under F.R. 45-A. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the Estate Officer on merits. In addition, the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Estate Officer.

(4) Where action to cancel the allotment is taken on account of un-authorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee and any other person residing with him therein, to vacate that premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(5) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officers, at the discretion of the Estate Officer may be allotted another residence in the same class at any other place.

(6) The Estate Officer shall be competent to take all or any of the actions under sub-rule (2) to (5) of this rule and also to declare the officer who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

S.R. 317-AQ-21.—Overstayal in residence after cancellation of allotment :

Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any of the provisions contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of residence, services, furniture and garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by the Salt Commissioner from time to time.

Provided that, an officer, in special cases, may be allowed by the Estate Officer to retain a residence on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45-A for a period not exceeding six months beyond the period permitted under Rule 10(2).

S.R. 317-AQ-22.—Continuance of allotments made prior to the issue of these rules :

Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules, notwithstanding that the officer to whom it has meen made is not entitled to a residence of that type under rule 5 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

S.R. 317-AQ-24.—Relaxation of rules :

If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government of India for decision.

S R. 317-AQ-24.—Relaxation of rules :

The Government of India after consultation/approval with/ of the appropriate authority if required under the rules, relax for reasons to be recorded in writing, all or any of the provisions of these rules in the case of any officer/classes of officer or residence/or type/types of residence.

[F. No. 44011/22/76-Salt]
I. MAHADEVAN, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मई, 1979

का० आ० 1897.—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसरण में:—

1. केरल सरकार ने श्रीमती पंकजाक्षी अम्मा, मुख्य सरकारी विश्लेषक, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम को, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है।

2. महाराष्ट्र सरकार ने आयुक्त, खाद्य और औषधि प्रशासन महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई को, उक्त समिति का सदस्य नाम निर्दिष्ट किया है।

3. राजस्थान सरकार ने, श्री अशोक भट्टाचार्य, मुख्य पुलिस विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को, उक्त समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है।

4 त्रिपुरा सरकार ने, श्री पी०के० राय, लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्रिपुरा सरकार, अगरतल्ला को, उक्त समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है; और

5. पश्चिमी बंगाल सरकार ने, श्री निर्मल कुमार परमानिक, लोक विश्लेषक (खाद्य और जल), लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता को, उक्त समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 276 (असा०) तारीख 1 अप्रल, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन किया जायेगा, अर्थात :--

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य" शीर्षक के नीचे--

1. क्रम सं० (8) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर "श्रीमती पंकजाक्षी अम्मा, मुख्य सरकारी विश्लेषक, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम, प्रविष्टि रखी जाएगी;

2. क्रम सं० (2) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, "आयुक्त, खाद्य और औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

3 क्रम सं० (17) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, "श्री अशोक भट्टाचार्य, मुख्य पुलिस विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

4. क्रम संख्या (19) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर "श्री पी०के० राय, लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्रिपुरा सरकार, अगरतल्ला" प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

5. क्रम सं० (21) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, "श्री निर्मल कुमार परमानिक, लोक विश्लेषक (खाद्य और जल) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता," प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[संख्या० पी० 15016/1/78-डी.एम.एस.एण्ड पी.एफ.ए.]
विजय भूषण, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th May, 1979

S.O. 1897.—Whereas in pursuance of clause (e) of sub-section (2) of section 3 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954),—

(i) the Government of Kerala have nominated Smt. Pankajakshy Amma, Chief Government Analyst, Government of Kerala, Trivandrum, as a member of the Central Committee for Food Standards,

(ii) the Government of Maharashtra have nominated the Commissioner, Food and Drugs Administration, Government of Maharashtra, Bombay, as a member of the said Committee,

(iii) The Government of Rajasthan have nominated Shri Ashok Bhattacharya, Chief Police Analyst, Rajasthan, Jaipur, as a member of the said Committee,

(iv) the Government of Tripura have nominated Shri P. K. Roy, Public Analyst, Public Health Laboratory, Government of Tripura, Agartala, as a member of the said Committee, and

(v) the Government of West Bengal have nominated Shri Nirmal Kumar Parmanik, Public Analyst (Food and Water), Public Health Laboratory, Government of West Bengal, Calcutta, as a member of the said Committee ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India In the late Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. S.O. 276 (E) dated the 1st April, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading "Members nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 3",—

(i) against Sl. No. (8), for the entry, the entry "Smt. Pankajakshy Amma, Chief Government Analyst, Government of Kerala, Trivandrum." shall be substituted ;

(ii) against Sl. No. (11), for the entry, the entry "Commissioner, Food and Drugs Administration, Government of Maharashtra, Bombay." shall be substituted ;

(iii) against Sl. No. (17), for the entry, the entry "Shri Ashok Bhattacharaya, Chief Police Analyst, Rajasthan, Jaipur," shall be substituted ;

(iv) against Sl. No. (19), for the entry, the entry "Shri P. K. Roy, Public Analyst, Public Health Laboratory, Government of Tripura, Agartala." shall be substituted ; and

(v) against Sl. No. (21), for the entry, the entry "Shri Nirmal Kumar Parmanik, Public Analyst (Food and Water), Public Health Laboratory, Government of West Bengal, Calcutta." shall be substituted.

[No. P. 15016/1/78-DMS&PFA]
VIJAY BHUSHAN, Dy. Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 1979

का० आ० 1898.—भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात एतद्द्वारा निदेश देती है कि एम०डी० (यूनिवर्सिटी आफ अर्लेनजेन), पश्चिमी जर्मनी" की चिकित्सा अर्हता उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

[संख्या० वी० 11016/29/78-एम०ई० (पी०]

(Department of Health)

New Delhi, the 21st May, 1979

S.O. 1898.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the Medical qualification "M. D. L. University of Erlangaa), West Germany" shall be recognised medical qualification for the purposes of that Act.

[No. V. 11016/29/78-M.E. (Policy)]

आदेश

का० आ० 1899.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तारीख 21 मई, 1979 की अधिसूचना सं० वी० 11016/29/78-एम०ई० (पी०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "एमडी० (यूनिवर्सिटी आफ अर्लेनजेन) पश्चिम जर्मनी" की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा० अग्नेज हुबर जिनके पास उक्त अर्हता है शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए फिलहाल श्याम नगर क्रिश्चियन अस्पताल पो० श्याम नगर जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल के साथ सम्बद्ध है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा—

(1) राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि, अथवा

(2) जिस अवधि तक डा० अग्नेज हुबर उक्त श्याम नगर क्रिश्चियन अस्पताल, 24-परगना

पश्चिम बंगाल के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो, उस अवधि को पूर्वोक्त डा० द्वारा मैडिकल प्रैक्टिस के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या वी० 11016/29/78-एम०ई० (पी०)]

ORDER

S.O. 1899.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 11016/29/78-ME(P) dated the 21st May, 1979 the Central Government has directed that the Medical qualification, "M.D. (University of Erlangan), West Germany" shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Agnes Huber who possesses the said qualification is for the time being attached to the Shyamnagar Christian Hospital, P.O. Shyamnagar, District 24 Parganas, West Bengal for the purposes of teaching, research or Charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Agnes Huber is attached to the said Shayamnagar Christian Hospital, 24, Parganas West Bengal;

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/29/78-M.E. (Policy)]

नई दिल्ली, 22 मई, 1979

आदेश

का० आ० 1900.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 जुलाई, 1962 की अधिसूचना सं० 16-5/62-एम-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी आफ जार्जटाऊन, वाशिंगटन, अमेरिका द्वारा प्रदत्त एम०डी० चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी।

और यतः डा० इलीन नीड फील्ड जिनके पास उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल होली फैमिली अस्पताल, मंदर, जिला रांची के साथ सम्बद्ध है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

1. 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि अथवा

2. उस अवधि को जब तक डा० इलीन नीड फील्ड होली फैमिली अस्पताल, मंदर, जिला रांची के साथ संबद्ध रहते हैं, जो भी काम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मैडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे.

[संख्या वी० 11016/6/79-एम ई (पी)]

New Delhi, the 22nd May, 1979

ORDER

S.O. 1900.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-5/62-MI, dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification, M. D. awarded by University of Georgetown, Washington, U.S.A shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) ;

And whereas Dr. Eileen Niedfield who possesses the said qualification is for the time being attached to the Holy Family Hospital Mandar, Ranchi District for the purposes of charitable work ;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the provision to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period upto 31st December, 1979 ; or,

(ii) the period during which Dr. Eileen Niedfield is attached to the said Holy Family Hospital, Mandar, Ranchi District,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/6/79-M.E. (Policy)]

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

का०आ० 1901—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने मैडिकल कालेज अमृतसर की प्रिन्सिपल डा० (कुमारी) सी० फिलिपस को० डा० प्रीतम सिंह के स्थान पर भारतीय आयुर्वेदिक परिषद का सदस्य चुना है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 138 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित "शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"45 डा० (कुमारी) सी० फिलिप्स,
प्रिन्सिपल, मैडिकल कालेज,
अमृतसर।"

[संख्या वी० 11013/12/79-एम०ई० (पी)]

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 1901.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. (Miss) C. Phillips, Principal, Medical College, Amritsar, has been elected by the Guru Nanak Dev University to be a member of the Medical Council of India vice Dr. Pritam Singh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. S. O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3", for Serial Number 45 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be substituted, namely :—

"45. Dr. (Miss) C. Phillips,
Principal,
Medical College, Amritsar."

[No. V. 11013/12/79-M.E. (Policy)

का०आ० 1902—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए रविशंकर विश्वविद्यालय ने पंडित जे०एन०एम० मैडिकल कालेज, रायपुर के डा० एस०एस० गुप्ता को 27 मार्च, 1979 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य चुना हुआ है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 138 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत, क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"34. डा० एस० एस० गुप्ता,
डीन, पंडित जे०एन०एम. मैडिकल कालेज,
रायपुर"

[संख्या वी० 11013/14/79-एम०ई० (पी)]

S.O. 1902.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. S.S. Gupta, Dean, Pt. J.N.M. Medical College, Raipur, has been elected by the Ravishankar University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 27th March, 1979 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138 dated the 9th January, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3", for Serial No. 34 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"34. Dr. S. S. Gupta, Dean, Pt. J. N. Medical College, Raipur."

[No. V. 11013/14/79-M.E. (Policy)]

का० आ० 1903.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) की धारा (ख) के उपबंधों के अनुसरण में बेरहामपुर विश्वविद्यालय द्वारा एम०के०सी०जी० मैडिकल कालेज, बेरहामपुर के प्रिंसिपल प्रोफेसर बी० राजगुरु को 24 मार्च, 1979 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य चुना गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती, है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 39 और उस से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"39. प्रो० बी० राजगुरु,
प्रिंसिपल,
एम०के०सी०जी० मैडिकल कालेज,
बेरहामपुर।"

[संख्या वी० 11013/15/79-एम.ई०(पी)]
आर० वी० श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 1903.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Prof. B. Rajguru, Principal, M. K. C. G. Medical College, Berhampur, has been elected by the Berhampur University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 24th March, 1979 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3", for Serial No. 39 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"39. Prof. B. Rajguru, Principal, M. K. C. G. Medical College, Berhampur."

[No. V. 11013/15/79-M.E.(Policy)]
R. V. SRINIVASAN, Deputy Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1979

का० आ० 1904.—पशु आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) के खण्ड 3, उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 27-5-79 से छः महीने की अवधि के लिए यू० के०, आयरलैण्ड, फ्रांस, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया से अश्वजातीय पशुओं के आयात पर एतद्द्वारा प्रतिबंध लगाती है। यह प्रतिबंध ऐसे युवा पशुओं पर लागू नहीं होगा जिनका कभी मेल नहीं कराया गया है और जो प्रजनन स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहे हैं, बशर्ते कि :—

(क) अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त युवा अश्वजातीय पशुओं के साथ प्राधिकृत पशु-चिकित्सक का इस आशय का पशुचिकित्सा संबंधी एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो कि पशु गत एक वर्ष के दौरान प्रजनन स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहा है और इन पशुओं के लिंगच्छेद तथा मूत्र-द्वारा योनि और सेना विक्स से एकत्र की गई फुरेरी मानक संवर्धनिक-पद्धतियों द्वारा व्याधि विषयक सूक्ष्म अणुओं के लिए नकारात्मक पाई गई हैं, तथा

(ख) भारत में प्राप्त किए जाने पर आयातित पशुओं को स्वामी की परिसर में 30 दिन तक अलग रखा जाएगा, जिसकी सूचना इस मंत्रालय को दी जाएगी। संगरोध की अवधि के दौरान पशुओं की एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जीवाणु विज्ञान संबंधी संवर्धनिक जांच की जाएगी और संक्रामक अश्वजातीय मेट्रिईटिस (कान्टेजियेस इक्वाईन मेटाइटिस) रोग के लिए नकारात्मक घोषित किए जाने के बाद ही इन पशुओं को अन्य पशुओं के साथ मिलाया जाएगा।

[संख्या 50-22/77-एल० डी० टी० (एल० एच० एक्यू)]
वी० पी० कपूर, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 28th May, 1979

S.O. 1904.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Livestock Importation Act 1898 (Act 9 of 1898), the Central Government hereby prohibits for further period of six months with effect from 27-5-79 the import from U.K. Ireland, France, USA and Australia of the equine species of animals except young equines which have never been mated and have not been in contact with breeding stock provided that :

(a) in addition to the health requirements specified under the Act the young equines are accompanied by a Veterinary Health Certificate from an authorised Veterinarian that the animals have not been in contact with the breeding stock during the last one year and that the swabs collected from prepuce and Urethra/Vagina and cervix of these animals were found negative for pathoganic micro-organisms by standard culture-methods, and

(b) on receipt in India, the imported animals are kept in isolation for 30 days at the premises of the owner under intimation to this Ministry. During the quarantine period the animals shall be subjected to bacteriological cultural examination by a recognised laboratory and will be mixed with other stock cnly

when declared negative for contagious equine matrits infection.

[No. 50-22/77 LDT (LH-AQ)]
B. B. KAPOOR, Deputy Secy.

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1979

का० आ० 1905.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचालन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अध्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री पी० एस० माथुर	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	3-4-70 (अपराह्न)
2.	श्री डी० वी० एस० वर्मा	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	11-6-69 (अपराह्न)
3.	श्री सोहन सिंह बडवाल	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	9-4-69 (अपराह्न)

[सं० 52/5/79-एफ० सी० III]
एस० एल० कम्बोह, अवर सचिव

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 31st May, 1979

S.O. 1905.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of pruchase, storage, movement transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of th Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India ;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, he Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section(I) of Section 12A of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the Officer/ employees.	Permanent post held under the Central Government.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the FCI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sh. P.S. Mathur	U.D.C.	U.D.C.	3-4-70(A/N)
2.	Shri D.V.S. Verma	U.D.C.	U.D.C.	11-6-69(A/N)
3.	Sh. Sohan Singh Badwal	U.D.C.	U.D.C.	9-4-69(A/N)

[No. 52/5/79-FC. III]
S. L. KAMBOH, Under Secy.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

का० आ० 1906.—भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) की धारा 8 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली, के कर्मचारियों के लाभ के लिए संस्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे।

[सं० एफ० 3-9/78-सी०ए० I(1)]

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Culture)

New Delhi, the 24th May, 1979.

S.O. 1906.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Gandhi Darshan Samiti, New Delhi.

[No. F. 3-9/78-CAI(1)]

का०आ० 1907.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8क उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संगठन अर्थात् :—

"गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली" का नाम जोड़ती है।

[सं० एफ० 3-9/78-सी०ए० I(1)]
कपिला वात्स्यायन, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

S.O. 1907.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the

Schedule to the said Act the name of the following organisation, namely :—

"The Gandhi Darshan Samiti, New Delhi".

[No. F. 3-9/78-CAI(1)]

KAPILAVATSYAYAN, Joint Educational Adviser

नई दिल्ली, 30 मई, 1979

का० आ० 1908:—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, संस्कृति विभाग की अधिसूचना सं० एस० ओ० 254, दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 को रद्द करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के सुरक्षा अधिकारी को जो कि राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष अधिकारी है उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भू-सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और वह प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत एक भू-सम्पदा अधिकारी को सौंपे गए कार्यों की, विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के लोक परिसर के सम्बन्ध में अपने स्थानीय क्षेत्राधिकारी की सीमाओं के अन्दर-अन्दर निभाएंगे।

[सं० एफ० 13-6/79-सी० ए० 1(5)]

डी० एन० सक्सेना, उप शिक्षा सलाहकार

New Delhi, the 30th May, 1979

S.O. 1908.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occurants) Act, 1971 (4 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India, Department of Culture, No. S.O. 254, dated the 24th December, 1974, the Central Government hereby appoints the Security Officer, Victoria Memorial, Calcutta, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on an estate officer by or under the said Act within the local limits of this jurisdiction in respect of the public premises pertaining to the Victoria Memorial, Calcutta.

[No. F. 13-6/79-CH-5]

D. N. SAKSENA, Deputy Educational Adviser

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 23 मई, 1979

का०आ० 1909.—कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1979 है।

2. कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में—

(क) खण्ड 16 के उपखण्ड (2) की मद (क) में 'विंचवाला' शब्द के स्थान पर "विंच चालक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड 42 में, शीर्षक और उपखण्ड (1), दोनों में, क्रमशः 'विंचमैन" और "विंचवाला" शब्दों के स्थान पर "विंच चालक" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) अनुसूची में, मद (2) की उप मद (ग) में, "विंचवाला" शब्द के स्थान पर "विंच चालक" शब्द रखे जाएंगे।

[फा०सं० एल डी एक्स/14/79]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 23rd May, 1979

S.O. 1909.—The following draft of a Scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Dock Workers (Regulation of employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideraton by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Second Amendment Scheme, 1979.

2. In the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959,—

(a) in item (e) of sub-clause (2) of clause 16 for the word "Winchman" the words "Winch Driver" shall substituted ;

(b) in clause 42, both in the heading and sub-clause (1), for the word "Winchman" the words "Winch Driver" shall be substituted ;

(c) In the Schedule, in sub-item (c) of item (2), for the word "Winchman", the words "Winch Driver" shall be substituted.

[File No. LDX/14/79]

नई दिल्ली, 24 मई 1979

का० आ० 1910.—मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में संशोधन करने के लिए कतिपय स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 3562, तारीख 23 नवम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 9 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 3331–3332 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 19 दिसम्बर, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम—मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956

(i) खण्ड 16 के उपखण्ड (2) की मद (ग) में, 'विंचवाला' शब्द के स्थान पर 'विंच चालक' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड 42 में (जिसमें पार्श्व शीर्ष भी सम्मिलित है) जहां कहीं भी क्रमशः 'विंचवाला और विंचवालों' शब्द आए हैं उन के स्थान पर 'विंच चालक' शब्द रखे जाएंगे,

(iii) अनुसूची 1 में मद (2) की उपमद (ग) में 'विंचवाला' शब्द के स्थान पर 'विंच चालक' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) अनुसूची 2 में "विंचवाला" शब्द के स्थान पर 'विंच चालक" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० एस० डी० एम/17/78]

वी० शंकरलिंगम्, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 1910.—Whereas certain draft scheme to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 3331-3332 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 9th December, 1978, under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 3562, dated the 23rd November, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 19th December, 1978 ;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Second Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956,—

(i) in item (c) of sub-clause (2) of clause 16, for the word "Winchman", the word "Winch Driver" shall be substituted ;

(ii) in clause 42 (including the marginal heading), for the word "Winchman", wherever it occurs, the word "Winch Driver" shall be substituted ;

(iii) in sub-item (c) of item (2) in Schedule I, for the word "Winchman", the word "Winch Driver" shall be substituted ;

(iv) in Schedule II, for the word "Winchman", the word "Winch Driver" shall be substituted.

[No. LDM/17/78]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली 24 मई, 1979

का०आ० 1911.—दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दीपघरों को 'सामान्य दीपघर' घोषित करती है, अर्थात् :—

1. हुमानी प्वाइंट रेकन
2. कच्चीगढ़ रेकन
3. बित्रा दीपघर

[फा०सं० 1-डी (18)/78]

एन०डी० मल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 1911.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 2 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), the Central Government hereby declares the following lighthouses to be 'general lighthouses for the purposes of the said Act, namely :—

1. Humani Point Racon.
2. Kachchigadh Racon.
3. Bitra Lighthouse.

[File No. 1-D(18)/78]

N. D. MALHOTRA, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई 1979

का० आ० 1912.—केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1051 तारीख 6 मई 1972 को अधिक्रांत करते हुए भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उन अधिकारियों को जिनका उल्लेख नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में किया गया है सरकार के राजपत्रित अधिकारी की समतुल्य पंक्ति के अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। ये अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत, स्थानीय अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
दिल्ली (पालम), मुम्बई (सान्ताक्रूज) कलकत्ता (दमदम) और मद्रास (मीनम्बक्कम्) विमानपत्तनों के महाप्रबंधक।	भारत अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है।

[सं० ए०वी० 24011/6/79-ए०ए०]

सी० एम० चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 26th May, 1979

S. O. 1912.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation S.O. No. 1951, dated the 6th May, 1973, the Central Government hereby appoints the officers of the International Airports Authority of India mentioned in Col(1) of the table below, being the officers of equivalent rank of the gazetted officer of Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act within the local jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entries in Column (2) of the said table.

TABLE

Designation of the officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
General Managers of Airports, Delhi (Palam), Bombay (Santacruz), Calcutta (Dum Dum) and Madras (Meenambakkam).	Premises belonging to or taken on lease by and under the administrative control of the International Airport Authority situated within the local limits of their respective jurisdiction.

[No. AV.24011/6/79-AA)]

C.M. CHATURVEDI, Jr. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1979

का०आ० 1913 चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37वां) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी और ग्रेड-1 के स्थानापन्न अधिकारी श्री एस० रामास्वामी को 7-5-79 के पूर्वाह्न से तीन मास की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड मद्रास में अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती है।

[फा०सं० 802/18/79-एफ०सी०]

के०एस० वेंकटरामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd May, 1979.

S.O. 1913.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government is pleased to appoint Shri S. Ramaswamy, a permanent Section Officer and officiating Grade I officer of the Central Secretariat Service, as officiating Additional Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras on an adhoc basis for a period of three months from 7-5-1979 F.N.

[F. No. 802/18/79-FC]

K. S. VENKATARAMAN, Desk Officer

संचार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1979

का० आ० 1914.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3349 दिनांक 15 सितम्बर, 1972 को अधिक्रांत करते हुए निदेश देते हैं कि :—

(1) इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' पदों के बारे में स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(2) उक्त अनुसूची के भाग 2 और 3 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग' और साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'घ' पदों के बारे में स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी, होगा और स्तम्भ 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के बारे में क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

भाग 1 साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख'

पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा वे शास्तियां जो वह (नियम 11 में उल्लिखित सदों के सम्बन्ध में) अधिरोपित कर सकता है।	
		प्राधिकारी	शास्तियां
1	2	3	4
विदेश संचार सेवा (1) सहायक इंजीनियर (2) मुख्य मेकेनीशियन (3) तकनीकी सहायक (4) सहायक विद्युत गृह अधिक्षक (5) वरिष्ठ फोरमैन	महानिदेशक	(1) महानिदेशक (2) उप महानिदेशक (तकनीकी कार्यन्वयन)	सभी (i) –(iv)

1	2	3	4
(6) उप प्रबन्धक (परियात)	महानिदेशक	(1) महानिदेशक (2) उप महानिदेशक (परियात)	सभी (i)—(iv)
(7) परियात लेखा अधिकारी (8) लेखा अधिकारी (9) प्रशासनिक अधिकारी (10) लागत लेखा अधिकारी (11) कनिष्ठ विश्लेषक (12) सहायक प्रशासनिक अधिकारी (13) सुरक्षा अधिकारी (14) परियात लेखापाल	महानिदेशक	(1) महानिदेशक (2) अपर महानिदेशक	सभी (i)—(iv)

टिप्पण :—स्तम्भ (1) में उल्लिखित किसी भी पद पर रत्त निष्क्रिय विदेश संचार सेवा, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में, नियम 11 के उप-खण्ड (v) से (ix) में दी ई किसी भी प्रमुख शास्ति को केवल भारत सरकार अधिरोपित कर सकती है ।

भाग II—साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग'

पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा वे शास्तियां जो वह (नियम 11 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में) अधिरोपित कर सकेगा।		अपीली प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
विदेश संचार सेवा				
(1) कनिष्ठ फोरमैन (2) कनिष्ठ तकनीकी सहायक (3) फोरमैन फिटर (4) वरिष्ठ यान्त्रिक सहायक (5) वरिष्ठ फिटर	उप महानिदेशक (तकनीकी कार्यान्वयन)	(1) उप महानिदेशक (तकनीकी कार्यान्वयन) (2) संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी (i) — (iv)	अपर महानिदेशक उप-महानिदेशक (तकनीकी कार्यान्वयन) [उस दशा में जब कि कार्यालय के प्रधान का पद उप महानिदेशक (तकनीकी कार्यान्वयन) से निम्नतर हो] अन्यथा अपर महानिदेशक]
(6) पर्यवेक्षक (7) वरिष्ठ अन्तरसंचार प्रचालक (8) मुख्य पड़ताल-कर्त्ता (9) कनिष्ठ अन्तरसंचार प्रचालक (10) वरिष्ठ पड़ताल-कर्त्ता	उप-महानिदेशक (परियात)	(1) उप महानिदेशक (परियात) (2) संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी (i)—(iv)	अपर महानिदेशक उप-महानिदेशक (परियात) [उस दशा में जब कि कार्यालय के प्रधान का पद उप-महानिदेशक (परियात) से निम्नतर हो; अन्यथा अपर महानिदेशक]
(11) लागत लेखापाल (12) आशुलिपिक श्रेणी 'क' (13) अधीक्षक (14) आशुलिपिक श्रेणी 'ख' (15) हिन्दी अनुवादक (16) प्रधान लिपिक (17) सहायक परियात लेखापाल (18) वरिष्ठ भंडारी (19) प्रवर श्रेणी लिपिक (अनुभागों के परियात लेखा/सार और प्रशासनिक ग्रुप)	निदेशक (प्रशासन)	(1) निदेशक (प्रशासन) (2) संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी (i)—(iv)	अपर महानिदेशक
(20) कनिष्ठ भंडारी				
(21) पुस्तकालाध्यक्ष				
(22) प्रारूपकार/चयन श्रेणी प्रारूपकार (23) आशुलिपिक श्रेणी 'ग'/चयन श्रेणी आशुलिपिक श्रेणी 'ग' (24) प्रवर श्रेणी लिपिक (अनुभागों के परियात लेखा/सार और प्रशासन ग्रुप')	(i) मुख्यालय (ii) स्विचिंग कम्प्लेक्स बम्बई और शाखा कार्यालय।	(i) निदेशक (प्रशासन) (ii) संबंधित कार्यालय का प्रधान	(i) निदेशक (प्रशासन) (ii) संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी सभी अपर महानिदेशक
(25) मोटर ड्राइवर/चयन श्रेणी मोटर ड्राइवर (26) कनिष्ठ तकनीकी सहायक (27) कनिष्ठ फिटर (28) बढ़ई/चयन श्रेणी बढ़ई (29) राज/चयन श्रेणी राज (30) लुहार	स्विचिंग कम्प्लेक्स बम्बई और शाखा कार्यालय	संबंधित कार्यालय का प्रधान;	संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी उप महानिदेशक (तकनीकी) [उस दशा में जब कि कार्यालय के प्रधान का पद उप-महानिदेशक से निम्नतर हो; अन्यथा अपर महानिदेशक]

1	2	3	4	5
(31) कनिष्ठ पड़ताल-कर्त्ता	स्विचिंग कम्पलेक्स बम्बई और शाखा कार्यालय	संबंधित कार्यालय का प्रधान	संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी उप-महानिदेशक (परियात) [उस दशा में जब कि कार्यालय के प्रधान का पद उप-महानिदेशक से निम्नतर हो; अन्यथा अपर-महानिदेशक]

टिप्पण :—उपर्युक्त स्तम्भ (1) में दिये गए किसी भी पद पर 8 अगस्त, 1961 से पहले नियुक्त किये गए कर्मचारियों के सम्बध में नियम 11 के उप खण्ड (v) से (ix) तक में दी गई कोई भी प्रमुख शास्ति को केवल विदेश सचार के महानिदेशक ही अधिरोपित कर सकते हैं। इसी प्रकार उस समय के उप-महानिदेशक (वित्त और प्रशासन) या उप महानिदेशक (परियात) द्वारा नियुक्त किये गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई भी प्रमुख शास्ति उप महानिदेशक स्तर के या उनसे उच्चस्तर के अधिकारी ही अधिरोपित कर सकते हैं।

भाग III—साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख'

पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा वे शास्तियां जो वह (नियम 11 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में) अधिरोपित कर सकेगा।		अपील प्राधिकारी
		अधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
विदेश सचार सेवा				
सभी पद—मुख्यालय	उप-निदेशक (प्रशासन) संबंधित कार्यालय का प्रधान	उप-निदेशक (प्रशासन) संबंधित कार्यालय का प्रधान	सभी	अपर महानिदेशक
सभी पद—शाखा कार्यालय			सभी	अपर महानिदेशक

टिप्पण :—उस समय निदेशक (प्रशासन) द्वारा नियुक्त किये गए कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई भी प्रमुख शास्ति उप महानिदेशक के स्तर या उनसे उच्चस्तर के अधिकारी ही अधिरोपित कर सकते हैं।

[स० सी० 11012/1/78—ओ० सी० टी० आई० पंजाबी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1979

S.O. 1914 In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Communications No. S. O. 3349 dated the 15th September, 1972, the President hereby directs that:—

(i) in respect of posts in the General Central Service, Group 'B', specified in column (1) of Part I of the Schedule to this order, the authority specified in column (2) shall be the Appointing Authority and the authority specified in column (3) shall be the Disciplinary Authority in regard to the penalties specified in column (4);

(ii) in respect of the posts in General Central Service, Group 'C' and the General Central Service, Group 'D', specified in column (1) of Parts II and III of the said Schedule, the authority specified in column (2) shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns (3) and (5) shall be the Disciplinary Authority and Appellate Authority respectively in regard to the penalities specified in column (4).

SCHEDULE

PART I —GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'B'

Name of the post	Appointing Authority	Authority Competent of Impose Penalties and Penalties which it may Impose (With Reference to item Numbers in Rule 11)	
		Authority	Penalties
(1)	(2)	(3)	(4)
OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE			
(1) Assistant Engineer (2) Chief Mechanician (3) Technical Assistant (4) Assistant Power House Superintendent (5) Senior Foreman	Director General	(i) Director General (ii) Deputy Director General (Technical Operations)	All (i)—(iv)
(6) Deputy Traffic Manager	Director General	(i) Director General (ii) Deputy Director General (Traffic)	All (i)—(iv)

1	2	3	4
(7) Traffic Accounts Officer (8) Accounts Officer (9) Administrative Officer (10) Cost Accounts Officer (11) Junior Analyst (12) Assistant Administrative Officer (13) Security Officer (14) Traffic Accountant	Director General	(i) Director General (ii) Additional Director General	All (i)—(iv)

NOTE: In respect of officers appointed by the now defunct Overseas Communications Service Board of Management, to any of the posts mentioned under column (1), any of the major penalties enumerated in sub-clauses (v) to (ix) of rule 11, can be imposed only by the Government of India.

PART II GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'C'

Name of the post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE				
(1) Junior Foreman (2) Junior Technical Assistant (3) Foreman Fitter (4) Senior Mechanical Assistant (5) Senior Fitter	Deputy Director General (Technical Operations)	(i) Deputy Director General (Technical Operations (ii) Head of Office concerned	All (i)—(iv)	Additional Director General Deputy Director General (Technical Operations) [In case the Head of Office is of a status lower than that of Deputy Director General (Technical Operations); otherwise, Additional Director General]
(6) Supervisor (7) Senior Intelcom Operator (8) Head Checker (9) Junior Intelcom Operator (10) Senior Checker	Deputy Director General (Traffic)	(i) Deputy Director General (Traffic) (ii) Head of Office concerned	All (i)—(iv)	Additional Director General, Deputy Director General (Traffic). [In case the Head of Office is of a status lower than that of Deputy Director General (Traffic) otherwise. Additional Director General]
(11) Cost Accountant (12) Stenographer Grade A (13) Superintendent (14) Stenographer Grade B (15) Hindi Translator (16) Head Clerk (17) Assistant Traffic Accountant (18) Senior Storekeeper (19) Upper Division Clerk (Traffic Accounts/Abstract and Administrative Group of Sections) (20) Junior Storekeeper (21) Librarian	Director (Administration)	(i) Director (Administration) (ii) Head of Office concerned	All (i)—(iv)	Additional Director General
(22) Draftsman/Selection Grade Draftsman (23) Stenographer Grade C/ Selection Grade Stenographer Grade C (24) Lower Division Clerks (Traffic Accounts/Abstract and Administrative Group of Sections) (25) Motor Driver/Selection Grade Motor Driver	(i) Headquarters Office (ii) Switching Complex, Bombay and Branch Offices.	(i) Director (Administration) (ii) Head of Office concerned	(i) Director (Administration) All (ii) Head of Office concerned All	Additional Director General

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
(26) Junior Mechanical Assistant (27) Junior Fitter (28) Carpenter/Selection Grade Carpenter (29) Mason/Selection Grade Mason (30) Blacksmith	Switching Complex, Bombay and Branch Offices.	Head of Office concerned	Head of Office concerned	All	Deputy Director General (Technical Operations) (In case, the Head of Office is of a status lower than that of Deputy Director General otherwise, Additional Director General).
(31) Junior Checker	Switching Complex, Bombay and Branch Offices.	Head of Office concerned	Head of Office concerned	All	Deputy Director General (Traffic) (In case the Head of Office is of a status lower than that of Deputy Director General; otherwise Additional Director General.

NOTE: In respect of officials appointed prior to 8th August, 1961 to any of the posts mentioned in column (1), any of the major penalties enumerated in sub-clause (v) to (ix) of rule 11 can be imposed only by the Director General, Overseas Communications Service. Similarly, in respect of those appointed by the Deputy Director General (Finance and Administration), or Deputy Director General (Traffic), only of the major penalties can be imposed only by an officer of the rank of Deputy Director General or above.

PART III—GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'D'

Name of the post	Appointing Authority	Authority Competent to Impose Penalties and Penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Panalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE				
All Posts—Headquarters	Deputy Director (Administration)	Deputy Director (Administration)	All	Additional Director General
All Posts—Branch Offices	Head of Office concerned	Head of Office concerned	All	Additional Director General

NOTE: In respect of officials appointed by the then Director (Administration), any one of the major penalties can be imposed only by an officer of the rank of Deputy Director General or above.

[No.C.11012(1)/78-OC]
T.I. PUNJABI, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1979

का० आ० 1915.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 1950 का 31 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा इस विभाग में बन्दोबस्त विंग में कार्य कर रहे बन्दोबस्त आयुक्त श्री डी० सी० चहल को उक्त अधिनियम द्वारा या, उसके अधीन उप अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों निष्पादन करने हेतु उन राज्यों के लिए जिनमें उक्त अधिनियम लागू होता है, उप अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

[सं० 1 (26)/विशेष सेल/77 एस० एस०-II]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION
(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 25th May, 1979

S.O. 1915.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints Shri D. C. Chahal, Settlement Officer in the Settlement Wing of this Depatrment as Deputy Custodian of Evacuee Property for the States to which the aforesaid Act applies for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian by or under the said Act wtih immediate effect.

[No. 1(26)/Spl. Cell/77-SS.II]

का० आ० 1916.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 1950 का 31 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा इस विभाग के बन्दोबस्त विंग में सहायक बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे श्री प्रीतम सिंह को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपर अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने हेतु उन राज्यों के लिए जिनमें उक्त अधिनियम लागू होता है, अपर अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

यह अधिसूचना सं० ए-36016 (1) /75 प्रशा० (राज)/सं०वि/76 दिनांक 19-5-78 का अतिक्रमण करती है।

[सं० 1 (28)/विशेष सेल/77-एस० एस०-II]

दीना नाथ आसीजा, संयुक्त निदेशक

S.O. 1916.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Pritam Singh, Assistant Settlement Commissioner in the Settlement Wing of this Department as Additional Custodian of Evacuee Property for the States to which the aforesaid Act applies for the purpose of discharging the duties imposed on such Additional Custodian by or under the said Act with immediate effect.

This supersedes notification No. A-36016(1)/75-Ad. (GZ)/SW/76 dated 19-5-1978.

[No. 1(26)/Spl.Cell/77-SS.II]

D. N. ASIJA, Jt. Director

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd May, 1979

S.O. 1917.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No.1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Golukdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad, and their workman, which was received by the Central Government on the 18th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD.

In the Matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 12 of 1978.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Golukdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 10th May, 1979.

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-20012/246/77-D. III(A), dated, the 11th July, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Golukdih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad, in dismissing Shri Sagir Mian, Bhatta Mazdoor, with effect from 23rd September, 1976, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The parties have filed a settlement. The terms of the settlement are verified. They appear to be proper and just. The award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

[No. L-20012/246/77-D.III(A)]

SETTLEMENT

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In Ref. No. 12 of 1978

Employers in relation to Golukdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their Workman represented by RCMS Union.

Joint petition of compromise settlement :

The humble petitioners on behalf of the parties above named most respectfully beg to state that the instant dispute has amicably been settled between the parties on the terms stated below :—

Terms of Settlement

1. The parties agreed that Sri Sagir Mia will be re-instated in his respective post at Golukdih colliery of Bhart Coking Coal Ltd. Area IX within 15 days of his reporting for duty to the General Manager, Area IX.

2. The parties agreed that the continuity of service of the concerned workman shall be maintained and the period of his idleness from the date of dismissal to that of re-instatement shall be treated as leave without pay.

3. The parties agreed that they shall have no other claim what-so-ever against each other on account of the present dispute which stands fully and finally resolved by this settlement.

The petitioners pray that the Honourable Tribunal may be pleased to accept the above settlement and to pass award in terms thereof.

For Management :

Sd/-

1. R. SINGH, General Manager, Area IX.

Sd/-

2. M. N. SINGH, Personnel Manager, Area IX

For workman :

Sd./-

1. MAHARAJ SINGH, Secretary, RCMS, Golukdih Colliery Branch.

Sd./-

2. SAGIR MIA, the concerned workman.

Witness :—

Sd/-

1. B. D. SINGH, Sr. P.O. Area No. IX.

Sd/-

2. SABHAPATI SINGH, Asstt. Secretary, RCMS, Golukdih Colliery Branch

Sd./-ILLEGIBLE
For employees

Sd./-ILLEGIBLE
For workman

S.O. 1918.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 68 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jealgora, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen—None.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, the 8th May, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/89/76 DIIIA dated 22nd November, 1976, for the adjudication of the following industrial dispute.

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jealgora, Dist. Dhanbad in dismissing Shri Basudeo, Fan Khalasi with effect from 24th April, 1975, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

2. Short facts of the case are that the delinquent was charge-sheeted for absence from duty on 22-2-1975 at 11 a.m. That enquiry was pending when on 24-3-1975 he assaulted Shri Ajit Singh, Junior Engineer with a stick at pit no. 7. He was charge-sheeted and was found guilty after domestic enquiry. Dismissal from service was the punishment inflicted upon him by the disciplinary authority. This reference relates to this domestic enquiry arising out of the incident of assault which resulted in the dismissal of the delinquent.

3. Not knowing that the delinquent died on 29-7-1978 as has now been certified by the head-man of the village, learned counsel for the union declared on 8-8-1978 that he would not adduce any oral or documentary evidence on the preliminary question of regularity and propriety of the enquiry. D.E. papers were examined and after hearing the arguments of the parties it was held that the domestic enquiry was valid and proper. That decision was not vitiated on account of the death of the delinquent prior to it, because delinquent was not a party to the case. The dispute had been sponsored by the union which was duly represented in the case on 8-8-1978 even after the death of the delinquent.

4. After holding that the domestic enquiry was valid and proper the only question left for consideration at this final stage was the question of quantum of punishment. The death of the delinquent has rendered the determination of that question unnecessary. Firstly, assault on an officer at the work place simply because he detected his absence from duty, did justify an order of dismissal. Secondly, even if some compassionate view is taken on proof of certain circumstances the reduced rigor of punishment will have no meaning for a deceased employee. Service is a personal right and it dies with the party. The heirs could only have interest in money benefit in a case of reinstatement with back wages but that possibility is ruled out in the circumstances of the present case.

5. It is therefore held that the domestic enquiry was valid and proper which called for a punishment of dismissal though the finding on the quantum of punishment has now been rendered infructuous because of the death of the delinquent. No money benefits survive to the heirs of the deceased. The award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-20012/89/76-D-III(A)]

S.O. 1919.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dobari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Offic Jharia, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3 AT DHANBAD

Reference No. 13 of 1978

In the matter of an industrial dispute u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dobari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen.—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 9th May, 1979

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Doari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen. Accordingly they, by order No. I-20012/130/77-D. III(A), dated 9th February, 1978 referred the said dispute to this Tribunal u|s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication with the following issue framed :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dobari colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad in terminating the services of Shri Sukar Singh, Miner with effect from 29th June, 1976 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

After receipt of the reference written statement was filed by the employers and the union prayed for time for filing written statement. Ultimately on 9-5-1979 a joint petition of compromise was filed by the parties incorporating therein the terms of settlement arrived at between them in respect of the industrial dispute pending for adjudication in this Tribunal. The contents of the joint petition of compromise were verified as correct from the side of the workmen by Shri G. D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh and Shri B. D. Singh, Senior Personnel Officer, Bharat Coking Coal Limited. I heard the parties on the joint petition and it is prayed before me that an award may be passed in terms of the settlement as filed. It appears that the settlement in its turn has been signed by the authorised representative of Bharat Coking Coal on behalf of the employers and Shri G. D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh presenting the workmen and also thumb impressed by the workmen actually concerned in the Reference. The terms of the settlement, beneficial as they are to the parties, are accepted. Nothing therefore stands in the way of an award being passed on the basis of the settlement. Accordingly I pass the Award in terms of the settlement which do form a part of the Award as Annexure 'A'.

J. P. SINGH, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD

In Ref. No. 13 of 1978

Employers in relation to Dobari colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their workman represented by R.C.M.S. Union

Joint Petition of compromise settlement

The humble petitioners on behalf of the parties above named most respectfully beg to state that the instant dispute has amicably been settled between the parties on the terms stated below :—

Terms of Settlement

1. The Parties agreed that Shri Sukar Singh will be re-instated in his respective post at Dobari colliery of Bharat Coking Coal Limited, Area No. IX within 15 days of his reporting for duty to the General Manager, Bastacolla Area IX.

2. The Parties agreed that the continuity of service of the concerned workman shall be maintained and the period of his idleness from the date of dismissal to that of re-instatement shall be treated as leave without pay.

3. The parties agreed that they shall have no other claim what-so-ever against each other on account of the present dispute which stands fully and finally resolved by this settlement.

The petitioner pray that the Honourable Tribunal may be pleased to accept the above settlement and to pass award in terms thereof.

For management :	For Workman .
Sd/-	Sd/-
1. (R. Singh)	1. (G. D. Pandey)
General Manager, Area IV.	Secretary, R.C.M.S.
Sd/-	L.T.I.
2. (M. N. Singh)	2. (Sukar Singh), Miner,
Personnel Manager-IX.	The Concerned Workman
Witness :	I verify the signature of the
Sd/-	employers and workmen's re-
1. (B. D. Singh)	presentative and the L.T.I. of
Sr. Personnel Officer-IX.	the workman concerned.
Sd/-	Sd/- ILLEGIBLE.

2. (Tulshi Singh)

C. C. M. Driver, I/D. Card

No. 235251

[No. L-20012/130/77-D-III(A)]

New Delhi, the 29th May, 1979

S.O. 1920.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri Sudhir Prasad Singh, Clerk, Accounts Department of Indian Iron & Steel Company Limited, Chasnala Colliery, Post Office Patherdih, District Dhanbad, which was received by the Central Government on the 26th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

Complaint No. 5 of 1975

In the matter of a Complaint under Section 33-A of the **Industrial Disputes Act, 1947**

PARTIES :

Shri Sudhir Prasad Singh, Clerk,
Accounts Department of Indian Iron & Steel Co. Ltd.,
Chasnala Colliery, P.O. Patherdih, Dist. Dhanbad.

...*Complainant*

Vs

The Indian Iron & Steel Company Ltd.,
Chasnala Colliery through its Chief Executive Officer,
Chasnala Colliery, P.O. Patherdih, District : Dhanbad.

..Opp. Party

APPEARANCES :

On behalf of the complainant—Shri B. N. Sharma, Jt. General Secretary, Janata Mazdoor Sangh, Jharia, Dhanbad.

On behalf of the Opp. Party.—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 23rd May, 1979

AWARD

This is a complaint filed by Shri Sudhir Prasad Singh, Clerk, Accounts Department under Section 33-A of the I.D. Act, 1947 against the opposite party employers. The case proceeded along its course. Ultimately on 21-5-1979 when the case was fixed for hearing, Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary, Janata Mazdoor Sangh on behalf of the complainant filed a petition for withdrawal of the complaint petition on the ground that the complainant case was likely to be settled between the parties mutually. In view of the above submissions made by the complainant I dismiss the complaint petition as withdrawn.

J. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20025/18/79-D.III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 23rd May, 1979

S.O. 1921.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employer in relation to the management of Hindustan Lalpeth Colliery, Chandrapur (Maharashtra) and their workmen which was received by the Central Government on 14th May, 1979.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, B.Sc., LL.M., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP.)

Case No. CGIT/LC(R)(10) of 1971

PARTIES :

Employers in relation to the management of Hindustan Lalpeth Colliery, Chandrapur (Maharashtra) and their workmen, represented through the President, Maharashtra Pradesh Rashtria Koyala Khadan Kamgar Sangh, Jatpura Gate No. 1, Chandrapur (Maharashtra).

APPEARANCES :

For Workmen.—Shri B. K. Tiwari, Advocate.

For Management.—Shri P. S. Nair, Advocate.

Industry : Coal Mine. *District : Chandrapur (M.S.)*

AWARD

Jabalpur, the 28th April, 1979

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its order No. 1/42/70-LR.II, dated 7th April, 1971, for the adjudication of the following dispute by this Tribunal :—

"Whether the strike resorted to by the Maharashtra Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Kamgar Sangh, Chandrapur from the 13th April, 1970 to the 25th April, 1970 in the Hindustan Lalpeth Colliery, Post Office Chandrapur was legal ?".

2. It is not disputed that the Company is a public utility service carrying on coal mining industry and at the same time it renders material service to the community by pumping out water from the mine for being supplied to the citizens of Babupeth and surrounding locality. Substantially large number of workers of this industry are the members of Maharashtra Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Kamgar Sangh (hereinafter we called the Sangh) Chandrapur, which is a general union of the coal mine workers. The Sangh served two notices of demand, one supplementing the other, raising in all 19 demands with the management on 24th and 25th March, 1970 and threatened to proceed on strike with effect from 13-4-1970 if the demands were not conceded. The management informed the Government and conciliation proceedings started. The failure report was received by the Government on 13th April, 1970 on which date the workers proceeded on strike. The strike was celled off and the workers resumed work with effect from 27th April, 1970. They had thus remained on strike from 13th April, 1970 to 26th April, 1970 (both days inclusive). While calling off the strike there was an agreement between the parties. The relevant clauses of which may be reproduced as follows :—

"(i) Both the parties are free to approach the competent authorities to get the declaration on the legality or otherwise of the strike and payment of wages for the lay off period after resumption of work.

(ii) The management agrees not to take any action against the workers till the decision as clause IV and the Union also agree not to agitate over this issue till the decision of clause IV".

As the pay for the strike period has been withheld pending declaration of legality of the strike as per above clauses of the agreement, the Central Government made this reference.

3. According to the management the strike was illegal because :—

(i) it was brought about before the conclusion of conciliation proceedings ;

(ii) it started before the expiry of the period prescribed by Section 22 of the Industrial Disputes Act ;

(iii) it commenced within 7 days of the conclusion of the conciliation proceedings contrary to the provisions of Section 22-D of the Industrial Disputes Act ; and

(iv) the strike commenced during the period in which award dated 11th August, 1969 passed by the Central Government Industrial Tribunal in Reference No. 4 of 1969 was in operation and had not been set aside.

4. The Sangh alleged that the reference was bad because, dispute was not an industrial dispute, the reference was merely for declaration, and the reference contemplates strike by the Union when in fact only the workers, and not the Union, could go on strike. The Sangh raised yet another legal objection against validity of the reference saying that the agreement dated 27-4-1970 contemplated the declaration as to the legality of the strike to be made by the Central Government and not by a Tribunal. The Sangh further alleged that the stand of the management throughout was unreasonable and the workers were left no alternative but to strike the work. Factum of non prosecution of the officers of the union makes it evident that the Sangh was not at fault in the matter.

5. A writ petition No. 618/1971 was filed by the union before the High Court of Madhya Pradesh which had granted stay of the proceedings before the Tribunal. After about 7 years it was ultimately dismissed as withdrawn on 7th July, 1978. Thereafter inspite of several notices neither party has taken any interest in the reference.

6. As per agreement dated 27-4-1970 the dispute about legality or otherwise of the strike was left open and the parties were left free 'to approach the competent authorities to get the declaration on that point'. The matter was not left to the Central Government for giving an award as arbitrator. The dispute, so left open, was certainly an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act as it was a dispute between the employers and the employees connected with the employment, non-employment or the terms of the employment. The objection of the Sangh in this respect has thus no force.

7. The other objection raised by the Sangh is that the reference speaks of the strike being resorted to by the Sangh whereas in fact only the workers could go on strike. When the reference speaks of the resorting of the strike by the Sangh it clearly means the resorting of the strike by a body of persons employed in the industry acting in combination which is the essence of the definition of strike given in Section 2(q) of the Industrial Disputes Act. As such there is no ambiguity confusion or illegality in the order of reference. The objection of the Sangh raised in this respect is again rule out.

8. After dealing with these preliminary objections there remains no substantial dispute about the legality of the strike because the Sangh has not said anything in reply to the objections against the legality of the strike raised by the management. It is not denied by the Sangh that the Company was a public utility service. Section 22 of the Industrial Disputes Act prohibits strike in a public utility service without giving to the employer a notice of strike, and —

(c) before the expiry of the date of the strike specified in any such notice as aforesaid, or

(d) during the pendency of any conciliation proceeding and 7 days after the conclusion of such proceedings.

There was breach of all these provisions in the present case. The strike notice contemplated what the strike was to commence on 13th April, 1970. According to Section 22(1)(c) it should not have therefore commenced till the expiry of that date. It is not disputed that the failure report of the conciliation proceedings held on strike notice, reached the Government on 13th April, 1970. According to Section 20(2)(b) the conciliation proceedings shall be deemed to conclude on the date on which the failure report is received by the Appropriate Government. Thus the strike commenced on the very day on which the report was received.

The day should have been excluded. Moreover according to Section 22(1)(d) the strike could not commence till after the expiry of 7 days from the above date of conclusion of conciliation proceedings. No legal strike could therefore commence till 20th April, 1970.

9. It follows that as per Section 24(1)(i) the strike was illegal because it commenced in contravention of Section 22 of the Industrial Disputes Act. The reference is answered accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

Dated : 28-4-1979.

[No. 1/42/70-LR-II-D.IV-B]

SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

का०आ० 1922.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में वर्ष 1978-79 के दौरान कोयला खान श्रमिक आवासन और साधारण कल्याण निधि के साधारण कल्याण लेखा में प्राप्तियों और उसमें से व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन और वर्ष 1976-77 का लेखा विवरण तथा उक्त निधि के साधारण कल्याण लेखा में से वर्ष 1976-77 के दौरान विनियोजित क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रकाशित करती है, अर्थात्

भाग-I

1978-79 के दौरान प्राप्तियों और व्यय का प्राक्कलन

साधारण कल्याण लेखा

प्राप्ति	व्यय
4,38,28,000 रु०	5,09,65,000 रुपए (इसमें उधार के 1,01,000 रुपए भी सम्मिलित है)

भाग II

वर्ष 1977-78 के लिये लेखा-विवरण

साधारण कल्याण लेखा

	प्राप्ति	व्यय
1. 1-4-1977 को आदि अतिशेष	2,02,93,000	
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	4,30,93,000	
3. वर्ष के दौरान व्यय		3,91,96,000
4. 31-3-1978 को अंतिम अतिशेष		3,31,90,000

वर्ष 1977-88 के क्रियाकलापों पर हुए व्यय के आंकड़ों का क्रियाकलापों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है —

	(हजार रुपयों में)
1. प्रशासन	27.09
2. स्वास्थ्य	281.91
3. शिक्षा	32.80
4. जल प्रदाय	97
5. आमोद-प्रमोद	5.35
6. विभिन्न सहायता	1.74
7. सहकारी संस्थाएं	3.28
8. भूमी परिवहन	1.25
9. भूमी परिवहन	23
10. एन०सी०एस०एम० को अनुदान	6.00
11. शुल्क का प्रतिदाय	22.43
12. संग्रहण प्रभार	5.91
योग	391 96

टिप्पण :—ऊपर दिखाए गए आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि 1977-78 का लेखा अभी बन्द नहीं किया गया है।

भाग III

वर्ष 1977-78 के दौरान किए गए विनियोजित क्रियाकलापों की रिपोर्ट

1. **चिकित्सा सुविधायें :**

(क) धनबाद (बिहार) (300 शैयाएं), आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) (350 शैयाएं) और मनेन्द्रगढ़ (मध्य प्रदेश) (100 शैयाएं) स्थित केन्द्रीय अस्पताल और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 18 से 50 तक शैयाओं वाले बारह क्षेत्रीय अस्पताल कार्य करते आ रहे लगभग 7 लाख रोगियों का संगठन के चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क इलाज किया गया। अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं कोयला खान उद्योग में नियोजित लगभग 10,000 आश्रितों को भी दी गई हैं। महाराष्ट्र के चांदा कोयला क्षेत्र में हिन्दुस्तान लालपेठ कोयला खान में उक्त क्षेत्र के 14,000 खनकों के फायदे के लिए 50 शैयाओं का एक क्षेत्रीय अस्पताल भी स्थापित किया जा रहा है। तलचर कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीय-कोयला विकास निगम के अस्पताल में संघ द्वारा उस कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल की व्यवस्था के विकल्प के रूप में यथोचित आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान देकर एक विशेष वार्ड की व्यवस्था के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(ख) औषधालय : मुख्य कोयला क्षेत्र (बिहार) में एक एलोपैथिक स्थायी औषधालय, असम कोयला क्षेत्र में एक चल चिकित्सा एकक और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 29 आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते रहे हैं। अपेक्षित आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए झरिया कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय आयुर्वेदिक औषधालय भी कार्य करता रहा है। औषधालय-वार इलाज किए गए रोगियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) परिवार कल्याण और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र :— संगठन के तीन केन्द्रीय अस्पतालों और क्षेत्रीय अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल से सम्बद्ध परिवार कल्याण और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र कार्यरत रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन द्वारा पहले से ऐसे दो केन्द्र, एक बारजोलाई (असम) में और एक तलचर (उड़ीसा) अहिन महिला स्वास्थ्य परिदर्शकों के भार-साधन में स्वतन्त्र एककों के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। चांदा कोयला क्षेत्र में कोयला खान (महाराष्ट्र) के कर्मकारों के फायदे के लिए सरकारी अस्पताल, चांदा से सम्बद्ध ब्लाक बराबर काम करता रहा है।

(घ) औषधालय सेवाओं को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता :— कोयला खान के कर्मकारों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए कोयला खानों में औषधालयों का स्तर बनाए रखने/सुधारने के लिए कोयला खान प्रबन्धकों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान देने की स्कीम चालू रखी गई है तथा कोयला खान प्रबन्धकों को इस वर्ष के दौरान कोयला खान कर्मकारों के लिए औषधालय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए 6.53 लाख रुपए की रकम दी गई है।

(ङ) यक्ष्मा के रोगियों के लिए इलाज :—यक्ष्मा से पीड़ित कोयला खान कर्मकारों और उनके आश्रितों का इलाज, संगठन के 312 शैयाओं वाले 4 यक्ष्मा अस्पतालों में किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके लिए विभिन्न यक्ष्मा आरोग्याश्रमों में 56 शैयाएं आरक्षित रखी गई। यक्ष्मा के इलाज की स्कीम चालू रखी गई है और इस स्कीम के अधीन इलाज कराने वाले यक्ष्मा रोगियों को निर्वाह भत्ता भी दिया जाता रहा है। उस अवधि के दौरान इस स्कीम पर 2.69 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

(च) खनन क्षेत्रों में परिवार कल्याण संबंधी क्रियाकलाप :—प्रबंधकों और कोयला खान श्रम कल्याण संगठन ने विभिन्न कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों के लिए भारतीय श्रम संगठन/संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन परियोजनाओं के सहयोग से 29 परिवार कल्याण केन्द्रों पर वर्तमान परिवार कल्याण कार्यक्रम चालू रखा गया है। रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान नगर पालिका अस्पतालों और शिशु स्वास्थ्य रक्षा (केन्द्रों) को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। इन सभी अस्पतालों में नसबन्दी आपरेशन किए जा रहे हैं। विभिन्न खानों में तैनात किए गए प्रसार शिक्षकों को अस्पतालों से सम्बद्ध कर दिया गया है और वे पात्र दम्पत्तियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं तथा उनको नसबन्दी आपरेशन के लिए अभिप्रेरित करने और परिवार कल्याण पद्धति के उपाय अपनाने में उन्हें शिक्षित करने के लिए कर्मकारों के निवास स्थानों पर जाते रहे हैं। कार्यक्रम को सुचारु ढंग से चलाने के लिए अस्पतालों को आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए जाते रहे हैं। रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान 185 नसबन्दी और 1698 ट्यूबेक्टोमी के आपरेशन किए गए। इसके अतिरिक्त 1,28,583 पर परम्परागत निरोध वितरित किए गए।

(छ) पुनर्वास :—धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में से प्रत्येक से सम्बद्ध पुनर्वास केन्द्र कार्य करते रहे हैं। मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में छिन्दवाड़ा में पुनर्वास केन्द्र भी कार्य करता रहा है। कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के सहयोग से छिन्दवाड़ा में कृत्रिम अंग विनिर्माण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव के संबंध में भी प्रगति हुई है। पश्चिमी बंगाल में सिधवाड़ी में पुनर्वास एवं उल्लासगृह इस वर्ष के दौरान कार्य करता रहा है।

(ज) अन्य चिकित्सा सुविधाएं :—चिकित्सीय और लोक स्वास्थ्य के लिए, संगठन के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप थे, कैंसर कुष्ठ रोग, मानसिक रोग आदि रोगों के इलाज के लिए सुविधाएं जुटाना, धनबाद और आसनसोल स्थित केन्द्रीय अस्पतालों में रक्त बैंक चलाना, कोयला खान कर्मकारों को चश्मों और कृत्रिम दंतावली निशुल्क देना तथा मलेरिया और फाइलेरिया नियंत्रण कार्य, इत्यादि।

(झ) उन कोयला खनकों के जो खानों में गंभीर/प्राणान्तक दुर्घटनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं, आश्रितों को सहायता देने की स्कीम चालू रखी गई है। एक मुश्त रकम और मासिक भत्ते दिए जाने के अलावा ऐसे कोयला खनिकों के बालकों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। संगठन के चिकित्सीय संस्थानों में ऐसे आश्रितों के निशुल्क चिकित्सीय इलाज के लिए भी सुविधाएं दी जाती रही हैं।

2. शिक्षा तथा आमोद-प्रमोद विषयक सुविधाएं :—(क) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश में लाने वाले कुछ सुसंगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1. बहुउद्देश्यीय संस्थाएं	60
2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	3
3. महिला कल्याण केन्द्र	4
4. पोषक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	163
5. कोयला खान कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति	522
6. औ०प्र०सं० में प्रशिक्षण के लिए कोयला खान कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति	25
7. कोयला खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास	1
8. अवकाश गृह	2

(ख) खेल और क्रीड़ा :—कोयला खान कर्मकारों के मनोरंजन के लिए प्रति वर्ष खेल और क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1977-78 के दौरान विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं के आयोजन के लिए संगठन ने 1.80 लाख रु० खर्च किए हैं।

(ग) अन्य क्रियाकलाप :—इस संबंध में की गई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं में, (1) शिक्षा संस्थाओं को सहायता अनुदान (2) फिल्मों का प्रदर्शन, और (3) अनुमोदित स्कीमों के अनुसार कोयला खनकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां अनुदत्त करना है।

(घ) खानों में होने वाली दुर्घटनाओं से मरने वाले कर्मकारों की पत्नियों और उनके स्कूल जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए उपबन्ध।

3(क) जल प्रदाय स्कीम: इस वर्ष के दौरान जल प्रदाय स्कीमों पर 66,850.00 रुपए की राशि खर्च की गई थी। संगठन, कोयला खानों, प्रबन्धकों, को संवीक्षित व्यय की कुल रकम का 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान देता रहा है जैसा कि जल प्रदाय स्कीम में विहित है। पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित और निधि द्वारा अंशत: वित्त पोषित दो एकीकृत जलप्रदाय स्कीमों में से पूर्ववर्ती एक स्कीम का कार्य आरम्भ हो चुका है और पश्चातवर्ती स्कीम निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित दो प्रमुख जल प्रदाय स्कीमें हैं अर्थात् :— (i) छिंदवाड़ा जिला में पेंच घाटी जल प्रदाय स्कीम, और (ii) सुगना कोयला क्षेत्र में कुमाम व्रुव, चिरकुंडा क्षेत्र जल प्रदाय स्कीम। सुगना कोयला क्षेत्र में जल प्रदाय स्कीम पर, संबंधित राज्य का इन पर कुल परिव्यय 3.70 करोड़ रु० है। सरकारों के परामर्श से, सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) कुएं खोदना :—रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान अब तक कुल 333 कुएं बनाए जा चुके हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र की विभिन्न कोयला खानों में 14 कुएं खोदने के लिए मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को 30,620.00 रु० दिए गए थे।

4. सहकारी आन्दोलन :—इस वर्ष के दौरान कोई भी नए प्राथमिक भण्डार, सहकारी प्रत्यय सोसाइटी और थोक या केन्द्रीय सहकारी भण्डार नहीं खोले गए। समीक्षाधीन अवधि के अन्त में कोयला खान कर्मकारों के सहकारी भण्डारों और प्रत्यय सोसाइटियों की संख्या 491 था। इनमें पहले से खोले गए 10 थोक या केन्द्रीय सहकारी भंडार भी सम्मिलित है और वे कोयला खान कर्मकारों के लिए कार्य करते रहे हैं।

[सं० जेड-16016/3/78-एम-2]
पी० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 24 May, 1979

S. O. 1922.—In pursuance of sub-section (5) of Section 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts into and expenditure from the General Welfare account of the Coal Mines Labour Housing

and General Welfare Fund during the year 1978-79 together with a statement of the account for the year 1977-78 and a report of the activities financed during the year 1977-78 from the general welfare account of the said Fund, namely:—

PART I

Estimates of receipts and expenditure during 1978-79.

GENERAL WELFARE ACCOUNT

Receipt	Expenditure
Rs. 4,38,28,000	Rs. 5,09,65,000 (including loans of Rs. 1,01,000)

PART II

Statement of account for the year 1977-78

GENERAL WELFARE ACCOUNT

	Receipt.	Expenditure
1 Opening balance as on 1.4.1977	2,92,93,000	
2. Receipts during the year	4,30,93,000	
3. Expenditure during the year		3,91,96,000
4. Closing balance as on 31.3.1978.		3,31,90,000
TOTAL :	7,23,86,000	7,23,86,000

The break-up of activity-wise expenditure figures for 1977-78 is as under :

	(in thousands of rupees)
1. Administration	27,09
2. Health	281,91
3. Education	32,80
4. Water Supply	97
5. Recreation	5,35
6. Financial assistance	4,74
7. Cooperatives	3,28
8. Bhuli Township	1,25
9. Bhuli Transport	23
10. Grant to N.C.S.M.	6,00
11. Refund of cess	22,43
12. Collection charges.	5,91
	391,96

N.B. The figures shown above are provisional as the accounts for 1977-78 have not yet been closed.

PART III

Report on the activities financed during the year-1977-78

MEDICAL FACILITIES

(a) The Central Hospitals at Dhanbad (Bihar) (300 beds), Asansol (West Bengal) (350 beds) and Manendragarh (M.P.) Bihar (100 beds) and twelve Regional Hospitals with bed strength varying from 18 to 50 beds continued to function in different coalfields. Approximately about 7 lakhs patients were treated at the medical institutions of the Organisation free of charge. Indoor medical facilities have also been extended to about 10,000 sweepers employed in coal mining industry. A 50 beds Regional Hospital at Hindustan Lalpeth Colliery in Chanda Coalfield in Maharashtra is also being set up for the benefit of 14,000 miners in that area. Provision of a specialised ward in the National Coal Development Corporation's Hospital in Talcher Coal-field by giving suitable recurring and non-recurring grant as an alternative to Organisation's providing a Regional Hospital in that coalfield has been sanctioned.

(b) Dispensaries : One Allopathic static Dispensary in Mugma Coalfield (Bihar), one Mobile Medical unit in Assam Coalfields and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coalfields were continued. A Central Ayurvedic Pharmacy in Jharia Coalfield to manfacture required Ayurvedic medicines also continued to function.

(c) Family Welfare and Maternity and Child Welfare Centre:— A Family Welfare and maternity and child welfare centre attached to each of the three Central Hospitals and the Regional Hospitals of the Organisation remained in operation, Besides 2 such centres, one each at Nargolai (Assam) and Talcher (Orissa already established by the Organisation also continued to function as independent units under the charge of qualified Lady Health Visitors. For the benefit of the colliery workers in Chanda Coalfield, (Maharashtra) the block attached to the Government Hospital, Chanda continued to function.

(d) Financial assistance for improving dispensary service :— With a view to encourage the colliery managements for maintaining/improving the standard of dispensaries at the collieries for the benefit of colliery workers and ther dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued and a sum of Rs. 6.53 lakhs was paid to the colliery managements during the year for providing medical facilities to the colliery workers.

TREATMENT FOR T.B. PATIENTS :—The Colliery workers and their dependents suffering from T.B. were treated in the Organisations 4 T.B. Hospitals with bed strength of 312 beds. Besides 56 beds remained reserved for them in different T.B. Sanatoria. The Scheme of Demiciliary T.B. treatment also continued to function including payment of subsistence allowance to the T.B. patients undergoing such treatment. A sum of Rs. 2.69 laks was spend approximately on this Scheme during the period.

(f) Family Welfare activities in the Mining areas.—This existing Family Welfare programme has been continued at 29 family welfare centres with the assistance of ILO/UNFPA project at various Coal, Mica, Iron Ore and Limestone and Dolomite mines run by the management and Coal Mines Labour Welfare Organisation. During the year under report the M.C.H. and child health care has also been integrated with the family welfare programme. All these hospitals are conducting sterilistrtions operations. The Extension educators posted in different mines are attached to a hospital and are conducting eligible couple survey by visiting the residence of workers in order to motivate them for strilisatiln operations and to educate them in adopting the way of family welfare methods. The necessary instruments are also supplied to the hospitals in order to run the programme smoothly. During the year under report 185 vasectomies and 1698 Tubectomies operations were conducted. In addition 1,28,583 conventional contraceptives were distributed.

(g) Rehabilitation :—The Rehabilitation centres attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol continued to function. The Rehabilitation centre at Chhindwara in M.P. Coalfield also continued functioning. The proposal to set up an artificial limb manufacturing centre at Chhindwara in collaboration with Artifical Limb Manufacturing Corporation, Kanpur was processed. The Rehabilitation-cum-Convalescent Home at Sidhabari in West Bengal Coalfield continued functioning during the year.

(h) Other Medical Facilities.—Other important activities of the Organisation conducted on the medical and public health sides were provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy, Mental cases, running of Blood Bank at the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and dentures to the colliery workers, Malaria and Filaria Control Operation etc. etc.

(i) The scheme for grant of relief to the dependents of coal mines who meet with serious/fatal accidents in mines continued operation. Besides providing lumpsum amount and monthly allowances, Scholarships are also provided to the children of such coal miners. Facilities for free medical treatment to the dependents were also provided at the medical institutions of the Organisation.

2. Educational and Recreation Facilities.

(a) Some relevant statistics high-lighting the important activities on this account are given below :—

(i) Multipurpose Institutes	60
(ii) Adult Education Centres.	3
(iii) Women Welfare Centres.	4
(iv) Feeder Adult Education Centre	163
(v) Scholarship to the children of colliery workers.	522
(vi) Scholarship to the children of colliery workers for training in I.T.I.	25
(vii) Boarding Houses for school going children of colliery workers.	1
(viii) Holiday Home	2

(b) Games and sports.—Games and sports are held every year to provide recreation to colliery workers. During the year 1977-78 for organising various games and sports a sum of Rs. 1.80 lakhs was sanctioned by this Organisation.

(c) Other activities.—Other important facilities provided in this connection comprise of : (1) grant-in-aid to the Educational Institutions, (2) exhibition of films, and (3) Grant of Scholarships to the Children of Coal-miners according to the approved scheme.

(d) Provisions for financial assistance to the wives and school going children of colliery workers who died of accident in mines.

(a) Water Supply Scheme :

During the year a sum of Rs. 66.850.00 was spent on water supply schemes. The Organisation continued to pay grant-in-aid as prescribed in the water supply scheme upon 50 per cent on the total cost of scrutinised expenditure to the colliery managements. Out of two intergrated water supply schemes excuted by the State Governments of West Bengal and Bihar partly financed by the Fund, the former one has been put to commission and the latter remained under execution. Two major water supply schemes involving a total out-lay of Rs. 3.70 crores namely : (i) Pench Valley Water Supply Scheme in Chhindwara District, and (ii) Kumar Dubi-Chirkunda Area. Water Supply Scheme in Mugma Coalfields are also under active consideration in consultation with the concerned State Governments.

(b) Sinking of Wells.—Total number of wells so far completed is 333 during the period under report. A sum of Rs. 30,620.00 was paid to M/s. Eastern Coalfields Limited, for sinking of 14 wells at their different collieries in Raniganj coalfield.

4. Co-operative Movement :

No new Primary stores. credit Co-operative Societies and Wholesales or Central Co-operative Stores were opened during the year. The total number of co-operative stores and Credit Societies of Colliery Workers at the end of the period under review stood at 491. These included 10 Wholesale or Central Co-operative Stores already opened which continued functioning for colliery workers.

(No. Z-16016/3/78-M.II)

P. K. SEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1979

का०आ० 1923.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वाति केमिकल कारपोरेशन, प्लाट नं० बी०-18, केमिकल जोन, एम०आई० डी०सी० इण्डस्ट्रियल एरिया, पुराना भेंडापाडा, अम्बरनाथ-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018/30/79-पी०एफ० II(i)]

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 1923.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Swati Chemical Corporation, Plot No. B-18, Chemical Zone, M.I.D.C. Industrial Area, Old Bhendipada, Ambernath-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978.

[No. S. 35018/30/79-PF. II(i)]

का०आ० 1924.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 फरवरी, 1975 से मैसर्स के०एल० एम० कारपोरेशन, एलाइट हाउस, 54-ए, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्वांचल), मुम्बई-93 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/28/79-पी०एफ०II (ii)]

S.O. 1924.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of February, 1975 the establishment known as Messrs. K. L. M. Corporation, Elite House, 54-A, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Bombay-93 for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35018/28/79-PF.II(ii)]

का०आ० 1925.—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डो जापान स्टील्स लिमिटेड, पाटलीपाड़ा, स्वामी विवेकानन्द रोड, ठाणे-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिएं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018/32/79-पी०एफ II(i)]

S.O. 1925.—Whereas, it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Indo-Japan Steels Limited, Patlipada, Swami Vivikanand Road, Thane-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishments ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S.35018/32/79-PF.II(i)]

का० आ० 1926.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1978 से मैसर्स स्वाति केमिकल कारपोरेशन, प्लाट नं० बी-18 केमिकल जोन, एम, आई० डी० सी० इण्डस्ट्रियल एरिया, पुराना भेंडीपाडा, अम्बरनाथ-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018/30/79-पी० एफ० II/(ii)]

S.O. 1926.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necesary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1978 the establishment known as Messrs Swati Chemical Corporation, Plot No. B-18, Chemical Zone, MIDC Industrial Area, Old Bhendipada, Ambernath-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018/30/79-PF.II(ii)]

का० आ० 1927.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 15 जनवरी, 1979 से मैसर्स तेतुलिया कोक प्लाट, जी० टी० रोड, तेतुलिया डाकघर, बड़वा, जिला धनबाद, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है

[सं० एस० 35019/59/79-पी० एफ० II/(ii)]

S.O. 1927.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the fifteenth day of January, 1979 the establishment known as Messrs Tetulia Coke Plant, G.T. Road, Tetulia Post Office, Barwa, District Dhanbad, for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019(59)/79-PF.II(ii)]

का० आ० 1928.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तेतुलिया कोक प्लाट, जी० टी० रोड, तेतुलिया डाकघर, बड़वा जिला धनबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 15 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/59/79- पी० एफ० II (i)]

S.O. 1928.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tetulia Coke Plant, G.T. Road, Tetulia Post Office, Barwa, District Dhanbad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the fifteenth day of January, 1979.

[No. S.35019/59/79-PF.II(i)]

का० आ० 1929.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के० एल० एम० कारपोरेशन, इलाइट हाउस, 54- ए, अंधेरी कुर्ला रोड अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-93, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस- 35018/28/79- पी० एफ० II (i)]

S.O. 1929.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. L. M. Corporation, Elite House, 54-A, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Bombay-93, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1975.

[No. S. 35018/28/79-P. F. II (i)]

का० आ० 1930.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रूप मिलन, 79, महर्षी कार्वे मार्ग, मुम्बई-20, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस- 35018/27/79-पी० एफ० II]

S.O. 1930.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Roop Milan, 97, Maharshi Karve Marg, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S. 35018/27/79-P. F. II]

का० आ० 1931.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निडल एण्ड थ्रेड, 3 डी, ठक्कर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, सीताराम मिल्स कम्पाउंड, एन० एम० जोशी मार्ग, मम्बई-11 जिसके अन्तर्गत 70 मैरिन ड्राईव, मुम्बई-20 स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018/33/79-पी० एफ II]

S.O. 1931.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Needle and Thread, 3D, Thacker Industrial Estate, Sitaram Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Bombay-400011 including its branch at 70 Marine Drive, Bombay-400020, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act. to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1977.

[No. S.-35018/33/79-P. F. II]

का० आ० 1932.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टन्ना ट्रेडिंग कारपोरेशन, दूसरा फ्लोर, 11 ए, नाथलाल डी० पारिख मार्ग मुम्बई 34 जिसके अन्तर्गत (1) 82 काजी सईद स्ट्रीट, दूसरा फ्लोर, मुम्बई- 3 (2) जामनगर और (3) गुजरात स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018/26/79-पी० एफ II (i)]

S.O. 1932.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees' in relation to the establishment known as Messrs Tanna Trading Corporation, 2nd Floor, 11-A, Nathalal D. Parikh Marg, Bombay-39, including its branches at (1) 82, Kazi Sayed Street, Second Floor, Bombay-3 (2) Jamnagar and, (3) Gujarat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment·

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act. to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S. 35018/26/79-P. F. II (i)]

का० आ० 1933.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1976 से मैसर्स इण्डो-जापान स्टील्स लिमिटेड, पाटलीपाडा, स्वामी विवेकानन्द रोड, ठाणे-7, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018/32/79-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1933.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1976 the establishment as Messrs. Indo-Japan Steels Limited, Patlipada, Swami Vivikanand Road, Thane-7, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35018/32/79-P. F. II (ii)]

का० आ० 1934.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विर्दी इंजीनियरिंग वर्क्स, 413/59, जी० टी० रोड, लिल्लुआ, हावड़ा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017/7/79-पी० एफ० (II)]

S.O. 1934.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Virdi Engineering Works, 413/59, G. T. Road, Lilloah, Howrah, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35017/7/79-P. F. II]

का० आ० 1935.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जग्गी ब्रदर्स ओवरसीज (प्राईवेट) लिमिटेड, 1, लिंडसे स्ट्रीट, कलकत्ता-16, जिसके अन्तर्गत (1) के-57, कनौट प्लेस, नई दिल्ली और (2) 12 बस्ती, जलंधर शहर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस- 35017/13/79-पी० एफ० (II)]

S.O. 1935.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaggi Brothers Overseas (Private) Limited, 1, Lindsay Street, Calcutta-16 including its branches at (1) K. 57, Connaught Place, New

Delhi and (2) 12, Basti Jullundur City, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35017/13/79-P. F. II]

का० आ० 1936.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेट्रोपोलिटन फाउंड्री (प्राइवेट) लिमिटेड, 12/1 बीरेन राय रोड (पश्चिम) कलकत्ता-34, जिसके अन्तर्गत 6 बी आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-1 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस- 35017/14/79-पी० एफ० II(i)]

S.O. 1936.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Metropolitan Foundary (Private) Limited, 12/1, Biren Roy Road (West), Calcutta-700034 including its Registered Office at 6 B. R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S-35017/14/79-P. F. II(i)]

का० आ० 1937.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स मेट्रोपोलिटन फाउंड्री (प्राईवेट) लिमिटेड, 12/1, बीरेन राय रोड (पश्चिम) कलकत्ता-34, जिसके अन्तर्गत 6 बी आर एन मुखर्जी रोड कलकत्ता-1 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017/14/79-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1937.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs. Metropolitan Foundary (Private) Limited, 12/1, Biren Roy Road (West),Calcutt-700034 including its Registered Office at 6B R. N. Mukherjee Road, Calcutta-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/14/79-P. F. II (ii)]

का० आ० 1938.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एरकुट्टीपोर टी कम्पनी लिमिटेड, "नारायणी बिल्डिंग" 27 ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017/15/79-पी० एफ० II(i)]

S.O. 1938.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arcuttipore Tea Company Limited, "Narayani Building" 27, Braborne Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35017/15/79-P. F. II (i)]

का० आ० 1939.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1976 से मैसर्स एरकुट्टीपोर टी कम्पनी लिमिटेड, "नारायणी बिल्डिंग" 27 ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017/15/79-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1939.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of December, 1976 the establishment known as Messrs. Arcuttipore Tea Company Limited, "Narayani Building" 27, Braborne Road, Calcutta-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/15/79-P.F. II (ii)]

का० आ० 1940.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डक्कन वाइन कारपोरेशन आफ इण्डिया, एम० जी० रोड, सिकन्दराबाद जिसके अन्तर्गत मोती वाइन स्टोर्स एण्ड बार, एम० जी० रोड, सिकन्दराबाद, स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/451/77-पी० एफ II]

S.O. 1940.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Deccan Wine Corporation of India, M. G. Road, Secundrabad including its branch at Moti Wine Stores and Bar, S. D. Road, Secundrabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/451/77-P. F. II]

का० आ० 1941.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केलट्रोन इण्टरटेनमेंटस सिस्टम्स लिमिटेड, (थाईकॉड) केलट्रोन हाउस, वेल्लयमहलम, त्रिवेन्द्रम-I नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ;

यह अधिसूचना उस मास के, जिसमें अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाए, अन्तिम दिन को प्रवृत्त होगी।

[सं० एस-35019/278/78-पी० एफ० II]

S.O. 1941.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Keltron Entertainments Systems Limited, (Thycaud) Keltron House, Vellayamhalam, Trivandrum-I, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the last day of of the month in which the notification is published in the Official Gazette.

[No. S. 35019/278/78-P. F. II]

का०आ० 1942.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी० मुखर्जी इण्टरप्राइजेज, 16बी शिवनगर, कदमा, जमशेदपुर-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019/55/79-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1942.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. T. Mukherjee Enterprises, 16/B, Shibnagar, Kadma, Jamshedpur-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1979.

[No. S. 35019/55/79-P.F. II(i)]

का०आ० 1943.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वर्धमन, विक्रान्ति सिनेमा कम्पाउंड, जामबाग, हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019/51/79-पी०एफ०II]

S.O. 1943.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vardhman, Vikranti Cinema Compound, Jambagh, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1978.

[No. S. 35019/51/79-P.F. II]

का०आ० 1944.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी सुब्रमण्यम, गान्धी स्ट्रीट, कोठापेटा, श्री कलाहस्ती, चित्तूर जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019/63/79-पी०एफ०II(i)]

S.O. 1944.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. Subramanyam, Gandhi Street, Kothapeta, Srikalahasti, Chittoor District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35019/63/79-P.F. II (i)]

का०आ० 1945.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 अक्तूबर, 1978 से मैसर्स डी० सुब्रमण्यम, गान्धी स्ट्रीट, कोठापेटा, श्रीकलाहस्ती, चित्तूर जिला, नामक उक्त स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019/63/79-पी०एफ०-II(ii)]

S.O. 1945.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1978 the establishment known as Messrs. S. Subramanyam, Gandhi Street, Kothapeta, Srikalahasti, Chittoor District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/63/79-PF.II(ii)]

का०आ० 1946.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शैक अमीर बशा, एम० जी० स्ट्रीट, श्रीकलाहस्ती, चित्तूर जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं। अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019/66/79-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1946.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shaik Ameer Basha, M. G. Street, Srikalahasti, Chittoor District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35019/66/79-P.F. II(i)]

का०आ० 1947.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1978 से मैसर्स शैक अमीर बशा, एम० जी० स्ट्रीट, श्री कलाहस्ती, चित्तूर जिला, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 5019/66/79-पी० एफ०II (ii)]

S.O. 1947.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1978 the establishment known as Messrs. Shaik Ameer Basha M. G. Street, Srikalahasti, Chittoor District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/66/79-P.F. II (ii)]

का०आ० 1948.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विवेक इंजीनियरिंग, 157,न्यू बरादवाड़ी सक्ची, जमशेदपुर, (बिहार), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019/68/79-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1948.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vivek Engineering, 157, New Baradwari Sakchi, Jamshedpur-1 (Bihar), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1979.

[No. S. 35019/68/79-P.F.II(i)]

का०आ० 1949.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात, 1 अप्रैल, 1979 से मैसर्स विवेक इंजीनियरिंग, 157, न्यू बरादवाड़ी सक्ची, जमशेदपुर (बिहार), नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019/68/79-पी०एफ० II(ii)]

New Delhi, the 24th May, 1979

S.O. 1949.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of he Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1979 the establishment known as Messrs. Vivek Engineering, 157, New Baradwari Sakchi, Jamshedpur-1 (Bihar), for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/68/79-PF.II(ii)]

का०आ० 1950.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे०आर० इंजीनियरिंग कम्पनी, 56/टी आर/पाइप लोहित रोड़, [कदमा, जमशेदपुर (बिहार), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019/58/79-पी०एफ०II(ii)]

S.O. 1950.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. J. R. Engineering Com-

pany, 56/TR Type, Lohit Road, Kadma, Jamshedpur (Bihar), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1979.

[No. S.35019/58/79-PF.II(i)]

का०आ० 1951.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 मार्च, 1979 से मैसर्स जे० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी, 56/टी०आर०टाइप, लोहित रोड, कदमा, जमशेदपुर (बिहार) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०35019/58/79-पी०एफ०II (ii)]

S.O. 1951.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1979 the establishment known as Messrs. J. R. Engineering Company, 56/TR Type, Lohit Road, Kadma, Jamshedpur (Bihar), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/58/79-P.F.II(ii)]

का०आ० 1952.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कासमोकान, 231, नार्थ ले आउट सोनारी, जमशेदपुर-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019/57/79-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1952.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Cosmocon, 231, North Lay Out Sonari, Jamshedpur-ii, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1979.

[No.S. 35019/57/79-PF.II(i)]

का०आ० 1953.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1979 से मैसर्स कासमोकान, 231 नार्थ ले आउट सोनारी, जमशेदपुर-2, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019/57/79-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1953.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1979 the establishment known as Messrs. Cosmocon, 231, North Lay Out Sonari, Jamshedpur-ii, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/57/79-PF.II(ii)]

का० आ० 1954.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हबीबुल्लाह एण्ड ब्रादर्स, जी०एस० रोड, जगसलाई, जमशेदपुर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस-35019/56/79-पी० एफ० II(i)]

S.O. 1954.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Habibullah and Brothers, G. S. Road, Jagsalai, Jamshedpur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1979.

[No. S. 35019/56/79-PF.II(i)]

का० आ० 1955.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1979 से मैसर्स हबीबुल्लाह एण्ड ब्रदर्स, जी० एस० रोड, जगसलाई, जमशेदपुर, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019/56/79-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1955.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1979 the establishment known as Messrs. Habibullah and Brothers, G.S. Road, Jagsalai, Jamshedpur, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/56/79-PF.II(ii)]

का० आ० 1956.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1977 से मैसर्स टक्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, दूसरा फ्लोर 2 ए, नाथलाल डी० पारिख मार्ग, मुम्बई 39 जिसके अन्तर्गत (1) 82, काजी सईद स्ट्रीट, दूसरा फ्लोर मुम्बई-3(2) जामनगर और (3) गुजरात स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थान को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35018/26/79-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1956.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of

April, 1977 the establishment known as Messrs Tanna Trading Corporation, 2nd Floor, 11A Nathalal D. Parikh Marg, Bombay-39, including its branches at (1) 82, Kazi Sayed Street, Second Floor, Bombay-3 (2) Jamnagar and (3) Gujarat, for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018/26/79-PF.II(ii)]

का०आ० 1957.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एन० एम० नागराजा राव, बीड़ी मन्युफैक्चरर, जयाराम राव स्ट्रीट, श्रीकालाहस्ती, चित्तूर जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम०-35019/61/79-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1957.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs N. M. Nagaraja Rao, Beedi Manufacturer, Jayaram Rao, Street, Srikalahasti, Chittoor District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S.35019/55/79-PF.II(ii)]

का०आ० 1958.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1979 से मैसर्स टी० मुखर्जी इण्टरप्राइजेज, 16/बी० शिवनगर, कदमा, जमशेदपुर-5, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019/55/79-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1958.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1979 the establishment known as Messrs. T. Mukherjee Enterprises, 16/B Shibnagar, Kadma, Jamshedpur-5, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/55/79-PF. II(ii)]

का० आ० 1959.—दि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 ग की उपधारा (1) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम की संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर उक्त अधिनियम की धारा 11 ग की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का सहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, उक्त स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी स्थापन को छोड़कर उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले किसी अन्य स्थापन में चला जाता है तो नियोजक, उस जाने वाले कर्मचारी के जमाखाते में आनुपातिक प्रीमियम की ऐसे अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा ।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कोयला खान भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक समूह बीमा के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

8. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो उसे कर्मचारी की दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

9. समूह बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह समझा जाएगा कि यह छूट उस तारीख से रद्द कर दी गई है और स्थापन को उक्त स्कीम के अन्तर्गत हुआ माना जाएगा।

11. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी और नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

12. यदि नियोजक, प्रीमियम आदि के संदाय में कोई व्यतिक्रम करता है तो, मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यह छूट न दी जाने की दशा में कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

[सं० आर० 11017/2/79-पी० एफ० I]

S.O. 1959.—Whereas the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (1) of Section 11C of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Coal Mines Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11C of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad, maintain such account and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 11C of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. The employer shall arrange, in respect of an employee who leaves the establishment and joins another establishment covered under the said Act, to transfer to the Insurance Fund in respect of the other establishment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employee.

6. Where an employees, who is already a member of the Coal Mines Provident Fund is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

9. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Coal Mines Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled and the employer proceeded against.

12. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

[No. R-11017/2/79-PF.I]

का०आ० 1960.—मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज इण्डिया लिमिटेड डा० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र मुम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय, आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन उक्त स्थापन के नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद उक्त स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी स्थापन को छोड़कर उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले किसी अन्य स्थापन में भेजा जाता है तो उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, उस जाने वाले कर्मचारी के जमा खाते में आनुपातिक प्रीमियम को ऐसे अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा ।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षा वर्ग करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

8. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर पूर्वोक्त स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

9. समूह बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र, मुम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

10. यदि किसी कारबश उक्त स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे उक्त स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या पूर्वोक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो, यह समझा जाएगा कि यह छूट उस तारीख से रद्द कर दी गई है और स्थापन को उक्त स्कीम के अन्तर्गत हुआ माना जाएगा ।

11. यदि किसी कारणवश, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी और ऐसे नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

12. यदि उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रीमियम के संदाय आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

[सं० एस० 38014/80/78-पी०एफ० II]

S.O. 1960.—Whereas Messrs. Glaxo Laboratories India Limited, Dr. Annie Besant Road, Worli Bombay, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all he provisions of the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, Bombay, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer in relation to the said establishment shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of inspection charges, shall be borne by the employer of the said establishment.

4. The employer in relation to the said establishment shall display, on the Notice Board of the said establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, the amendments thereto alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Th employer in relation to the said establishment shall arrange, in respect of an employee who leaves the said establishment and joins another establishment covered under the said Act, to transfer to the insurance fund in respect of the other establishment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employee.

6 Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund under the said Act or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in the said establishment, the employer shall

immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. The employer in relation to the said establishment shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme aforesaid be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir or nominee of the employee as compensation.

9. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, Bombay, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme aforesaid are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Where, for any reason, the employer in relation to the said establishment fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled and such employer proceeded against.

12. In case of default, if any, made by the employer in relation to the said estblishment in payment of premium etc the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

[No. S. 35014/80/78-PF.II]

नई दिल्ली, 26 मई, 1979

का० आ० 1961 .—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1978 से मैसर्स एम०एन० नागराजा राव, बीड़ी मैन्युफैक्चरर जयाराम राव स्ट्रीट, श्री कलाहस्ती चित्तूर जिला, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एम० 35019/61/79-पी०एफ० II(ii)]

New Delhi, the 26th May, 1979

S.O. 1961.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1978 the establishment known as Messrs. N. M. Nagaraja Rao, Beedi Manufacturer, Jayaram Rao Street, Srikalahasti, Chittoor District for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/61/79-PF. II(ii)]

का०आ० 1962 :—मैसर्स विकर्स स्पेरी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, पोस्ट बैग 7653 अकुर्ली रोड, कांदीवली, मुम्बई, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र मुम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, आने वाले सभी व्ययों का वहन उक्त स्थापन के नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा के स्कीम नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद उक्त स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी स्थापन को छोड़कर उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले किसी अन्य स्थापन में लगा जाता है तो उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक उस आने वाले कर्मचारी के जमा खाते में आनुपातिक प्रीमियम को ऐसे अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा ।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो उक्त अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य, है उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को संदत्त करेगा ।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

8. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर पूर्वोक्त स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के

अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

9. समूह बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र मुम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

10. यदि किसी कारणवश उक्त स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के जिसमें उक्त स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या पूर्वोक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह समझा जाएगा कि यह छूट उस तारीख से रद्द कर दी गई है और स्थापन को उक्त स्कीम के अन्तर्गत हुआ माना जाएगा ।

11. यदि किसी कारणवश उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक उक्त नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगम हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द कर दी जाएगी और ऐसे नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

12. यदि उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रीमियम के संदाय आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो वह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

[सं० एस० 35014/29/79-पी०एफ० II]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

S.O. 1962.—Whereas Messrs. Vickers Sperry of India Limited Post Bag 7653, Akurli Road, Kandivli, Bombay (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, Bombay, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer in relation to the said establishment shall pay such inspection Charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, shall be borne by the employer of the said establishment.

4. The employer in relation to the said establishment shall display, on the Notice Board of the said establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, the amendments thereto alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. The employer in relation to the said establishment shall arrange, in respect of an employee who leaves the establishment and joins another establishment covered under the said Act, to transfer to the insurance fund in respect of the other establisment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employee.

6. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund under the said Act or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in the said establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. The employer in relation to the said establishment shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme aforesaid be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir or nominee of the employee as compensation.

9. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the scheme aforesaid are reduced in any manner, the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Where, for any reason, the employer in relation to the said establishment fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to the cancelled and each employer proceeded against.

12. In case of default, if any, made by the employer in relation to the said establishment in payment of premium, etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

[No. S. 35014/29/79-PF.II]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 25th May, 1979

S.O. 1963.—*In pursuance of section* 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State

Bank of Bikaner and Jaipur and their workman over termination of services of Shri Ram Patan Ram, Ex-Waterman, which, was received by the Central Government on 15-5-79.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 191 of 1977

In re :

Shri Ram Patan Ram,
262/1, Jain Mandir Gali,
Mohalla Ram Nagar,
Ghandhinagar,
Delhi-31 ... Petitioner

VERSUS

The Personnel Manager,
Head Office,
State Bank of Bikaner and Jaipur,
S. M. S. Highway,
Jaipur.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its Order No. L-12012/64/77-D.II.A dated the 1st September, 1977 made a reference to this Tribunal u/s 10 of the I.D Act, 1947 :

'Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in terminating the services of Shri Ram Patann Ram, Ex-waterman at their Connaught Circus, New Delhi Branch w.e.f. 22-1-1974 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?'

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. Thereafter a written statement was also filed. Finally a replication was filed. On the pleadings of the parties issues were framed and the only issue framed was as referred in the order of reference and the case was adjourned for evidence of the parties. In the meanwhile talks for compromise started between the parties and finally a compromise was arrived at between the parties. It was ordered to be recorded in so far as it was beneficial for the workman. The statement of Shri T. C. Gupta and Shri P. Surya Narain, the representative of the Union and the Management respectively was recorded in which it is stated by them that. The parties have arrived at a settlement vide Ex. S/1. A no dispute award be made subject to the directions that the settlement S/1 is binding upon the parties'

3. In view of the statement recorded above, a no dispute award is hereby made in the reference and parties are left to bear their own costs.

Dated :—the 16th April, 1979.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.
[No. L-12012/64/77-D.II.A]

S.O. 1964.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur and their workman over termination of the services of Shri O. P. Sharma, Clerk-cum-Typist of Kota Branch, which was received by the Central Government on 15-5-1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 43 of 1977

In re.:

Shri O. P. Sharma,
The Secretary,
Rajasthan Bank Employees Union,
Rampura Bazar,
Kota-6. ... Petitioner

VERSUS

The Managing Director,
State Bank of Bikaner and Jaipur,
S. H. S. Highway,
Jaipur.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its Order No. L-12012/195/76-D.II.A dated the 30th March, 1977 made a reference to this Tribunal u/s 10 of the I.D. Act, 1947 :

'Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur in terminating the services of Shri O. P. Sharma, Clerk-cum-Typist of Kota Branch of the Bank w.e.f. 4-8-72 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?'

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. Thereafter a written statement was also filed. In the meanwhile talks for compromise started between the parties and finally a compromise was arrived at between the parties. It was ordered to be recorded in so far as it was beneficial for the workman. The statement of Shri R. L. Khandelwal and Miss Mithilesh Singhal, the representative of the Union and the Management respectively was recorded in which it is stated by them that. The parties have compromised vide Ex. S/1. Application A/1 is correct. A 'no dispute' award be made.

3. In view of the statement recorded above, a no dispute award is hereby made in the reference and parties are left to bear their own costs.

Dated : the 30th April, 1979.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.
[No. L-12012/195/76-D.II.A]

S.O. 1965.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Grindlays Bank Ltd. and their workman over termination of services of Shri Udey Singh, Waterman, which was received by the Central Government on 15-5-1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 108 of 1978

In re :

Shri Udey Singh,
C/o Shri S. P. Khanna, General Secretary,
National and Grindlays Bank Employees,
Union, C/o Grindlays Bank Ltd.,
Amritsar. ... Petitioner

VERSUS

The General Manager (Northern Region),
Grindlays Bank Ltd.,
Connaught Circus,
New Delhi.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its Order No. L-12012/101/78-D.II.A, dated the 27/29th November, 1978 made a reference to this Tribunal u/s 10 of the I.D. Act, 1947 :

'Whether the action of the management of Grindlays Bank Ltd. in terminating the services of Shri Udey Singh, Waterman in the subordinate service of the Amritsar Branch of the Bank w.e.f. 7.2.78 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?'

2 On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. In the meanwhile talks for compromise started between the parties and finally a compromise arrived at between the parties. It was ordered to be recorded in so far as it was beneficial for the workman. The statements of Shri Rajinder Syal and Shri K L. Sethi, the representative of the Union and the Management respectively were recorded in which it is stated by them that 'parties have arrived at a compromise vide Ex. S/1. A no dispute award be made'.

3 In view of the statement recorded above, a no dispute award is hereby made in the reference and parties are left to bear their own costs.

Dated : the 30th March, 1979.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer
[No. L-12012/101/78-D.II.A]

S.O. 1966.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen over debarring Shri O. N. Mehrotra and Shri R. K. Srivastava, Clerks in Lucknow Branch from officiating as Accountant for a period of one year, which was received by the Central Government on 15-5-1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 42 of 1978

In Re :

Shri O. N Mehrotra etc.
The Secretary,
U. P. Bank Employees Union.
Red Gate,
Hotel Gopalganj,
Lucknow, (U.P.). ....Petitioner

VERSUS

The Regional Manager,
Punjab National Bank,
Hazratganj,
Lucknow, (U.P.).

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its Order No. L-12012/102/77-D.II.A. dated 5th April, 1978, made a reference to this Tribunal u/s 10 of the I.D. Act 1947

'Whether the action of the management of Punjab National Bank Gautam Budh Marg, Lucknow in debarring Shri O. N. Mehrotra and Shri R. K. Srivastva Clerks in their Lucknow Branch from officiating as Accountant for a period of one year in justified ? If not to what relief are these workmen entitled ?'

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. Thereafter a written statement was also filed. In the meanwhile talks for compromise started between the parties and finally a compromise was arrived at between the parties. It was ordered to be recorded in so far as it was beneficial for the workman. The statement of Shri G. B. Singh, the representative of the Management respectively was recorded in which it is stated by them 'The matter has been compromised. The workman has been promoted in consequence. I tender letter A/1 in this behalf. A no dispute award be made'.

3. In view of the statement recorded above, a no dispute award is hereby made in the reference and parties are left to bear their own costs.

Dated : the 30th April, 1979.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer
[No. 12012/102/77-D.II.A.]

S.O. 1967.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workman over termination of services of Shri Nar Singh Purohit, which was received by the Central Government on 15-5-1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 47 of 1978.

In re :

Shri Nar Singh Purohit,
The General Secretary,
Rajasthan Bank Employees Union.
Binani Building,
Bikaner (Rajasthan).

VERSUS

The General Manager,
State Bank of Bikaner & Jaipur
S.M.S. Highway
Jaipur (Rajasthan).

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its Order No. L-12012/86/77-D II. (A) dated the 10/11th May, 1978, made a reference to this Tribunal u/s 10 of the I.D. Act 1947 :

'Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in terminating the services of Shri Nar Singh Purohit employed in their Industrial Estate Branch Jodhpur w.e.f. 1-1-69 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?'

2 On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. Thereafter a written statement was also filed.

Finally a replication was filed. On the pleadings of the parties issues were framed and the two issues were framed as under :—

1. Whether the dispute has been raised after unnecessary lapse of time ? Its effect ?.

2. As in the order of reference.

Thereafter the case was adjourned for evidence of the parties. In the meanwhile talks for compromise started between the parties and finally a compromise was arrived at between the parties. It was ordered to be recorded in so far as it was beneficial for the workman. The statement of Shri R. L. Khandelwal and Miss Mithilesh Singhal, the representative of the Union and the Management respectively was recorded in which it is stated by them that 'I tender settlement vide Ex. S/1 and application A/1. The matter in dispute has been settled between the parties. A no dispute award be made in this reference.

3. In view of the statement recorded above, a no dispute award is hereby made in the reference and parties are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 30th April, 1979.

[No. L-12012/86/77-D (I.A]

New Delhi, the 29th May, 1979

S.O. 1968.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following consolidate award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Pujab National Bank, Ahmedabad and their workmen over reinstatement and confirmation of Shri B C. Shah, Godown Keeper, Dabhoi and termination of services of Shri R. P. Parikh, Kapadwanj, which was received by the Central Government on the 22-5-1979.

BEFORE SHRI R. C. ISRANI, B.A. (Hons.), LL:B:, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 6 of 1975

ADJUDICATION

BETWEEN

Management of the Punjab National Bank, Regional Office, Ahmedabad.

...First Party

AND

Their Workmen.

..Second Party

In the matter of reinstatement and confirmation of Shri B. C. Shah, Temporary Godown Keeper, Dabhoi.

WITH

Reference (ITC) No. 6 of 1975

ADJUDICATION

BETWEEN

Management of the Punjab National Bank, Regional Office, Ahmedabad.

...First Party

AND

Their Workmen.

...Second Party

In the matter of termination of services of Shri R. P. Parikh, Temporary Godown Keeper, Kapadwanj.

APPEARANCES :

Dr. Anand Prakash, assisted by Shri Jagat Arora, Advocate for the First Party Employer bank ; and

Shri M. S. Udesi Advocate assisted by Shri K. N. Mehrotra and Shri C. L. Bhardwaj of All India Punjab National Bank Employees' Association for the Second Party-workmen.

CONSOLIDATED AWARD

These are the two references made by the Government of India in the Ministry of Labour, New Delhi, u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter to be referred to as the 'Act' in respect of certain industrial disputes which have arisen between the management of the Punjab National Bank, hereinafter to be referred to as the 'Bank' and the workmen employed under it through the union known as All India Punjab National Bank Employees' Association, hereinafter to be referred to as the 'Union'. In the first instance, the two references were made by the Government of India to the Industrial Tribunal, Delhi, but thereafter they were withdrawn from that Tribunal and were referred to Shri M. U. Shah, the then Presiding Officer, Industrial Tribunal for Central Government with headquarters at Ahmedabad. After his retirement, the two references were transferred to this Tribunal vide the orders dated 27-8-1977 after this Tribunal was also constituted as Industrial Tribunal for Central Government. Since common questions of law and to a certain extent even of facts are involved in these two references, the parties gave the joint purshis, ex. 25 dated 21-6-1978 in the Reference (ITC) No. 4 of 1975 which will hereinafter be referred to as the 'First Reference', with a request that the two references be consolidated. After hearing the learned representatives of the parties, the order was made below the application ex. 25 for the consolidation of the two references. The First Reference shall be treated as the main reference and the second reference, viz., Reference (ITC) No. 6 of 1975 is consolidated with it. That reference will hereinafter be referred to as the 'Second Reference'.

2. The industrial dispute covered by the first reference, as it appears from the schedule attached to the original order of reference is to the following effect :—

"Whether the All India Punjab National Bank Employees Association, Delhi is justified in demanding reinstatement and confirmation of Shri B. C. Shah, temporary Godown Keeper of Punjab National Bank, Dabhoi Branch of the said Bank ? If so, from what date and to what relief is the said workman entitled ?"

Similarly the idustrial dispute covered by the Second Reference, as it appears from the original order dated 20-5-1975 under which this reference has been made relates to the demand which is as under :—

"Whether the management of the Punjab National Bank, Bombay is justified in terminating the services of Shri R. P. Parikh, temporary Godown Keeper at Kapadwanj with effect from the 14th August, 1973 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

3. In support of the demand covered by the First Reference relating to the case of Shri B. C. Shah, who will hereinafter be referred to as "Shri Shah", the Union representing the said workman has filed its statement of claim, Ex. 2/2 dated 30-9-1975. It is the case of the Union that Shri Shah was originally appointed as a temporary godown keeper vide the order, ex. 8/1 dated 24-10-1967 by the Bank. The terms and conditions on which he was appointed as such temporary godown keeper are also contained in the said order of appointment ex. 8/1. It is important to note that Shri Shah was appointed in that post for a specific purpose which is indicated in para 1 of that order of appointment, ex. 8/1 dated 24-10-67. It will be important to reproduce that para 1 which is as under :—

"That your appointment is on a purely temporary basis for the account of Messrs Miyabhai Jamalbhai and

Co. Nasavadi and that your appointment, however in the first instance will be for a period of one month only which may be extended by us in writing from time to time. Your services would be liable to be terminated at any time during the prescribed period of temporary 'appointment by giving you 14 days notice and would come to an automatic end on the adjustment of the above account or when the party refuses to pay the Bank the salary of the godown keeper If after, joining you leave Bank's service without giving 14 days notice, you will be liable to pay the bank a week's pay including allowance in lieu of notice."

4. The grievance of the Union is that even though the Bank did require the services of Shri Shah continuously as a godown keeper, yet, in order to see that he did not put any continuous service, the Bank effected artificial and uncalled for breaks in his service. The details are given in its statement of claim as to how appointments were given to Shri Shah and again how terminations were effected in his service only with a view to showing that he was not in continuous service of the Bank He entered into the service of the Bank for the first time on 24-10-1967 and ultimately his services were finally terminated with effect from 15-7-1974. It is thus clear that during a span of such a long period as about 7 years, his services were terminated on as many as 9 occasions and thereby he was deprived of the benefit of being confirmed in the service of the Bank. The contention of the Union is that in accordance with the Shashtri Award, the Desai Award and the Bi-Partite Agreements between the management of the Bank and the workman, Shri Shah was entitled to be confirmed after he had put in a continuous service of one year, but the Bank effected artificial breaks in his otherwise continuous service, and he was unjustifiably denied the said benefit of confirmation. It is also urged by the Union that even after the breaks were artificially effected in the otherwise cotinuous service of Shri Shah, his continuous service being more than one year, would amount to continuous service as contemplated under the provisions of S. 25-B of the Act and, therefore, the various terminations of his service would amount to his retrenchment from service as contemplated u/s 2 (oo) of the Act. It is, therefore, contended that if his termination amounted to retrenchment, the Bank was bound to follow the conditions precedent to retrenchment of workmen as laid down u/s 25-F of the Act and since these conditions were not complied with in any case of the termination of services of Shri Shah, these terminations were absolutely illegal and uniust. In view of this position, since the authorities of the Bank did not pay any heed to the request made by the Union, this industrial dispute was raised with the Government of India, Ministry of Labour and ultimately the same has been referred for adjudication to this Tribunal in the manner as stated above. It may be stated at this stage that so far the academic qualifications are concerned, Shri Shah is a IInd Class Graduate with Economics. The Union, therefore, has asked for the following reliefs :—

(1) It may be declared that the termination of services of Shri Shah was illegal and unjust.

(2) A direction be given to the bank authorities to reinstate Shri Shah in his original position.

(3) That considering the long and satisfactory service of Shri Shah, a direction be also given to the Bank that he should be confirmed if he completed satisfactory service for one year under the Bank.

(4) A direction be given to the Bank to pay full back wages to Shri Shah with all the benefits which he would have received if he had continued in the services of the Bank.

5. On behalf of the Bank, written statement ex. 3 has been filed on 28-7-1976. Many facts as disclosed from the statement of claim have been admitted. It is also admitted that Shri Shah was engaged by the Bank as a temporary godown keeper for specific period for the godown of the borrower of the Bank, viz., M/s. Mivabhai Jamalbhai Nasval. The main contention of the Bank appears to be that because he was appointed for a specific period, his services came to an end automatically on the expiry of that specific period for which he was appointed. The Bank has also admitted the different dates on which appoitment orders were given to Shri Shah and also the dates on which his services were terminated by the Bank. It is also admitted that he served as a godown keeper at different stations as indicated in the statement of claim. The Bank denied the claim of Shri Shah for any retrenchment compensation as according to the Bank, the different terminations of service at different times of Shri Shah did not amount to his retrenchment from service. The case of the Bank in this connection appears to be that Shri Shah's service had come to an end by efflux of time and, therefore, his case would not be, covered by the term 'retrenchment' as contemplated under the Act.

6. The Bank has also referred to a settlement which had been arrived at between the authorities of the Bank and the then union which represented the employees of the Bank. That settlement is produced at ex. 55 and it is dated 13-7-72. It is explained by the Bank that in view of that settlement, the employees of the Bank had to appear for qualifying test and the employees, including Shri Shah, had agreed voluntarily to appear at such test. Actually Shri Shah had appeared at such test on 25-11-1974 but unfortunately he failed to qualify at that test. The case of the Bank, therefore, is that on that account also the services of Shri Shah could not be continued as he had failed to qualify for such service at that qualifying test. The said settlement was arrived at between the Bank and the All India Punjab National Bank Employees Federation.

7. As regards confirmation or permanency of Shri Shah, it was explained through the written statement that since Shri Shah had failed to qualify at that qualifying test, the question of his permanency did not arise. On page 16 of that written statement, the Bank took the following stand :

"Shri Shah, as already stated was subjected to bank's recruitment rules and had he been a successful candidate he would also have been in the permanent role of the bank by now. Since he disqualified he was not only considered for permanent employment in the bank but he was also not considered for further temporary appointment in the bank since the institution of temporary appointment clerical hands and of temporary godown keepers was abolished in accordance with the terms of Memorandum of Settlement between the bank and the Employees' Federation referred to above."

The Bank admitted that its employees were covered by the Shashtri Award, the LAT Award, The Desai Award, the 1st Bi-Partite Settlement and the 2nd Bi-Partite agreement. However, the Bank also relied upon the last settlement dated 13-7-1972 on the basis of which the temporary posts were abolished and all the employees of the Bank were subjected to the recruitment rules of the Bank. On page 19 of the written statement, the Bank once again reiterated :

"Since in accordance with the recruitment rules Shri Shah could not qualify in the qualifying test he could not be given any preference for absorption in the permanent service of the bank."

It was contended on behalf of Shri Shah through the statement of claim that after the final termination of his services with effect from 15-7-1974, he had been without any employment. The Bank gave its reply in para 13 of its written statement which is as under :

"(13) It is submitted that the bank is not at fault if Shri Shah is unable to secure any employment elsewhere."

It is thus clear that the Bank does not contend that after the termination of his services, Shri Shah has been able to secure any other employment under any other employer. Not only that, but the Bank contended that the termination of services of Shri Shah was a case of discharge simpliciter as explained in the earlier paras of the written statement.

8. So far the other reference is concerned, it relates to one Shri R. P. Parikh who was also a temporary godown keeper of the Bank at Kapadvanj. In support of the demand covered by that reference, the Union has filed its statement of claim, ex. 2/3 dated 20-2-1975. In his case also, the contention of the Union is the same that he was first appointed vide the order ex. 12[1 dated 10-7-1967. The termination of his service for the last time was on 14-8-1973. It is thus clear that even he had served during a span of about six years. During this span of six years there had been 11 terminations of his service at different intervals. The Union has contended that all these terminations were also effected mala fide and these breaks were artificial. It is the case of the Union that these breaks were effected deliberately in order to see that the said workman who will hereinafter be referred to as 'Shri Parikh', did not put in a continuous service and on that strength did not claim confirmation or permanency. In this case also it is contended by the Union that all these terminations amounted to retrenchment and the conditions which required to be satisfied were also not satisfied even in the case of Shri Parikh. As such, all these terminations were illegal and unjust. Shri Parikh is admittedly a B.Sc. 1st Class from Gujarat University and his services according to the Union, as a godown keeper were also satisfactory against whom there was no complaint whatsoever. Through the statement of claim it was prayed that Shri Parikh be directed to be reinstated in the services of the Bank with effect from 14-8-1973 from which date his services were illegally and wrongly terminated; that he should be given his full back wages for the period during which he has remained out of employment and a direction should also be given to the Bank to confirm him in the services of the Bank after his successful completion of one year of service.

9. On behalf of the Bank, written statement ex. 33 has been filed on 24-6-1976. In this case also the Bank has admitted so many facts. But again, the ame pleas heve been taken as were taken through the written statement filed in the case of Shri Shah. According to the Bank, even Shri Parikh was appointed as a temporary godown keeper for a specific period and therefore on the expiry of that period his services automatically came to an end. It is vehimentaly denied that the termination of services of Shri Parikh at different intervals would amount to retrenchment and would attract the compliance of those conditions which are required to be satisfied before effecting retrenchment. On the question of permanency also, the same plea was taken that since he was absolutely a temporary hand employed for a specific period, his services terminated on the expiy of that period and therefore the question of making him permanent did not arise. Through this written statement also, the same plea regarding the settlement ex. 55 dated 13-7-1972 was repeated. It was urged that Shri Parikh like many other employees of the Bank had exercised option on the basis of that settlement to appear at the qualifying test and that he had actually appeared for that test on 24-11-1973 at Ahmedabad. It is explained that unfortunately he could not succeed in that test and therefore also it was not possible to continue him in the services of the Bank. In view of this position, it was vehimently urged that even this demand be rejected and the reference should be disallowed.

10. Before these references could be heard on their merits, on behalf of the Bank an application was given for amending the original written statement. That application was allowed after hearing the parties by passing a detailed order and in the First Reference the amended written statement is at ex 29 dated 11-7-1978. Similarly in the Second Reference, the amended written statement is at ex. 30 dated 11-7-1978. Through this amended written statement certain legal contentions have been taken regarding the maintainability of these two references. The main legal contentions which have been raised through this amended written statement as well as through the application ex. 29 dated 11-7-1978 are, that in these two cases the disputes were raised by the Union and not by these two individual workmen, viz., Shri Shah and Shri Parikh. The second contention is that if the original notices of demand in the two cases are scrutinized, it will appear that no plea had been taken regarding the application of S. 25 of the Act relating to 'continuous service' and the conditions precedent to retrenchment. It is also contended that in fact strictly speaking, no plea was originally taken even in respect of reinstatement of these two workmen in their original positions.

11. In these two references, on behalf of the Union representing these two workmen, three witnesses have been examined—one is Shri B. C. Shah himself whose evidence is at ex. 13, the other is Shri C. L. Bhardwaj, a representative of the Union whose evidence is at ex. 34 and the third witness is Shri T. R. Mishra whose evidence is at ex. 46. Thereafter the Union passed the purshis ex. 48 on 21-9-1978 closing its case. So far the Bank is concerned, two witnesses have been examined on behalf of the Bank—one is Shri A. S. Pande whose evidence is at ex. 49 and the other is Shri A. R. Raychoudhury whose evidence is at ex. 54. Thereafter the Bank closed its case vide the purshis ex. 59 dated 7-11-1978. The Union in the two references was represented by the learned advocate Shri M. S. Udesi who was assisted by Shri K. N. Mehrotra, Shri C. L. Bhardwaj and Shri K. R. Mehta. So far the Bank is concerned it was represented by the learned Counsel Dr. Anand Prakash, Senior Advocate, who was assisted by the learned advocate Shri Jagat Arora.

12. It is clear from the two orders of references in these two cases the industrial disputes were raised in both the cases by the Union named All India Punjab National Bank Employees' Association, Delhi. If that is so, the two concerned workmen being the members of that Union were duly represented by the Union for the purpose of raising these industrial disputes and, therefore, it cannot be said that the references are bad because they were not raised by the respective individual workmen. It is by now well settled that a duly registered and recognised trade union would be the negotiating agent for the workmen who are the members of that Union. In the instant case, it is no where the case of the Bank that these two concerned workmen, viz., Shri Shah and Shri Parikh were not the members of this Union or that for the purpose of raising such industrial disputes, there was any other agency recognised by these two workmen. As such, the first preliminary contention raised through the application ex. 29 or through the amended written statements ex. 29 and ex. 30 has absolutely no force and deserves to be rejected.

13. As regards the giving of notice of demand in respect of any industrial dispute, by now it is well settled that such a notice need not be in writing. A notice of that type can also be given orally by making a demand from the employer. In this case there were also conciliation proceedings before the conciliation officer appointed by the Central Government and a reference to those proceedings as well as to the plea taken by the parties before that authority would satisfy that the dispute raised by the Union did involve the question of reinstatement of these two workmen in their original positions which also indirectly involved the question regarding the legality or validity of the termination of their services at different intervals. In this connection, a reference is invited to letter ex. 35 dated 3-10-1974 addressed by the Union to the Assistant Labour Commissioner (C), Government of India, Ministry of Labour and Employment at Ahmedabad. From this letter it will become clear that the Union had contended that the termination of services of Shri Shah was illegal and a request was made that not only he should be reinstated but that he should also be confirmed and made permanent in accordance with the provisions of para 499 of the Shashtri Award. The authority to which this letter was addressed has issued notice to the Bank and to that notice the Bank had replied through the letter, ex. 36 dated 31-1-1975. To this letter of the Bank, the Union had given counter reply ex. 37 which is also on the record. The Assistant Commissioner of Labour had submitted his failure report ex. 38 dated 24-2-1975 to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour. In the opening para of that letter even the Assistant Commissioner had informed the Government of India that the demand had been made for the reinstatement of Shri B. C. Shah, a temporary godown keeper with effect from 9-5-1968. From this document it becomes amply clear that the terminations were challenged and a prayer was also made from the very beginning that the two workmen be reinstated in their original positions. So far Shri Shah is concerned, a further contention was taken that he should also be confirmed in the service of the Bank in accordance with the provisions of the Shashtri Award, on completion of the required satisfactory service for a period of one year.

14. Again, even though no specific plea had been taken by the Union that all these terminations of services of these two workmen amounted to their retrenchment from service, then too, the said legal plea would always be open to the Union as well as to the two concerned workmen because the legality and validity of these terminations is the very subject matter of these two references. This Tribunal while examining the legality and validity to these terminations of services of these two workmen, will be within its jurisdiction to find out as to whether these terminations amounted to retrenchment and if yes, whether the conditions precedent to be followed before effecting such retrenchment were or were not followed or complied with by the management of the Bank? This being the legal position, the preliminary legal contentions raised on behalf of the Bank will have absolutely no force.

15. Now I will take up the case of each individual workman and in the first place I will examine the case of Shri Shah. Shri Shah was admittedly appointed as temporary godown keeper for the first time with effect from 24-10-1967 vide the order ex. 8/1 of the same date i.e. 24-10-1967. It will be necessary to refer to various orders which were issued by the Bank either for the termination of his services or for the re-appointment of Shri Shah. These orders are at exbs. 11/3 to 11/10. It will be convenient to give in a tabular form the dates of his appointment as well as the termination of his services :

Date of appointment :	Date of termination :
24-10-1967	9-5-1968
16-12-1968	9-10-1969
6-1-1970	30-6-1970
16-1-1971	16-7-1971
7-2-1972	6-4-1972
7-4-1972	19-9-1972
1-12-72	31-12-1972
1-1-1973	6-7 1973
30-11-1973	15-6-1974
21-6-1974	15-7-1974

16. It is pertinent to note that in the case of Shri Shah, the order of reference does not confine itself to any particular date of termination of service of Shri Shah. It is in very general terms to find out whether the Union is justified in demanding reinstatement and confirmation of Shri Shah, the temporary godown keeper in the Bank. Then it refers to the relief to which the concerned workman would be entitled to. From the above mentioned dates of appointment and termination, it will be clear that the services of Shri Shah during the period from 24-10-1967 the date of his first appointment to 15-7-1974, the date of which his services were last terminated, he had already acquired the status of having put in a continuous service of more than one year. In order to appreciate this point, it will be necessary to refer to certain important provisions of the Act, S. 25B of the Act defines 'continuous service'. Sub-section (1) of that section refers to actual continuous service while sub-section (2) refers to 'deemed continuous service'. In the instant case, we would be concerned with sub-section (2) of S. 25-B of the Act. The said sub-section (2) is to the following effect :—

> "(2) Where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer—
>
> (a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—
>
> (i) ninety-five days, in the case of a workman employed workman employed below ground in a mine ; and
>
> (ii) two hundred and forty days, in any other case ;
>
> (b) for a period of six months, if the workman, during a period of six calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—
>
> (i) ninety-five days, in the case of a workman employed below ground in a mine ; and
>
> (ii) one hundred and twenty days, in any other case.
>
> Explanation.—For the purposes of clause (2), the number of days on which a workman has actually worked under an employer shall include the days on which—
>
> (i) he has been laid off under an agreement or as permitted by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, or under this Act or under any other law applicable to the industrial establishment;
>
> (ii) he has been on leave with full wages, earned in the previous years;
>
> (iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment; and
>
> (iv) in the case of a female, she has been on maternity leave; so however, that the total period of such maternity leave does not exceed twelve weeks."

17. Applying the provisions of sub-section (2) of S. 25B of the Act to the case of Shri Shah, it will appear that at least on two occasions during the entire period of his service he had put in a continuous service of one year and more. The above mentioned figures would show that on 30-6-70 his services were terminated. Now, 12 months immediately preceding that date would begin from 30-6-69. If we count the no. of days on which he had worked during the period from 30-6-69 to 30-6-70, it will appear that he had worked for 276 days which is definitely more than 240 days as contemplated u/s. 25B(2) of the Act. Again, his services were terminated on 6-7-73 and a period of 12 months immediately preceding from that date would fall on 6-7-72. Now, if we count the days on which he actually worked during the period from 6-7-72 to 6-7-73, it will appear that he had worked for 294 days which is definitely more than 240 days. It is thus clear that on 30-6-70, in the first instance and again on 6-7-73, the workman Shri Shah had put in a continuous service of more than one year. At this stage, let me dispose of an objection which was very feebly taken on behalf of the Bank by the learned advocate Shri Jagat Arora. It is urged by him that in counting 240 days, the holidays on which the workman had actually not worked should be excluded. It is contended by him that in the instant case, if Sundays and other holidays are excluded then this workman Shri Shah could not have actually worked for more than 240 days. In my opinion, this objection has absolutely no force because from the provisions of S. 25B(2) including the explanation attached to it, it becomes very clear that all those days for which the workman is paid his wages will have to be counted as the days on which he is deemed to have actually worked within the meaning of sub-section (2) of S. 25B of the Act. A direct querry was put to Shri Jagat Arora to show from the record of this reference whether for Sundays and other holidays, the workman Shri Shah was not paid any wages. Admittedly Shri Shah was not a daily rated workman but he was a monthly rated employee of the Bank. He was being paid his salary month-wise and not day-wise. If that is so, even if any Sunday intervenes, then too, he shall be deemed to have actually worked on those days for which he was also paid his wages. It is thus clear that Shri Shah had put in a continuous service for more than one year on two different occasions. Therefore, when his services were finally terminated on 15-7-74, he was a workman who had put in continuous service of more than one year. At this stage, it will be necessary to refer to the definition of 'retrenchment' as given in S. 2(oo) of the Act which is as under :—

> "retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include—
>
> (a) voluntary retirement of the workman; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill health."

18. From this definition it becomes clear that the termination of services by the employer of a workman for any reason whatsoever otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action would amount to retrenchment excepting in three exceptions which are given in clauses (a), (b) and (c) of that sub-section 2(oo) of the Act. In the instant case therefore the termniation of services of Shri Shah on 15-7-74 for whatever reason would amount to retrenchment. If that is so, then, it will have to be seen as to how such a retrenchment could be legally effected? S. 25F of the Act lays down the conditions precedent to retrenchment of workmen. It will be necessary to reproduce the same and it is as under :—

"25F. No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice :

Provided that no such notice shall be neecssary, if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service,

(b) the workman has been paid at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the official gazette."

19. It is an admitted position that none of these three conditions were complied with by the management of the Bank before terminating the services of Shri Shah on 15-7-74. There is no dispute regarding the legal position that if there is case of retrenchment and if the conditions at no. (a) and (b) are not complied with before effecting such retrenchment, the retrenchment would be illegal and the result would be that the workman retrenched would continue to be in the service of the employer and he would also be entitled to his back wages for the period he was illegally retrenched from the service. That in the present case, the action of the management in terminating the services of Shri Shah with effect from 15-7-74, did amount to retrenchment, reliance is placed upon the latest decision of the Supreme Court of India in the case of State Bank of India vs. N. Sundaramoney 1974(29) F.J.R. 186 (1976-I L.L.J. p. 478). In that case the Supreme Court has interpreted the definition of 'retrenchment' as given in S. 2(oo) of the Act and it has also considered the provisions of S. 25F of the Act. According to the decision, even if the termination of service is by afflux of time on account of the employment being for any specific period, then too, if the concerned workman was in continuous service of not less than one year, the conditions precedent as laid down in S. 25F of the Act shall have to be complied with before effecting the retrenchment.

20. Dr. Anand Prakash, the learned counsel appearing on behalf of the Bank has drawn my attention to two decisions of the Delhi High Court given by its Division Bench—one in the case of Shri Lachman Das vs. Indian Express reported in 1977(34) F.L.R. p. 130 and the other in the case of Shri Ram Institute reported in 1978(37) F.L.R. p. 1. He has also invited my attention to the Full Bench decision of the Kerala High Court reported in 1979-I L.L.J. p. 211 in the case of L. Robert D'Souza vs. X.N., Southern Railway as well as the Division-Bench decision of the Calcutta High Court reported in 1978 LAB. I. C. 1581 in the case of Dabur (Dr. S. K. Burman) Pvt. Ltd. vs. State of West Bengal. It is urged by Dr. Anand Prasad that in these decisions the decision of the Supreme Court of India in Sundaramoney's case has been interpreted and these three High Courts, viz., Delhi, Kerala and Calcutta have interpreted the said decision as meaning that the Supreme Court has not changed its previous view that in all cases retrenchment presupposes surplusness of the employee retrenched. It is therefore urged by Dr. Anand Prakash that before it can be held in this case that these two workmen, viz., Sarvashri Shah and Parikh were retrenched from the service of the Bank, the finding will have to be given that they had become surplus and, therefore, their services were to be terminated. Apart from giving the finding, whether the subsequent decisions of Delhi, Kerala and Calcutta High Courts have actually and properly interpreted the decision of the Supreme Court in Sundaramoney's case, it can be safely held, on the facts of the present case, that in the case of these two workmen it can also be said without any fear of contridiction that their services were terminated because they had become surplus hands. It is an admitted position that Shri Shah was appointed to look after the godown in which the goods of M/s. Miyabhai Jamalbhai Nasvale were kept as they had been pledged with the Bank on account of they having taken loan from the Bank on the basis of those goods. If that is so, it is the case of the Bank itself that when the said loan was discharged by the loanee and, therefore, on their behalf, there was no necessity to keep any of his goods in that godown, the services of Shri Shah were no more required. This fact would indicate that Shri Shah had become a surplus hand with the Bank and, therefore, his services had to be terminated. If that is so, the termination of his service would undoubtedly amount to retrenchment even according to the previous view taken by the Supreme Court of India as urged before this Trbiunal by Dr. Anand Prakash the learned counsel appearing on behalf of the Bank. The similar is the case of Shri Parikh which will be discussed in details while dealing with this case. This would therefore show that seen from any angle, the only conclusion to which one can reasonably arrive at, would be that in this particular case the termination of service of Shri Shah with effect from 15-7-74 amounted to his retrenchment from service, he having put in a continuous service for not less than one year. As such, before his services were terminated, the conditions precedent as contained in S. 25F of the Act, should have been followed, as that termination amounted to retrenchment. The said conditions not having been followed, the order of his retrenchment would be illegal and bad in law.

21. The Bank has also given no valid reasons for not continuing Shri Shah in the service. Of course, the first reason is that because he was appointed for a specific purpose and also for a specific period, the said purpose having come to an end and the said period having already expired, it was no more necessary to keep him in services of the Bank. I have already replied to these two pleas. The next plea is that the Union and the management of the Bank had arrived at a settlement, a copy of which is produced at ex. 55 dated 13-7-72. According to that settlement, it was agreed by the Union that the employees of the Bank would abide by the recruitment rules of the Bank which envisaged the appearance of employees at the recruitment test for different posts under the Bank. It is contended that Shri Shah had also appeared at such a test in accordance with the said settlement but unfortunately he could not qualify himself and therefore his services had to be terminated as he could not be continued in service. He had appeared at that qualifying test on 25-11-74. When Dr. Anand Prakash the learned counsel appearing on behalf of the Bank was putting forth this plea based on the settlement ex. 55 before this Tribunal, a direct question was put to him and he was very fair enough to state that the said settlement was the settlement arrived at between the parties under the provisions of S. 2(p) of the Act. As such, the settlement, ex. 55 was none other but a settlement u/s 2(p) of the Act. If that is so, a further query was put to him, whether the conditions which required to be fulfilled in order to make that settlement effective were complied with ? He was quite fair and reasonable in stating that these conditions were not complied with. In this connection, reference is invited to sub-rule (4) of Rule 62 of the Industrial Disputes (Gujarat) Rules, 1966. Rule 62 refers to 'Memorandum of settlement'. Sub-rule (4) thereof is to the following effect :—

"(4) Where a settlement is arrived at between an employer and his workman otherwise than in the

course of conciliation proceedings before a Conciliation Officer or Board, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof to The Secretary to the Government of Gujarat, Education and Labour Department, Ahmedabad, the Commissioner of Labour, Ahmedabad, the Deputy Commissioner of Labour, Ahmedabad and the Conciliation Officer concerned."

22. In order that a settlement arrived at between the parties as contemplated u/s. 2(p) of the Act should be effective and legal, the conditions as laid down in sub-rule (4) of Rule 62 of the Rules have to be complied with. If they are not complied with it would not be a settlement u/s. 2(p) of the Act and consequently it will have absolutely no effect whatsoever. In the instant case, the conditions as laid down in sub-rule (4) of Rule 62 of the Rules were not complied with as the copies of this settlement, ex. 55 were not jointly sent by the parties to that settlement to the four authorities as laid down in that sub-rule (4) of Rule 62 of the Rules. If that is so, the said settlement would not be a legal settlement as contemplated u/s. 2(p) of the Act. If the said settlement was not a legal and enforceable settlement, anything done in pursuance of the said settlement would also not be legal and proper. As such, if Shri Shah appeared at that recruitment test in pursuance of the said illegal and unenforceable settlement, and if he failed at that test, it would have absolutely no effect on his employment under the Bank. In view of this position, the Bank was not authorized to terminate the services of Shri Shah even on the ground that he had failed to qualify in the recruitment test which was held in pursuance of the said settlement, ex. 55, which has turned out to be an illegal and ineffective settlement. Even on this ground, the Bank was, therefore, not justified in terminating the services of Shri Shah.

23. As regards the confirmation of Shri Shah, it is admitted by the Bank itself through its written statement, ex. 4, that if Shri Shah had qualified himself at that qualifying test, he would have been confirmed and made permanent in the services of the Bank. It is thus admitted that but for his failure at the recruitment test, he would have been entitled to be confirmed in the services of the Bank. Now, it has been seen above that the holding of the recruitment test in pursuance of the said settlement was not a legal and, a proper action of the Bank the settlement being not a legal and enforceable one. If that is so, Shri Shah would be entitled to get confirmation or made permanent in accordance with the provisions of the Sastri Award, the Desai Award and the Bi-partrite agreements entered into between the management of the Bank and the Union. In fact, a clear admission is made by the Bank through its written statement that in the ordinary course, according to the rules and regulations of the Bank, Shri Shah would have been made permanent but because he failed at the qualifying test, he had to be removed from the services of the Bank and since he was to be removed from the services of the Bank, the question of his confirmation or making him permanent did not arise. This being the position, a direction will have to be given to the Bank to not only reinstate Shri Shah and to pay him his full back wages from the date on which his services were wrongly and illegally terminated, i.e. from 15-7-74. but a direction will have also to be given that in accordance with the provisions of those awards and agreements, he should also be made permanent from the date from which he would have been made permanent but for his failure at the recruitment test. This would dispose of the case of Shri Shah.

24. I will now discuss the case of Shri Parikh covered by the Second Reference. Admittedly Shri Parikh was first appointed as a temporary godown keeper with effect from 10-7-67, vide the order ex. 12/1. In his case also it will be necessary to give in the tabular form the different dates on which he was appointed and again the dates on which his services were terminated :—

Dates of appointment	Dates of termination
10-7-67	8-2-68
17-5-68	9-11-68
26-12-68	18-7-69
17-11-69	31-3-70
7-4-70	29-10-70
27-11-70	7-6-71
14-6-71	12-10-71
23-11-71	17-1-72
21-1-72	5-7-72
10-7-72	31-5-73
1-6-73	14-8-73

25. In his case, a specific reference has been made as to whether his last termination, i.e. his termination of 14-8-73 was a legal and proper one. His last termination was on 14-8-73 and if we count a year immediately prior to that then it will start from 14-8-72. The above mentioned figures would show that his last but one appointment was on 10-7-72. Now, if we count the actual days on which he worked during 14-8-72 and 14-8-73, it would appear that he had worked for more than 240 days. The total no. of days on which he worked during that period of 12 months comes to 364 days. This would show that in fact practically he had put in a continuous service of not less than one year during that period. In fact his case would be covered by Subsection (1) of Section 25B of the Act because right from 14-8-72 to 13-8-73 his service was continuous. Even though his services were terminated on 31-5-73, yet, he was re-employed from 1-6-73. In any case, if his case would not fall u/s. 25B(1) of the Act because of break of one day in his service, then too, his case would be clearly covered by S. 25B(2) of the Act. He had therefore put in continuous service of not less than one year on 14-8-73 when his services were terminated. For the same reasons which I have already mentioned above while discussing the case of Shri Shah, even in the case of Shri Parikh, it can be legitimately held that the termination of his service with effect from 14-8-73 amounted to retrenchment. If that is so, the conditions precedent to be followed before effecting such retrenchment as envisaged u/s. 25F of the Act should have been complied with in his case also. Admittedly these conditions were not complied with and, therefore, the termination of his service with effect from 14-8-73 which amounted to his retrenchment from service was also not legal and proper. It may be pointed out in his case that his first appointment was through the letter ex. 12/1 dated 10-7-67. It would show that he was appointed on a purely temporary basis for the account of m/s. Gandhi Girdharlal Mansukhbhai & other accounts. It is thus clear that like Shri Shah, he was also appointed to keep watch over the godown where the goods of one of the customers of the Bank were pledged. The same arguments regarding he having become a spare hand or a surplus employee, as were given in the case of Shri Shah would also apply to him. In his case also the Bank has urged that even he had accepted the terms of the settlement, ex. 55, and in pursuance of this settlement he had also appeared at the recruitment test but had failed to qualify for the same. I have already discussed above, while referring to the case of Shri Shah that the said agreement was not a valid and legal agreement and, therefore, any steps taken by the Bank in pursuance of that agreement would not effect the service conditions of these two workmen. Merely because he could not qualify at the qualifying test which was held in pursuance of that illegal and ineffective settlement, it would not be a valid ground for terminating the services of this workman Shri Parikh. As regards the different decisions cited by the learned counsel appearing on behalf of the Bank, I have already discussed them while dealing with the case of Shri Shah and the same arguments would also apply to the case of Shri Parikh. From this entire discussion, it will appear that even the termination of service of Shri Parikh with effect from 14-8-73, was bad in law and therefore he would be entitled to reinstatement in his original position with the payment of his full back wages. At this stage, it may be clarified that the burden was upon the employer, viz., the Bank to show that during their unemployment under the Bank, these two workmen were gainfully employed elsewhere from where they had earned some money. The workman Shri Shah has been examined and his evidence is at ex. 13. During his cross examination no question was put to him as to whether he had been gainfully employed elsewhere after his services were terminated from the Bank. On the contrary through their written statement, the Bank has taken a stand that if these workmen have not been able to secure any alternative employment after their services were terminated from the Bank, the Bank would not be responsible for the same, which indirectly suggests

that the Bank agrees with the contention or the stand taken by these workmen that after their services were terminated from the Bank, they have not been able to secure any alternative employment elsewhere. Since there is no material on the record of these references that during the period of their unemployment, these workmen were gainfully employed elsewhere, it will not be possible to adjust any such amount against the past wages which may be found due and payable to these two workmen.

FIRST REFERENCE

SHRI B. C. SHAH

26. (i) It is hereby declared that the action of the Bank in terminating the services of Shri B. C. Shah with effect from 15-7-74 amounted to retrenchment and since the said retrenchment was not effected in accordance with law, the said action was absolutely illegal and unenforceable at law. As such, it is declared that Shri B. C. Shah continued to be in the service of the Bank as a temporary godown keeper.

(ii) It is, therefore, hereby directed that Shri B. C. Shah be reinstated in his original position as a temporary godown keeper under the Bank retrospectively with effect from 15-7-74.

(iii) It is further directed that Shri Shah should be paid his full back wages with effect from 15-7-74 including all allowances, etc. till he is actually reinstated in his original position by the Bank.

(iv) It is also directed that the Bank to confirm Shri Shah or to make him permanent in accordance with the prevalent rules and regulations or the directions given in different awards including the Sastri Award, the Desai Award and the Bi-partrite agreement, which action the Bank could not take as contended by them because of the fact that Shri Shah could not qualify at the recruitment test at which he had appeared but failed to qualify on 25-11-74. The holding of that test has been held to be illegal and, therefore, that fact could not come in the way of Shri Shah in making him permanent in accordance with the provisions of the above mentioned awards and agreements.

(v) The arrears of wages, etc. found payable to Shri Shah in accordance with the abovementioned directions shall be paid to him within a period of one month from the publication of this award in the Gazette of India.

SECOND REFERENCE

SHRI R. P. PARIKH

(vi) It is hereby declared that the termination of the services of Shri R. P. Parikh with effect from 14-8-73 was illegal and unenforceable at law. It is further declared that Shri Parikh continues to be in the service of the Bank as his retrenchment from service was not in accordance with law.

(vii) It is, therefore, hereby directed that Shri Parikh be reinstated in his original position as a temporary godown keeper under the Bank retrospectively with effect from 14-8-73.

(viii) It is further directed that Shri Parikh should be paid his full back wages including all allowances, etc. which he was drawing on the date of the termination of his service, i.e. with effect from 14-8-73 till he is actually reinstated in that position by the Bank.

(ix) The said arrears of wages becoming payable to Shri Parikh as directed above, shall be paid to him within one month from the date of publication of this award in the Gazette of India.

(x) The first party-Bank, in both the references to bear its own costs and also to pay the costs of the Union in the two references which are quantified at Rs. 1,000.

Ahmedabad

Dated :— 3rd May, 1979.

R. C. ISRANT, Presiding Officer.

[No. L-12012|20|75-D.II.A & L-12012|25|75-D.II(A)]

New Delhi, the 30th May, 1979

S.O. 1969.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Grindlays Bank Ltd. New Delhi and their workman over not allowing Shri Prem Chand Gupta, typist-cum-clerk to work as Telex Operator with effect from the 8th August, 1974, which was received by the Central Government on the 26-5-79.

BEFORE SHRI RAMESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I. D. No. 97 of 1977

In re :

General Secretary, National and Grindlays Employees Union, c/o Grindlays Bank Ltd., H-Block, Connaught Circus, New Delhi.

AND

The General Manager, Northern India, Grindlays Bank Ltd., H-Block, Connaught Circus, New Delhi.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. made a reference u/s 10 of the I. D. Act in respect of an Industrial Dispute between the workmen of Grindlays Bank Ltd., New Delhi and the Grindlays Bank Ltd., New Delhi to Industrial Tribunal, Delhi vide its order No. L-12012/145/75/DII/A dated the 20th September, 1975 as follows :

> Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited, New Delhi in not allowing Shri Prem Chand Gupta, typist-cum-clerk, to work as Telex Operator with effect from the 8th August, 1974 and in denying special allowance admissible to him is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The said reference was registered by Industrial Tribunal, Delhi and notices were issued to the parties for 30th October, 1975 whereupon statement of claim was filed by the workman. A written statement was also filed on behalf of the Management and finally a rejoinder was filed by the workman. Upon the pleadings of the parties following issues were framed :

1. Whether the cause has been properly and validly espoused ?
2. Whether the reference bad for the reason pleaded in para 2 of the preliminary objection in the written statement ?
3. As in the term of reference.

3. Thereafter one witness Shri Rajinder Syal was examined as W.W. 1 and the evidence of the workman was closed. In the meanwhile this case was transferred to this Tribunal by the appropriate Govt. and was accordingly registered and thereafter evidence of the Management was recorded. Finally the evidence of workman in rebuttal also was recorded. Thereafter an additional issue was framed vide my order dated the 30th March, 1978 in the following terms :

> "Whether this Tribunal has no jurisdiction in view of the allegations in the application dated 4-3-78."

4. Arguments were heard. After going through the pleadings of the parties and the evidence led by the parties and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the following findings :

5. As would be clear from the statement of claim filed on behalf of the workman it is urged on behalf of the workman union that Shri P. C. Gupta, workman joined the service of the Bank on 22-2-1962; that the Management installed a telex in Parliament Street Branch of the Bank, New Delhi on 24-3-1963 and Shri P. C. Gupta was appointed to operate the said machine; that initially no special allowance

was paid for performing the duties of telex machine operator which required special skill and higher responsibility over and above the normal and routine duties of a clerk and it was on representation of the workman that a sum of Rs. 20 was started to be paid as a special allowance w.e.f. June, 1963; that thereafter Shri P. C. Gupta was transferred to the Limits Department vide office notice No. 7 dated 8-8-74 and vide office letter dated 8-8-74 the workman was informed that as he was no longer required to perform the duties of a telex machine operator w.e.f. 9-8-74 the payment of special allowance would ceased from that date; that the workman protested against the said action of the Management it being against the conditions of his service and unjust, vindictive and illegal; that later on the union took up the matter with the Management but no amicable settlement could be arrived at; that the action of the Management was a colourable exercise of authority and was violation of Sec. 9-A of the I.D. Act; that finally this reference was made; that the action of the Management in the instant case is an unfair labour practice and colourable exercise of powers and is wrong, unjustified, arbitrary and in-operative.

6. The Management has contested these allegations of the workman inter alia on the ground that the matter has not been properly espoused by the Union and as such is not an Industrial Dispute; that the issue of special allowance has been settled vide Bipartite Settlement dated 19-10-1966 and no dispute can be raised regarding the implementation by that settlement or the points covered by that settlement during the operation of said settlement. On merits it is contended that although Mr. P. C. Gupta had been asked to operate the telex machine is substantive post remained that of clerk-cum-typist and he was liable to be transferred to any other Branch or section and hence the order of the Management was a valid order. Other allegations of the workman have been denied. It is also contended that the Management has a right to transfer a workman inter alia from one Department to another and it did not involve any violation of Section 9-A of the I.D. Act and it is contended that the workman is not entitled to any relief.

7. Issue No. 1 :

In order to prove this issue the workman have examined Shri Rajinder Syal who is the General Secretary of the National and Grindlays Bank Employees' since 1951. According to his statement as W.W. 1 about 900 employee of the Management are workman, about 780 are the members of this Union and workman here in this matter is also a member since 1962. This witness has categorically stated that the Union took a decision to espouse this case and this decision is Ex. W/1. From the perusal of Ex. W/1 I find that it is the extract of the proceedings of Executive Committee meeting held on 10th August, 1974. From the persual of this document I find that certainly the workmen—union had espoused the matter in dispute in accordance with the requirement of law. Nothing has been brought out in the cross examination of this witness to bely his statement in chief. The workmens—union is a registered union. It is stated by him that notice with immediate effect was given about meeting in which Ex. W/1 was passed on telephone and not in writing. Mere fact that the attendance of the meeting held on 10-8-74 was taken up separately on a piece of paper and pasted would not bely his statement or the fact that such a meeting was in fact held. It has been categorically stated by this witness during cross examination that it was incorrect to suggest that no notice of the meeting for 10-8-74 was given. There is no rebuttal of the statement of this witness. It would not be open to challenge the correctness of the statement of this witness supported as it is by Ex. W/1. It is not suggested during cross examination to W.W.1 that in fact no meeting was held or that Shri P. C. Gupta was not a member of the union or that this union was not a representative union. In view thereof this issue is decided in favour of the workman and against the Management.

8. Issue No. 2 :

In para No. 2 of the preliminary objection of the written statement it has been urged by the Management that the issue of special allowance was settled by the Bipartite settlement dated 19-10-1966 inter alia between the Indian Banks. Association and All India Bank Employees' Association and so long as the settlement is in operation no dispute can arise regarding the implementation of the settlement or the points covered by the settlement and therefore the reference is bad in law. It is not denied that a settlement exists between the Indian Banks Association and All India Bank Employees Association on the question of special allowance. However mere existence of settlement cannot invalidate the reference in this case because the reference does no go contrat to the said settlement. The settlement is of a general nature and goes to lay down in chapter 5 thereof various special allowances available to different categories for different work. The claim in the instant case is not in violation of the said settlement rather it has been canceded before me that this claim is in pursuance of that settlement for the operation of a telex machine to a telex operator. As to whether the workman in the instant case is entitled to the special allowance of Rs. 20 referred to in item No. 5 of para 5.2 of chapter 5 of the said settlement is a question of fact. It does not invalidate the reference in any manner and I hold accordingly.

9. Additional Issue :

In the application dated 4-3-78 the Management has challenged the transfer of this from the Industrial Tribunal Delhi to this Tribunal. However subsequent to this application a fresh order of transfer has been passed by the appropriate Govt. and in consequence thereof the parties representatives namely Shri R. C. Pathak, Rajinder Syal, P. C. Gupta for the union and Shri S. S. Sethi for the Bank stated in their statements recorded on 20-7-72 on this file that the parties do not want to re-open the proceedings and it is therefore requested that the proceedings recorded in this case by this Tribunal in view of the above statement and in view of the fact that a fresh order of transfer has been passed by the appropriate Govt. this issue does not servive and as such is decided against the Management and in favour of the workman.

10. Issue No. 3 :

This issue is as referred in the order of reference reproduced above. The facts so far as they relate to the appointment and of Shri P. C. Gupta as typist-cum-clerk in the Grindlays Bank and directions by the Bank to Shri P. C. Gupta to work as Telex Operator uptil 2-8-74 are not denied. The contention of the workman is that the order of transfer is in colourable exercise of administrative powers and was illegal, in-operative, unfair labour practice etc.

11. I would like to take it clear at the very outset that there are three categories of employees in the banking industry; the officers with which we are not concerned under the I.D. Act, the remaining two categories are that of clerks-cum-cashiers and the subordinate staff. We are not concerned with the subordinate staff either. The matter is limited to the clerk-cum-cashier. All workmen other than subordinate staff are clerks-cum-typist though at different time different jobs may be assigned to them. In the instant case it is admitted by Shri P. C. Gupta that he was appointed as clerk-cum-cashier and whom telex machine was installed on 24-6-63 he was required to operate the said machine and that he was paid Rs. 20 as special allowance for operating the said machine from the operation of such machine. The Id counsel for the workman has not been able to draw my attention to any special agreement whereby Shri P. C Gupta was appointed

as telex machine operator in contra distinction to his appointment as clerk-cum-typist. It was in his capacity as a clerk-cum-cashier that he was required to operate the telex machine for which he was paid a special allowance of Rs. 20. The said allowance was withheld from the date he was transferred to the limits Department i.e. w.e.f.8-8-74. In the face of these facts it would be difficult to accept the contention of the workman that he had earned a right to work as a telex machine operator for all time to come. If the contention of the workman was accepted the result would be that Shri P. C. Gupta would be deemed to have been appointed as a telex machine operator for all times to come which would not be correct to pay. In so far as this case involved a routine transfer of one person from one duty to another or from one Department to another it would be difficult to accept that it involved any violation of Section 9-A or that it involved change of conditions of service. In the very nature of discharge of its administrative functions the Management is called upon every now and then to effect transfers and postings and if in the exercise of these powers Shri P. C. Gupta happens to be transferred to another branch it cannot be said that it involved violation of Sec. 9-A of the I.D. Act. By as stretch of imagination it can be said that Shri P. C. Gupta had stguished any right to had the post of telex machine operator permanently. I have persued the entire agreement dated 19-10-66 between the Indian banks Association and the All India Bank Employees' Association but I do not find that any such conclusion can be arrived at from the reading of the said agreement in the circumstances of the present case. If such a narrow interpretation would be given it would bring the entire administration of the Bank to a stand still. It is neither the intention nor the purpose of the agreement dated 19-10-66 to curtail the powers of the Management to transfer the workman from one post to another or from one Department to another. A perusal of Ex. W/5 the order of transfer of Shri P. C. Gupta does not make of any malafide or victimisation or unfair labour practice. Even from the perusal of para 5.9 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 it cannot be said that a new category of telex machine operator has been created apart from clerk-cum-cashiers in the Bank and therefore Section 9-A is not attracted. It has not been urged before me on behalf of the workman that there was any distinct category of post as telex machine operators and in the absence thereof it cannot be said that the transfer of Shri P. C. Gupta in the instant case involve or was violative of Section 9-A or was an unfair labour practice or was illegal. Incidently it would be appropriate to refer to document Ex. W/3 which is copy of letter dated 6-7-65 from Sub-Ex. W/3 which is copy of letter dated 6-7-65 from Sub Manager of the Bank to General Secretary of the Union whereby it was clearly given to understand to the union that future appointment of operators was left to the discretion of the Management. Even Ex. W.W.2/1 does not show that Shri P. C. Gupta had been sanctioned special allowance of Rs. 20 for all time to come or that he had been appointed telex machine operator for all time to come rather that ad-hoc arrangement was subject to any agreement which might be eventually arrived at between the parties. Ex. W.W.2/2 is the order dated 1-1-1966. this also does not improve upon the ultration or further the claim of the workman. Letter Ex. W/5 dated 6-8-74 from Shri A. S. Mukherjee, Operation Manager of the Bank to Shri P. C Gupta also speaks that in view of transfer of Shri P. C. Gupta to Limits Department he was no longer required to perform the duties of a telex operator w.e.f. 9-8-74 and hence the special allowance paid to him will cease from that date. Even this order does not show any malafide involved in it. I have persued the statement of Shri P. C. Gupta as W.W.2. Even in his statement it is stated by him that he was required by the Bank to operate the telex machine and on his representation he was paid Rs. 20 P.M. special allowance as telex machine operator. He has stated that the cause of his transfer in fact was his trade union activities and the guise was merely a transfer but in fact it was to deprive him of special allowance but there is no evidence accept this statement to establish the allegation of the workman. During cross examination it is admitted by him that he continues to be typist-cum-clerk in the Bank. He admits the correctness of Ex. W.W.2/1. It is admitted by him that transfer is a normal feature in the Bank. He also admits that Shri Sheel Kumar was his successor as telex operator and also was a member of the union and prior thereto he was relief operator. When his statement is read in the light of statement of Shri R. S. Chopra, M.W.1 no doubt is left that this transfer was a routine transfer and involves no malafide and in consequence after giving due consideration to the entire matter before me I have come to the conclusion that the order of the Management in transferring Shri P. C. Gupta, typist-cum-clerk to Limits Department w.e.f. 8-8-74 was in exercise of administrative functions of the Bank and no malafide, illegality or unfair labour practice was involved. In consequence it is awarded that the action of the Management of Grindlays Bank Limited, New Delhi in not allowing Shri P. C. Gupta, typist-cum-clerk to work as telex operator w.e.f. 8-8-74 and in denying special allowance admissible to him is justified and that the workman is not entitled to any relief what-so-ever in this reference.

12. For my discussions and findings upon issues above, it is awarded that the action of the Management of the Grindlays Bank Ltd., New Delhi in not allowing Shri P. C. Gupta typist-cum-clerk to work as telex operator w.e.f 8-8-74 and in consequence denying special allowance admissible to him is justified and the workman is not entitled to any relief what-so-ever. Parties however are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 21st May, 1979.

[No. L-12012/145/75-D.II.A]

S. K. MUKERJEE, Under Secy.

S.O. 1970.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhanakhap Mica Mining Company and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 5 of 1977

Employers in relation to the management of Bhanakhap Mica Mine, Post Office Singer, Dist. Nawadah of M/s. Bhanakhap Mica Mining Company.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers—Shri S. N. Jha, Agent.

On behalf of the Workmen—Shri B. Singh, General Secretary, Abrakh Mazdoor Panchayat.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Mica.

Dated, Dhanbad, the 10th May, 1979

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bhanakhap Mica Mine P.O. Singer, District Nawadah of M/s. Bhanakhap Mica Mining Co. and their workmen by their Order No. L-28011/1/77-D. IIIB, dated the 25th October, 1977 referred the same to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication on the issue as in the schedule below :—

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Bhanakhap Mica Mine, Post Office Singer, District Nawadah of M/s. Bhanakhap Mica Mining Company for payment of

bonus @ 20 per cent for the accounting year ending on 31st December, 1974 is justfied ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

2. Parties were informed to file their written statements and on 5-2-1979 written statement was filed on behalf of the workmen while the employers requested for time for filing written statement on the next date. Ultimately on 5-4-1979 both parties appeared and filed a joint petition of compromise settling their industrial dispute. I heard the parties on the joint petition of compromise and it is submitted by them that an award be passed in terms of the statement. It appears that the joint petition of compromise has been duly signed by the General Secretary, Abrakh Mazdoor Panchayat, Jhumritelaiya, Hazaribagh from the side of the workmen and by Agent, Bhanakhap Mica Mining Company, Jhumeritelaiya, Hazaribagh from the side of the management. The terms of settlement appears to be beneficial to the parties and nothing stands in the way of an award being passed thereon.

In the result I pass an award in respect of the industrial dispute referred to on terms as embodied in the joint petition of compromise (settlement) which do form part of the Award as Annexure A.

J. P. SINGH, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 2, DHANBAD

CAMP—PATNA

Ref. No. 5 of 1977

Employers in relation to the management of M/s. Bhanakhap Mica Mining Co., Jhumritelaiya, Hazaribagh.

VERSUS

Their workmen represented through Abrakh Mazdoor Panchayat, Jhumritelaiya.

The humble joint petition on behalf of both the parties aforesaid.

Most respectfully sheweth :

1. That the Government of India had been pleased to refer the dispute for adjudication on the following terms :

"Whether the demand of the workmen of Bhanakhap Mica Mine, P.O. Singer, Distt. Nawadah of M/s. Bhanakhap Mica Mining Company for payment of bonus @ 20 per cent for the accounting year ending on 31-12-74, is justified. If so to what relief are the workmen entitled ?"

2. That this Hon'ble Tribunal had been pleased to issue notice for filing written statements of the parties.

3. That the parties have already entered into a mutual settlement on 3-4-79 and according to terms of the settlement, the copies of the said settlement is annexed herewith, which forms Annexure to this Joint petition.

4. That with this humble joint petition, it is prayed that the said settlement may please be accepted and the Award may please be announced in terms of the said settlement.

This therefore, prayed that this Hon'ble court would be graciously pleased to accept the settlement and would be further pleased to give its award in terms of the settlement.

And for this, both the parties shall ever pray.

S. N. Jha,
Agent,
Bhanakhap Mica Mining Company.

BHUBANESHWAR SINGH,
General Secretary,
Abrakh Mazdoor Panchayat
Jhumritelaiya

Dated : Patna,
The 5th April, 1979.

Memorandum of mutual settlement arrived at between the management of Bhanakhap Mica Mining Company, Jhumritelaiya and their workmen represented throgh Abrakh Mazdoor Panchayat, Jhumritelaiya on 3-4-1979.

PRESENT :

Representative of the Management
S. N. Jha, Agent of Bhanakhap Mica Mining Company.

Representative of the Workmen
Bhubaneshwar Singh, General Secretary, Abrakh Mazdoor Panchayat.

Short recital of the case

The General Secretary, Abrakh Mazdoor Panchayat raised an industrial dispute for more bonus to the extent of 20 per cent minus the percentage of bonus already paid for the accounting year 1974. On the other side the management contention was that the management has incurred loss in the said accounting year and besides this, there was no dispute raised with the management. Despite several attempts were made at the end of the Assistant Labour Commissioner (Central), Hazaribagh for an amicable settlement but no outcome could be achieved. On submission of failure report by the Assistant Labour Comissioner, Hazaribagh the Govt. of India had been pleased to refer the matter for adjudication to the Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad.

On receipt of the notices from the Industrial Tribunal, Dhanbad, the management started negotiation over the matter. After protracted discussions on several reasion the matter has been ceased on the following terms :—

Terms of Settlement

1. It is agreed by both the parties that the workmen have already been paid bonus 4 per cent for the accounting year 1974.

2. It is agreed by the management that the workmen will be paid 4.33 per cent as bonus for the said accounting year in addition to the percentage already paid.

3. It is agreed by both the parties that the amount of bonus will be paid to the workmen within thirty days from the date of settlement.

4. It is agreed that the copy of this settlement be filed before the Hon'ble Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad before whom the dispute is pending for adjudication.

Representing the Management.

S. N. Jha,
Agent
Bhanakhap Mica Mining Co., Jhumritelaiya

Representing the Workmen

Bhubaneshwar Singh,
General Secretary
Abrakh Mazdoor Panchayat,
Jhumritelaiya.

[No. L-28011/1/77-D. III. B]

New Delhi, the 1st June, 1979.

S.O. 1971.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bailadila Iron Ore Deposit 11C/13 and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th May, 1979.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, B.Sc., LL.M., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case Ref. No. CGIT/LC (R) (35)/1978

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bailadila Iron Ore Investigation Deposit 11C/13 and their workmen represented through the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Bailadila 11C Branch, P. O. Kirandul, Distt. Bastar (M.P.)

APPEARANCES :

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Union—Shri L. N. Malhotra, Advocate.

INDUSTRY : Iron Ore Mine. DISTRICT : Bhastar (M.P.)

AWARD

Jabalpur, the 24th April, 1979

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-26011/4/77-D. III(B) dated 22nd July, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :

> "Whether the action of the management of Bailadila Iron Ore Investigation Unit 11C/13 in not extending the N.M.D.C. service Regulation to S/Shri R. B. Singh, K. B. Pillai and V. K. Kutti, Lower Division Clerks working at Feasibility 11C/13 is justified ? If not, to what relief the said workmen are entitled and from what date ?"

2. It is not disputed that 11C/13 is an investigation branch of N.M.D.C. working at Bailadilla. The workers named in the reference viz. S/Shri R. B. Singh, K. B. Pillaj and V. K. Kutti, who were initially recruited in that investigation branch and came to be regularised in the ministerial cadre as Lower Division Clerks in that branch in course of time are governed by Model Standing Orders applicable to the investigation branch generally. On the other hand, Shri Chakravorty, Shri Prasad and others, who are also at present working in the investigation branch at 11C/13, belong to regular ministerial cadre of N.M.D.C. which is governed by the service regulations. They have brought their service conditions with them. There are no Certified Standing Orders governing the investigation branch. Thus at present there are two sets of persons in the ministerial branch, one set governed by Model Standing Orders and other set by the notified Service Regulations.

3. The case of the Union is that persons in the clerical cadre working at same place should not be governed by the two different set of rules as, in consequence those who are governed by the Model Standing Orders made to work for more number of hours and are deprived of many other benefits which are available to others who are governed by the Regulations of N.M.D.C.

4. The case of the management is that the demand raised by the Union, about exemption of all ministerial staff from Model Standing Orders, was meterially different from the reference that has been made by the Government of India. As such the reference is invalid in law and made mechanically without jurisdiction. There is no authority vested in the Tribunal to grant exemption from the applicability of Model Standing Orders to a set of workers. In this respect also the reference is bad. It is further alleged that draft for the certified Standing Orders has been presented to the Certifying Officer. His decision has been set aside by the Chief Labour Commissioner and the case has been remanded back to him for doing the needful in the matter of certifying the draft Standing Orders for the workers of investigation branch. The matter is pending there and this Tribunal has no jurisdiction to entertain the same dispute by way of reference.

5. It is true that the heading of the demand raised by the Union was 'the exemption of all ministerial staff from Model Standing Orders'. The demand in these words was reproduced in para 4 of the written satement filed by the management as demand no. 7. The union in it's rejoinder has not denied that the heading of the demand was as reproduced above. The workman has, however, filed the minutes of conciliation proceedings Ex. W/3 which clearly sets out the nature of the demand raised by the Union, the heading for which was not happily worded. The document mentions that :—

> "The union stated that there are three persons namely S/Shri R. B. Singh, K. G. Pillai, and V. K. Kutti L.D.Cs. who were appointed at 11C and subsequently regularised as ministerial cadre have been covered by Model Standing Orders whereas other ministarial cadre including one Shri M. Chakravorty Accounts Assistant and Shri N.R.C. Prasad Accounts Assistant are/were governed by N.M.D.C. Service Regulations. In N.M.D.C. the ministerial staff whenever and wherever posted are governed by N.M.D.C. Service Regulations only. Hence the action of the management in respect of three persons named above is highly discriminative and unjustified. They are not only deprived of the benefits of N.M.D.C. Service Regulations but also compelled to work for 8 hours a day while all other ministorial staff in 11C or elsewhere have to work only 6¼ hours a day. The union demands exemptions of the provisions of Model Standing Orders in case of these three workmen also as done in all other cases in the N.M.D.C."

The details of the stand so given, clearly indicate that the heading of the dispute is rather misleading. Thus the real dispute raised by the union is that instead of being governed by Model Standing Orders these three Lower Division Clerks should also be governed by Service Regulations which are applicable to others regular clerical staff of N.M.D.C. working for the present at the investigation branch. I am, therefore, inclined to hold that the reference is neither divorced from the nature of demand placed by the Union nor is so different in nature as may give rise to an inference that the dispute referred is materially different from the demand raised by the Union.

6. It is true that according to the Sec. 12A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 Model Standing Orders necessarily apply to an industry till Certified Standing Orders come into force. As there are no Certified Standing Orders for this branch upto this time there will be statutory application of the Model Standing Orders. The Act does not contemplate any authority, other than the Government under Sec. 14 of the Act which can exempt an industry from such statutory application of a Model Standing Orders. But in fact as said above the real nature of the demand raised was not for exemption from Model Standing Orders, but of extension of service Regulations to them, because once service Regulations are notified to be extended to a particular cadre in an industry. The Model Standing Orders will cease to apply by virtue of S. 13A of the Act.

7. Now it is the admitted position that some of the employees who are regular employees of N.M.D.C. and have come to the investigation branch on transfer are governed by the Regulations of N.M.D.C., while these Lower Division Clerks named in the reference are governed by the Model Standing Orders. This has created an anomalous situation in the sense that the persons working in the same department and performing the same nature of duties are being governed by two sets of rules. It appears to be very unreasonable that clerks coming from the regular office to work in the investigation branch should work only for 6¼ hours while the others who are directly recruited for the branch should be made to work for 8 hours. Similarly there can be no earthly justification that the clerks who are directly recruited for the branch should be deprived of certain privileges which are enjoyed by the clerks who are transferred to the branch from the N.M.D.C. regular office. The draft Standing Orders are pending for being certified and I am sure that in view of the observations of the Supreme Court made in Salem Erode Electricity Distribution Vs. Employees Union (5 SCLJ 2909) that the object of Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 is that the employees similarly situated should not be governed by two sets of Standing Orders, the certification officer shall see that this anomaly and discrimination are removed.

8. It is argued that this Tribunal has no jurisdiction and the remedy lies under the Industrial Employment (Standing Orders) Act because that contains a self contained Code. U.P. Electricity Board Vs. Hari Shanker (AIR 1979 SC

1965) is distinguishable from the facts of the present case. It does not say that the tribunal has no jurisdiction to entertain or decide a dispute to which Industrial Employment (Standing Orders) Act applies. On the other hand, in Guest Keen Williams(P) Ltd. Vs. P. J. Sterling (4 SCLJ 2837) the Supreme Court made it very clear that the reference to the Tribunal would not be incompetent even when the Standing Orders certified under the Act became part of the terms of the employment by the operation of Section 7 of the Act. Moreover in the present case the nature of the dispute is not covered by the Industrial Employment (Standing Orders) Act. The dispute is about the removal of the discripancy in service conditions relating to two sets of employees working in the same section, one being governed by the Regulations of N.M.D.C. and the other by the Model Standing Orders. There is no provision in Industrial Employment (Standing Orders) Act which empowers any authority to entertain or decide such a dispute. Jurisdiction of this Tribunal is therefore not barred even impliedly by any of the provisions of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

9. It is, therefore, held that the two sets of the service conditions prevailing amongsts the Clerical staff working in the Balladila Iron Ore Investigation Unit 11C/13 is not justified and shall be removed by the management either by extending the N.M.D.C. Service Regulations to the clerical staff working at the unit or if that is not possible then by seeking such modification in the draft standing orders pending for certification before the appropriate authority so that the service conditions prescribed therein for the Lower Division Clerks are in all respects equated with the service conditions of the other clerks working in that unit, to whom N.M.D.C. Regulations are applicable.

10. Reference is answered accordingly.

24.4.1979.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

[No. L-26011/4/77-D. III. B]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979